सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

12 जुलाई, 2019

षोडश विधान सभा 12 जुलाई, 2019 ई0

------------ शुक्रवार, तिथि --------------

त्रयोदश सत्र 21 आषाढ़,1941(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होती है ।

(व्यवधान)

इसको शून्यकाल में उठाइयेगा ।

प्रश्नोत्तर-काल

तारांकित प्रश्न सं0-991(श्री केदार प्रसाद गुप्ता)

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 की धारा-4(क) में निहित प्रावधानानुसार सरकार के सभी विभागो के स्तर पर शिकायत निवारण समिति का गठन किया जा चुका है । बिहार राज्य मुकदमा नीति,2011 की धारा-4(क)(4) में निहित प्रावधानानुसार जिला एवं अनुमंडल स्तर पर शिकायत निवारण समिति गठन करने का निदेश विभागीय पत्रांक 3679, दिनां 10.06.2015 द्वारा सभी जिलाधिकारियों को दिया गया है । इस संदर्भ में सभी जिलाधिकारियों से प्रतिवेदन की मांग की गयी है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष : आप सीनियर मेम्बर हैं, आप इस तरह से कीजियेगा, आप क्या प्लेकार्ड दिखा रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आखिर कबतक समिति का गठन हो जायेगा ?

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री : महोदय, जो 13वीं वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जो लिटिगेशन पॉलिसी बनी थी, उसी के तहत यह निर्णय लिया गया था कि राज्य स्तर पर, विभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जो कर्मी हैं, उनकी जो समस्या है, उनकी शिकायत को सुनने के लिए एक कमिटी बनायी जाय । महोदय, 11

जिलों में कमिटी का गठन हो गया है । सचिवालय स्तर पर प्रत्येक विभाग में कमिटी का गठन हो गया है और इम्पार्वड कमिटी का भी गठन स्टेट लेवल पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हो गयी है । हमने कल ही पुनः पत्रांक 4801 दिनांक 11.7.19 के द्वारा भेजा है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप माननीय सदस्य को बता दीजिए कि शीघ्र करने जा रही है।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री : महोदय, शीघ्र सरकार करने जा रही है ।

तारांकित प्रश्न सं0-992(श्रीमती भागीरथी देवी)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-993(सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-994(श्री मुजाहिद आलम)

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

जिला पदाधिकारी, किशनगंज के प्रतिवेदनानुसार अनुग्रह अनुदान अभिलेख संख्या-मृतक कुन्दन कुमार के आश्रित, पिता श्री शिव लाल यादव साकिन बस्ताकोला, थाना-कोचाधामन, जिला-किशनगंज को अनुग्रह अनुदान की निर्धारित राशि चार लाख रूपये का भुगतान हेतु दिनांक 10.07.19 को स्वीकृति प्रदान की गयी है । अतः अनुग्रह अनुदान की राशि भुगतान करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

श्री मुजाहिद आलम : महोदय, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जितना भी अनुग्रह अनुदान राशि का मामला है, वह दो साल, तीन साल तक पेंडिंग रहता है, गरीब आदमी हर ऑफिस दौड़-दौड़कर परेशान होता है । एक समय-सीमा होनी चाहिए, जब दो साल पर यह स्वीकृत हुआ और भी कई ऐसे मामले हैं जो तीन-तीन साल तक सामूहिक दुर्घटना के बाद भी उनको अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान नही दिया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं, अगर सरकार सामूहिक दुर्घटना में अनुग्रह राशि देती है तो उसमें विलम्ब अधिक नहीं होना चाहिए, इससे असंतोष होता है ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री : जी अच्छा ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-995(श्री रवीन्द्र सिंह)</u>

श्री रवीन्द्र सिंह : महोदय, जब स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा की मांग किये हैं....

अध्यक्ष : आप प्रश्न नहीं पूछियेगा ?

श्री रवीन्द्र सिंह : जी नहीं ।

अध्यक्ष : ठीक है, नहीं पूछा गया ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-996(श्री भोला यादव)</u>

श्री भोला यादव: महोदय, जो मेरा प्रश्न है, उसका उत्तर यदि स्वास्थ्य मंत्री बोलेंगे तो हम उनका बहिष्कार करते हैं ।

अध्यक्ष : नहीं पूछेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-997(श्री शम्भू नाथ यादव)</u>

(अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न सं0-998(श्री फैजल रहमान)</u>

अध्यक्ष : नहीं पूछ रहे हैं ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-999(श्री आलोक कुमार मेहता)</u>

अध्यक्ष : नहीं पूछ रहे हैं ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1000(श्री चन्द्रशेखर)</u>

अध्यक्ष : नहीं पूछ रहे हैं ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1001(श्रीमती एज्या यादव)</u>

अध्यक्ष : नहीं पूछ रहे हैं ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1002(श्री ललन पासवान)</u>

अध्यक्ष : आपका उत्तर दिया हुआ है ललन जी ।

(व्यवधान)

इस्तीफा मांगना आपका हक है । आप मांग रहे हैं तो उसमें आसन को क्या एतराज है । वह मांगना आपका हक है, मांग सकते हैं, आप किसी से कुछ भी मांग सकते हैं। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि रोहतास एवं कैमूर की पहाड़ी पर अवस्थित प्रश्नवर्णित गांवों एवं अधिकांश भूभाग संरक्षित वन क्षेत्र है । जहां किसी तरह की संरचना का निर्माण वन विभाग की स्वीकृति...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नितीन नवीन जी, बैठ जाइए ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : प्राप्ति के पश्चात् उनके द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही की जा सकती है । उक्त क्षेत्र में अवस्थित गांव एवं टोले की विद्युतीकरण का प्रस्ताव वन विभाग के स्तर पर लंबित रहने के कारण संबंधित क्षेत्र का विद्युतीकरण डिसेन्ट्रलाईज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड जेनरेशन (डी0डी0जी0) के माध्यम से सौर उर्जा चालित मिनी ग्रिड पावर प्लांट एवं स्टेंड अलोन सिस्टम लगाते हुए किया जा चुका है ।

श्री ललन पासवान : महोदय, माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनके कमिश्नर को बधाई देते हैं कि आजादी के 70 वर्षों के बाद सोलर से बिजली वहां दी जा रही है । एक रूपये बी0पी0एल0 और दो रूपये ए0पी0एल0, लेकिन महोदय, वन विभाग में लंबित है, सरकार ने पहल की है, मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही जानना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां गये थे और आश्वस्त किये थे, घोषणा करके आये थे कि स्थायी बिजली देंगे और सरकार उस दिशा में पहल कर रही है। हम माननीय मंत्री जी से इतना ही जानना चाहते हैं कि समय-सीमा निर्धारित करके वन विभाग से जो प्रोसेस चल रहा है, उसको कराकर स्थायी वनवासी, आदिवासियों का कैमूर एवं रोहतास के पहाड़ पर बिजली देने का कृपया कबतक करेंगे ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वन विभाग से बातचीत करके जल्द मामले का निपटारा किया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-1003(श्री अब्दुस सुबहान)

अध्यक्ष : नहीं पूछेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-1004(श्री विनोद प्रसाद यादव)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- स्वीकारात्मक है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि चिलमी ग्राम में स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्वीकृत है, परन्तु भूमि के अभाव में भवन निर्माण नहीं कराया जा सका है । भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त विहित प्रक्रियानुसार स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन निर्माण कराया जायेगा ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, वहां पर भूमि की उपलब्धता है और कई ऐसे जगह हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे जगह हैं, जहां से जमीन की उपलब्धता के संबंध में सूचना भेज दी गयी है, बावजूद निर्माण नहीं हो रहा है तो क्या माननीय मंत्री महोदय विभागस्तर पर उसकी समीक्षा करके प्रतिवेदन मंगाकर कार्रवाई करना चाहते हैं ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, विभागीय स्तर पर समीक्षा करके उसका प्रतिवेदन मंगाकर मैं कार्रवाई करूंगा और आपके उस अस्पताल को बनवाने में साकारात्मक प्रयास करूंगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-1005(श्री आनन्द शंकर प्रसाद)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है ।

पटना जिलान्तर्गत फुलवारीशरीफ प्रखंड के न्यू एतवारपुर मोहल्ला के गांधी कॉपरेटिव पथ में 33000 वोल्ट का अकार्यशील विद्युत तार को Reconductoring scheme के तहत बदलकर जनहित के लिए विद्युत आपूर्ति की जानी है । इसका लक्ष्य नवम्वर,2019 है ।

टर्न-2/राजेश/12.7.19

तारांकित प्रश्न संख्या-1006 (श्री शिवचन्द्र राम)

श्री लक्ष्मेश्वर राय मंत्री: महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । जिला पदाधिकारी वैशाली के प्रतिवेदन अनुसार स्व0 गरीबन कुमार, पिता: मुनिलाल चौधरी एवं स्व0 राजकुमार, पिता राजेश्वर चौधरी के आश्रित को अनुग्रह अनुदान राशि चार-चार लाख रुपये का भुगतान सी0एफ0एम0एस0 प्रणाली से कर दी गयी है ।

श्री शिवचन्द्र राम: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह भुगतान कब की गयी, हम तिथि जानना चाहते है कि भुगतान कब की गयी ?

अध्यक्ष: कब किया गया है, इसकी सूचना है आपके पास माननीय मंत्री जी ?

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री: महोदय, रिपोर्ट जो आया है, बैंक का डायरेक्ट चेक अब दिया नहीं जाता है, बैंक इन्टरनेट के द्वारा दिया है लेकिन रिपोर्ट आ गया है जिला पदाधिकारी से कि भुगतान कर दिया गया है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य वही भुगतान जो आर0टी0जी0एस0 से हुआ है, वह किस तिथि को हुआ है, यह सूचना तो होती है, अगर वह अभी नहीं है, तो इसकी सूचना मॅगवाकर माननीय सदस्य को दे दीजिये ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री: ठीक है महोदय ।

श्री शिवचन्द्र रामः अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा यह जो लाया गया नियम है, वह अच्छा नियम है, यदि कोई भी आदमी ऐक्सिडेंट में मरता है या डूबकर मरता है ....

(व्यवधान)

अध्यक्षः उन्होंने तो कहा है कि भुगतान हो गया है ।

श्री शिवचन्द्र रामः एक मिनट महोदय ।

अध्यक्षः ठीक है, पूछिये न ।

श्री शिवचन्द्र रामः महोदय, उसको तो तत्काल पैसा देना है, ये 2.10.2018 को उसकी मृत्यु हो जाती है ......

(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य शिवचन्द्र जी, अभी पिछले ही प्रश्न पर मैंने आसन से सरकार को इस बात के प्रति आगाह किया है कि यह सरकार की स्कीम है कि सामूहिक दुर्घटना में मरते हैं, तो उन्हें अनुग्रह राशि दी जायगी, तो ये दुर्घटना होने के बाद शीघ्र से शीघ्र दी जानी चाहिए, यह आसन से हमने पहले ही कह दिया है पिछले प्रश्न के क्रम में, तब इस बात को कितनी बार कहा जाय ।

श्री शिवचन्द्र रामः अध्यक्ष महोदय, हमारे वैशाली जिला में लगभग 50 मामला अभी भी है ।

तारांकित प्र० संख्या-1007 (श्री विजय शंकर दूबे)

अध्यक्षः नहीं पूछेंगे ।

तारांकित प्र० संख्या-1008 (डा0 (मो0) नवाज आलम)

श्री कृष्ण कुमार ऋषि, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को स्थानान्तरित किया गया है ।

अध्यक्षः ठीक है ।

तारांकित प्र० संख्या-1009 (श्री सुबोध राय)

अध्यक्षः उत्तर आ गया है, आप देखे हैं ?

श्री सुबोध रायः जी नहीं देखे हैं ।

अध्यक्षः नहीं देखे हैं तो माननीय मंत्री जी पढ़ेंगे ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः महोदय, खण्ड 1: उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि 176 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उत्क्रमित होने के फलस्वरुप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन रिक्त हो गया है । इसी रिक्त भवनों में आयुष प्रक्षेत्र के राजकीय औषधालयों को स्थानान्तरित करने के लिए विभागीय पत्रांक-283 दिनांक 22.2.2019 के द्वारा सभी सिविल सर्जन एवं जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया है, क्योंकि राज्य में आयुष प्रक्षेत्र के अधिकांश

राजकीय औषधालय किराये के भवन में संचालित है । जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी भागलपुर के पत्रांक-137/19 दिनांक 27.6.19 द्वारा मात्र राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय बैकुंठपुर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सन्हौला में स्थानान्तरित करने के लिए आदेश दिया गया है । राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय तिलकपुर को विहपुर में स्थानान्तरित किया जाना है । राजकीय आयुर्वेदिक औषधाालय, बैकुंठपुर में डा0 उमेश कुमार, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित है । आयुर्वेदिक मिश्रक एवं वृत एवं सफाईकर्ता का पद रिक्त है । राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय तिलकपुर में डा0 उषा कुमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी एवं श्री अभय कुमार आयुर्वेदिक मिश्रिक पदस्थापित हैं तथा वृत सह सफाईकर्ता का पद रिक्त है ।

खण्ड 2: उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय बैकुंठपुर में प्रतिदिन औसतन 15 रोगी एवं राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय तिलकपुर में प्रतिदिन 16 रोगी का चिकित्सिय उपचार किया जाता है ।

खण्ड 3: उपर्युक्त कंडिका 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री सुबोध राय: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो शोर में मैं सुन नहीं सका पूरी बात ....(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप तो हेड फोन लगाये हुए हैं, तब क्यों नहीं सुन पाये ।

श्री सुबोध राय: इतना शोर हो रहा है न सर ।

अध्यक्ष: ठीक है । चलिये ।

श्री सुबोध राय: अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूॅं माननीय मंत्री जी से कि सरकार की हमारी नीति है कि हर गॉव में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करना ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब लाभान्वित हो सके ....(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप पूरक पूछिये न ।

श्री सुबोध राय: उसी में मैं जानना चाहता हूॅं कि ऐसी परिस्थिति है,गरीबों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना है और आज जब कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप पूरक पूछिये न ।

श्री सुबोध राय: मैं पूरक ही पूछ रहा हूॅं सर ।

अध्यक्ष: नहीं, आप नीति बता रहे हैं ।

श्री सुबोध राय: महोदय, मैं वही जानना चाहता हूॅं कि सरकार इन औषधालयों को गरीबों के हित में और ज्यादा सुदृढ़ करके वहॉ यथास्थान में बनाये रखने के लिए तैयार है कि नहीं ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, मैंने अपने जवाब में कहा है कि हम व्यवस्थाओं को बेहतर करना चाहते हैं,इसीलिए जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उत्क्रमित किया गया है,वहॉ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन हमारे 176 जो खाली

हुए हैं, उन जगहों पर हम व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इन लोगों की प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं ।

तारांकित प्र० संख्या-1010 (श्रीमती कुंती देवी)

श्री महेश्वर हजारी, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, खण्ड 1: उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खण्ड 2: उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है । वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत 240 अदद के विरुद्ध 139 अदद चापाकल का निर्माण को पूर्ण किया जा चुका है तथा 63 अदद का कार्य प्रगति में है एवं 38 अदद का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है । वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत 412 अदद के विरुद्ध 179 अदद चापाकल का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है, 138 अदद का कार्य प्रगति पर है एवं 95 अदद का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है । उल्लेखनीय है कि एक चापाकल के निर्माण में लगभग चार से पॉच दिनों का समय लगता है । स्थानीय स्तर पर बोरर की पर्याप्त मात्रा में संख्या नहीं रहने के कारण लक्ष्य के अनुरुप चापाकल का निर्माण संभव नहीं हो पा रहा है,परन्तु सीमित संसाधनों के बावजूद कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल-1 गया में चापाकलों के निर्माण हेतु सतत् प्रयत्नशील है । यह कार्य संवेदक के माध्यम से नहीं बल्कि विभागीय रुप से कराया जा रहा है । सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के अपर्याप्त संख्या के कारण कार्य कराने में कठिनाई हो रही है ।

खण्ड 3: उत्तर अस्वीकारात्मक है । मुख्य अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार चापाकल का निर्माण निर्धारित गहराई तक किया जा रहा है एवं उसके निर्माण पर आई0एस0आई0 निर्माण सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है । अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य अंचल-गया द्वारा 34 अदद चापाकलों की स्थल जांच की गयी है और उसके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सभी 34 अदद चापाकल चालू हालत में है ।

श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकारा है कि हमारे यहॉ अभियंताओं की कमी है, जिसके कारण हम समय पर कार्य को पूरा नहीं कर रहे हैं । पिछली बार सभी सदस्यों ने इस बात की चिंता जतायी कि अभी जो आप कनीय अभियंताओं का तबादला किया है,उसके कारण बहुत से कार्य कहीं न कहीं यह जो है, वह सफर कर रहा है,तो माननीय मंत्री महोदय, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कार्य की धीमी गति तो है ही, लेकिन इसके बाद जो स्थानान्तरण हुआ है बड़े पैमाने पर और यह सभी डिपार्टमेंटल काम हो रहा है, तो डिपार्टमेंटल काम होने के कारण और डिले होगा और यह कहीं न कहीं माननीय सदस्यों का भी इसमें जो है

बड़ा ही नुकसान होने वाला है, इसलिए हम चाहेंगे कि इसपर आप सदन को अवगत कराइये कि आप इन समस्याओं से कैसे निबटेंगे ।

टर्न-3/सत्येन्द्र/12-7-19

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो आया है और प्रश्न में जो माननीय सदस्य ने क्वेश्चन किया है, वह इसमें संलिप्त नहीं है लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, यदि इस प्रश्न से से संबंधित कोई आपका प्रश्न हो तो पूछिये, जांच कराना हो जांच कराईए, हम सब चीज कराने को तैयार हैं लेकिन इस प्रश्न से संबंधित पूछिये न ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1011(श्री लाल बाबू राम)

अध्यक्ष: श्री लाल बाबू राम नहीं पूछेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1012(श्री सीताराम यादव)

(व्यवधान)

श्री अवधेश कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम नहीं पूछ सकते हैं..

अध्यक्ष: क्यों नहीं पूछ सकते हैं, आप बैठ जाईए न, आपके पूछने का समय आयेगा तो हम आपको देंगे । इस पर अभी बात खत्म हो गयी, हम आगे बढ़ गये हैं ।

(व्यवधान)

अरे हम आगे बढ़ गये हैं अवधेश बाबू । चलिये, ऊर्जा विभाग जवाब दीजिये ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी एवं जयनगर प्रखंड के वीरपुर, मढ़िया, नरकटिया आदि कई ग्रामों में जर्जर तार पोल एवं बांस बल्ले को बदलने का कार्य राज्य योजनान्तर्गत किया जायेगा । कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य दिसम्बर, 19 है ।

श्री सीताराम यादव: जल्द करवा दिया जाय । महोदय, जल्द करवा दिया जाय । 50 वर्ष पहले का पोल, अभी लकड़ी वाला पोल है, सब लोग खूंटा गाड़ गाड़ कर तार ले गये है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: कहा कि दिसम्बर तक सब बदल दिया जायेगा ।

अध्यक्ष: दिसम्बर तक करा देंगे, कुछ महीने की बात है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1013(श्री सत्य नारायण सिंह)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय,स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि अकोढ़ीगोला प्रखंड अवस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करकटपुर अपने पुराने भवन में संचालित है । उपलब्ध भूमि पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करकरटपुर के जर्जर भवन की स्थिति का आकलन कराते हुए जीर्णोद्धार अथवा नये भवन निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदन प्राक्कलन की मांग निर्माण एजेंसी बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना से की गयी है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1014(श्री आबिदुर रहमान)

अध्यक्ष: वैसे तो उत्तर दिया हुआ है, शायद माननीय सदस्य ने पढ़ा नहीं होगा ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, अररिया जिलान्तर्गत अररिया प्रखंड के नगर परिषद बार्ड संख्या- 5 में किशोर श्रीवास्तव से चन्द्रशेखर पासवान के घर हृदयपुर पश्चिम टोले के बांस बल्लों को बदलने का कार्य आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है । कार्य पूर्ण करने का समय दिसम्बर, 19 है। नगर परिषद बार्ड नं0-18 जहांगीर बस्ती में कमरूद्दीन के घर तक पूर्व से बिजली सुचारू रूप से चल रही है एवं कमरूद्दीन के घर से 125 मीटर की दूरी पर आबिदहुसैन अंसारी द्वारा नया घर बनाया जा रहा है ।

(2) स्वीकारात्मक है । कमरूद्दीन के घर में 125 मीटर की दूरी पर आबिदहुसैन अंसारी द्वारा नया घर बनाया जा रहा है । आवेदन प्राप्त होने पर विद्युत सम्बद्ध प्रदान किया जायेगा ।

श्री आबिदुर रहमान: हुजूर, ये तो टाउन में है इसलिए मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था यही जवाब हमको मिला था इसलिए जल्द से जल्द करा दिया जाय । जवाब हर बार यही मिलेगा और साथ ही साथ अररिया जोकीहाट में भी इस बार बाढ़ आ चुका है और नाव की भी व्यवस्था किया जाय ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1015(श्री अब्दुस सुबहान)

अध्यक्ष: नहीं पूछेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1016(श्री नीरज कुमार सिंह)

(व्यवधान)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री:(1) आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि छातापुर प्रखंड में कुल 23 स्वास्थ्य उपकेन्द्र है जिसमें 7 का अपना भवन है ।

(2) प्रश्न में किस स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण अपूर्ण बतलाया गया है, यह स्पष्ट नहीं है । माननीय सदस्य से मैं आग्रह करूंगा कि जिसकी चर्चा आप करना चाहते हैं उस स्थान के बारे में बता दें तो मैं उस स्थान का अवलोकन करा लूंगा और यदि वहां निर्माण की जरूरत होगी तो हम उसको करवा देंगे ।

श्री नीरज कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी एक भी अस्पताल सही ढंग से चालू नहीं है । हम चाहते हैं मंत्री महोदय से कि जल्द से जल्द निर्माण करा दें, हम जगह बतला देते हैं जगह हम देखकर आये हैं ।

अध्यक्ष: बतला दीजिये ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: ठीक है महोदय ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1017 (श्री वीरेन्द्र कुमार)

(अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 1018(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः आंशिक स्वीकारात्मक है। औरंगावाद जिला के अन्तर्गत रि-कंडक्टिंग योजना के तहत नवीनगर विधान-सभा क्षेत्र के पुनपुन फीडर के ग्राम पौथू एवं बैरिया पंचायत में मे0 जंक्शन कम्पनी लि0 द्वारा जर्जर तार बदलने का कार्य प्रगति पर है । शेष बचे कार्य को नवम्बर,19 तक पूर्ण कर लिया जायेगा ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंहः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो बिहार सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और मंत्री जी के नेतृत्व में ऊर्जा विभाग का बहुत अच्छा काम हुआ है लेकिन मैं पूछना चाहता हूॅ, जो उत्तर आया है, जंक्शन कम्पनी कोई काम नहीं कर रहा है, हमलोगों को बार-बार जो है ये क्षेत्र से दवाब आ रहा है,तार रोज टूट जाता है, रोज ट्रिप करता है तो इसको कबतक करा देंगे ।

अध्यक्षः उन्होंने तो कहा है कि नवम्बर तक करा देंगे ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिहःमहोदय, वह जंक्शन कम्पनी कर ही नहीं रहा है महोदय, आप नहीं सुने हमारी बात, जंक्शन कम्पनी कोई काम नहीं कर रहा है और उन्होंने कहा है कि प्रगति पर है तो दोनों बात में अन्तर है तो हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं..

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादवः आप लिखकर दीजिये, अविलम्ब कार्रवाई की जायेगी ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 1019 (श्री नन्द कुमार राय)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः (1) स्वीकारात्मक है ।

(2) योजना में गुणवत्ता एवं मापदंड के अनुरूप कार्य हेतु साईट पर परियोजना प्रबंधक के एजेंसी द्वारा गुणवत्ता की जांच की जाती है एवं केन्द्र सरकार द्वारा थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा भी कार्य की गुणवत्ता की जांच की जाती है । शेष बचे बार्ड में कार्य प्रगति पर है, कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य दिसम्बर,19 निर्धारित है ।

श्री नन्द कुमार रायः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूॅ कि एल0एंड टी0 की जो योजना है, वह हमलोगों की बात को संज्ञान में नहीं लेता है उसके चलते वार्ड नं0 1 वार्ड नं0-11,12 और वार्ड नं0-6 में जर्जर है और वहां जो पोल है उसको नहीं बदला गया है । क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि कबतक पूरा करा देंगे ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः मैंने कहा कि कार्य प्रगति पर है दिसम्बर,19 तक कर दिया जायेगा आपकी बात नहीं सुनती है कम्पनी तो आप लिखकर हमको दीजिये, उसको सुनना पड़ेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1020(श्री संजीव चौरसिया)

(व्यवधान)

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री:(1) स्वीकारात्मक है।

(2)स्वीकारात्मक है।

(3) भूमि के सत्यापन हेतु जिला पदाधिकारी, पटना को निर्देशित किया गया है ।

(4) वर्त्तमान में ग्राम पंचायत नकटा दियारा स्वास्थ्य उपकेन्द्र कार्यरत है एवं यहां पदस्थापित दो ए0एन0एम0 श्रीमती शैल कुमारी एवं श्रीमती अर्चना कुमारी के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है । नकटा दियारा से मात्र 9 कि0मी0 पर ही अनुमंडलीय अस्पताल, दानापुर अवस्थित है । जिला पदाधिकारी, पटना से भूमि उपलब्धता प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विहित प्रक्रियानुसार अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की कार्रवाई की जायेगी ।

श्री संजीव चौरसिया: अध्यक्ष महोदय, भाई वीरेन्द्र को भी ध्यान देना चाहिए नकटा दियारा का मामला है विधान-सभा में कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है और माननीय मंत्री जी ने..

अध्यक्ष: वीरेन्द्र जी बैठ गये हैं अब आप पूछिये ।

श्री संजीव चौरसिया: महोदय, आज इतना गंभीर विषय कि नकटा दियारा जो पंचायत है वह पूरा केन्द्र बिन्दु है वह पाटलीपुत्र लोकसभा का हो, सारण का हो, चाहे पटना साहिब का हो तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहेंगे कि आश्वासन उन्होंने दिया है, उसकी प्रक्रिया का प्रारम्भ कब से करेंगे और प्रकार अस्पताल का क्या रहेगा, वह किस प्रकार से कॉमन हेल्थ सेंटर की अवधि के बारे में भी विचार माननीय मंत्री को हैं कि नहीं, ये मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: प्रक्रिया की शुरूआत कर दी गयी है जिला पदाधिकारी, पटना को पत्र प्रेषित किया जा चुका है और अतिरिक्त प्रा0स्वा0केन्द्र स्तर का अस्पताल वहां बनाया जायेगा।

अध्यक्ष: क्या है,आपका रिंकू जी।

टर्न-4/मधुप/12.07.2019

अध्यक्ष : रिंकू जी, क्या कहना चाह रहे हैं ?

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिन्कु सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष के लोगों की यह कैसी संवेदना है कि विरोध भी कर रहे हैं तो हँस-हँसकर कर रहे हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1021 (श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, 1- अस्वीकारात्मक है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी जगह पर खड़े होकर कुछ बोलने लगे)

(व्यवधान)

वस्तुस्थिति यह है कि सदर अस्पताल मोतिहारी के बगल में ही रेड क्रॉस भवन मे पूर्व से ही संचालित है और आवश्यकतानुसार सभी मरीजों को ब्लड की सुविधा उपलब्ध है ।

2- सदर अस्पताल, मोतिहारी में ब्लड बैंक खोलने हेतु कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है । इसके अन्तर्गत बी0एम0एस0आई0सी0एल0 से ब्लड बैंक के लिए उपकरण भी प्राप्त हो चुका है जिसका इंस्टॉलेशन 15 दिनों के अन्दर करा दिया जायेगा।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सदर अस्पताल के बगल में जो यह ब्लड बैंक स्थापित की बात कर रहे हैं रेड क्रॉस के माध्यम से....

अध्यक्ष : उन्होंने यह नहीं कहा कि बात कर रहे हैं, वह चालू है और आप जो सदर अस्पताल में पूछ रहे हैं, वहाँ कहे हैं कि 15 दिन में मशीन पहुँचा देंगे ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : सर, जो चालू है.....

अध्यक्ष : उसकी कहाँ बात है ? आप जहाँ पूछ रहे हैं, उसके बारे में कह रहे हैं कि 15 दिन में मशीन पहुँचा देंगे ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : 15 दिन में कहाँ कह रहे हैं !

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : मशीन पहुँच चुका है, उसकी शुरूआत हो जायेगी ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष : आपके प्रश्न का जवाब हो गया ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : नहीं महोदय । एक मिनट । क्या मंत्री जी उसका उद्घाटन 15 दिनों में करवा देंगे ?

अध्यक्ष : श्री सरोज यादव ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 1022 (श्री सरोज यादव)</u>

अध्यक्ष : श्री सरोज यादव । नहीं पूछेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 1023 (श्री राजेश कुमार)</u>

अध्यक्ष : श्री राजेश कुमार ।

श्री ललित कुमार यादव : नहीं पूछेंगे सर ।

अध्यक्ष : वह तो हम एक बार में ही समझ गये हैं । नहीं पूछेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1024 (श्री चन्द्रसेन प्रसाद)

अध्यक्ष : चन्द्रसेन जी, आप उत्तर पढ़कर आये हैं ? देखकर आया करिये ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, नालंदा जिला में कृषि कार्य हेतु फीडर का निर्माण दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अन्तर्गत किया जा रहा है जिसमें इस्लामपुर और एकंगरसराय प्रखंड का कार्य भी शामिल है । वर्तमान में कृषि कार्य हेतु इस्लामपुर प्रखंड में 50 कि0मी0 11 के0वी0ए0 लाईन, 38 ट्रांसफर्मर और 62 कि0मी0 एल0टी0लाईन का निर्माण किया गया है । एकंगरसराय प्रखंड में 27 कि0मी0 11 के0वी0ए0 लाईन, 41 ट्रांसफर्मर और 60 कि0मी0 एल0टी0लाईन का निर्माण किया गया है । इसके अतिरिक्त 26.06.19 तक कृषि कार्य के लिए नये विद्युत संबंधन हेतु प्राप्त सभी आवेदनों के विरूद्ध दिसम्बर, 2019 तक संरचना का निर्माण कर विद्युत संबंधन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित है ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1025 (श्री समीर कुमार महासेठ)

अध्यक्ष : श्री समीर कुमार महासेठ । नहीं पूछेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1026 (श्री अनिल सिंह)

अध्यक्ष : श्री नितिन नवीन ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री : महोदय, प्राकृतिक आपदा एवं गैर प्राकृतिक आपदा अथवा स्थानीय प्रकृति की आपदा से होने वाली मृत्यु पर जिला पदाधिकारी को यह संतुष्ट होना है कि मृत्यु उसी प्राकृतिक आपदा एवं गैर प्राकृतिक आपदा अथवा स्थानीय प्रकृति के आपदा जनित कारणों से हुई है, मृत्यु का कारण विनिश्चय करने हेतु पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है । पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अभाव में जिला स्तर पर गठित जॉंच टीम के द्वारा समर्पित स्थल जॉंच प्रतिवेदन के आधार पर मृतक के आश्रित को सरकार द्वारा निर्धारित अनुग्रह अनुदान की राशि 4 लाख रूपये का भुगतान किया जाता है ।

इस तरह के मामलों में लू से मृत्यु होने का सत्यापन संभव नहीं हो पाने के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं है ।

श्री नितिन नवीन : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार के पास कोई ऐसा सर्वे की व्यवस्था है जो पोस्टमॉर्टम के अतिरिक्त लू से कितनी मौतें हुई, चूंकि जबतक यह जानकारी रहेगी तभी जिलाधिकारी लेवेल पर बात होगी । सरकार के पास कोई सर्वे या रिपोर्ट है कि पोस्टमॉर्टम के बावजूद कितनी मौतें हुईं पूरे गर्मी के दौरान ?

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : हमको तो मन कर रहा था कि मंत्री जी को बैठा देते हैं, सत्यदेव प्रसाद सिंह जी सारे प्रश्नों का जवाब दे देंगे ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री : महोदय, वहॉं के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मंत्री जी, आप बैठ जाइये, सत्यदेव जी बोल रहे हैं, बोलिये ।

हो गया ? आप उनको बोले न बोलने के लिए ! बोलिये मंत्री जी ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री : महोदय, पोस्टमॉर्टम के अभाव में वहॉं टास्क फोर्स की कमिटी है, यदि वह संतुष्ट हो जाती है कि यह लू के चलते मरा है तो उसको अनुदान की राशि सरकार द्वारा दिया जाना है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं राज्य की जनता के बीच में यह घोषणा किया कि औरंगाबाद, गया, नवादा या अन्य जगह में जो लू से मृत्यु हुई है, इसको प्राकृतिक आपदा मानते हुये उन्हें भी 4 लाख रूपये मुआवजा मुहैया कराया जायेगा ।

क्या विभाग माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में किसी तरह की कार्रवाई की है या नहीं की है ? या नहीं तो माननीय मंत्री यही बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री ने विभाग से सम्पर्क करके कोई घोषणा की ही नहीं थी ?

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री : महोदय, औरंगाबाद में अबतक 54 आदमी लू से मरे हैं, गया में 39 आदमी मरे हैं, नवादा में 14 आदमी मरे हैं, कुल 107 आदमी....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जानना यह चाह रहे हैं कि सरकार की घोषणा के मुताबिक गया हो, औरंगाबाद हो, जहॉं भी हो, लू से जो मौतें हुई हैं, उनको 4 लाख रूपये की अनुग्रह राशि के भुगतान की स्थिति क्या है ? वह जानना चाह रहे हैं ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री : यही तो बता रहे हैं । महोदय, प्रत्येक जिला में, जैसे औरंगाबाद जिला में लू लगने से 54 लोगों को 4 लाख रूपया जो अनुदान राशि है, वह दे दिया गया है ।

अध्यक्ष : 54 लोगों को 4 लाख रूपया भुगतान कर दिया गया है ?

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री : जी, किया गया है । 54 लोगों को भुगतान किया गया है । गया-39, नवादा-14, कुल 107 लोगों को अभी तक 4-4 लाख रूपया का अनुदान राशि उनको दे दिया गया।

अध्यक्ष : मंत्री जी, आपके कहने का मतलब है कि जितने लोगों की मौत हुई है या हुई होगी, उन सबको सरकार भुगतान करने का विचार रखती है ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री : विचार है ही ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री आनंद शंकर सिंह : महोदय....

अध्यक्ष : बोलिये ।

श्री आनंद शंकर सिंह : महोदय, सरकारी आंकड़ा है 54 का, सरकार के द्वारा यह बोला गया...

अध्यक्ष : आनंद शंकर जी, जो सरकार के पास आंकड़े हैं, सरकार वहीं बताती है । अगर आपके पास कोई दूसरा आंकड़ा है, अगर आपके कहने के मुताबिक मंत्री जी कह रहे हैं 50 मरे, एक उदाहरण के तौर पर कहता हूँ, आपके हिसाब से अगर 70 मरे हैं तो 70 लोगों की सूची आप इनको उपलब्ध करा दीजिये । ये जॉच करा लेंगे ।

श्री आनंद शंकर सिंह : माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी गये थे, इन्होंने बोला था....

अध्यक्ष : प्रश्न संख्या-1027 : श्री सत्यदेव सिंह । नहीं पूछेंगे ।

श्री सत्यदेव सिंह : नहीं महोदय, मैं पूछ रहा हूँ ।

अध्यक्ष : अच्छा, सत्यदेव सिंह पूछ रहे हैं ! दो सत्यदेव सिंह हैं न !

(व्यवधान)

स्वाभाविक रूप से जब सत्यदेव सिंह की बात आती है तो आसन का ध्यान इन्हीं की तरफ जाता है ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : हम सत्यदेव प्रसाद सिंह हैं ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, श्री सत्यदेव जी क्यों नहीं पूछेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : क्यों पूछेंगे ! सत्यदेव राम जी, एक सत्यदेव आप भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि यह प्रश्न नहीं पूछे हैं इसलिये और प्रश्न भी नहीं पूछा जाय, तो यह भी बता दीजिये । अगर आपकी इच्छा है कि शेष प्रश्न भी नहीं पूछे जायं तो आसन को क्या एतराज हो सकता है । बताइये ? अगर आप चाहते हैं कि कोई माननीय सदस्य अपना प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं इस कारण आगे भी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाय, अगर आपकी इच्छा यही है तो बता दीजिये, नहीं तो आगे का प्रश्न होने दीजिये ।

श्री सत्यदेव सिंह । स्वास्थ्य विभाग ।

टर्न-5/आजाद/12.07.2019

तारांकित प्रश्न सं0-1027(श्री सत्यदेव सिंह)

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सोनभद्र बंशी अवस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमित करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ बोलने लगे)

निर्माण एजेंसी बी0एम0एस0आई0सी0एल0,पटना के द्वारा भूमि उपलब्धता के आधार पर तकनीकी अनुमोदित पुनरीक्षित प्राक्कलन उपलब्ध करा दी गई है । इस वित्तीय वर्ष में विहित प्रक्रिया के अनुसार राशि उपलब्धता के अनुसार भवन निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जायेगा ।

श्री सत्यदेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि अगले बार भी मैंने प्रश्न किया था तो यही जवाब आया था । मेरा कहना है कि प्राक्कलन कब तक बन जायेगा और कब तक कार्य शुरू होगा ?

अध्यक्ष : सरकार ने कहा है कि इसकी स्वीकृति हो चुकी है तो आप प्राक्कलन पर हैं । सुनते ही नहीं हैं ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त हुआ है, पहले जो हुआ होगा, उसके बाद पुनरीक्षित किया गया है और उसके अनुसार निर्माण कार्य होगा ।

अध्यक्ष : हो गया । तारांकित प्रश्न सं0-1028, श्री अजीत शर्मा ।

तारांकित प्रश्न सं0-1028(श्री अजीत शर्मा)

अध्यक्ष : अजीत शर्मा जी, आपने उत्तर पढ़ा है क्या ?

श्री अजीत शर्मा : नहीं सर ।

अध्यक्ष : मैं इसलिए बार-बार स्मारित करता हूँ कि आप पढ़कर आते तो आप इसपर पूरक पूछते।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, स्वीकारात्मक है ।

भागलपुर में विद्युत आपूर्ति की जिम्मेवारी फ्रेन्चाईजी के तहत मे0 एस0पी0एम0एल0 को थी, इस कारण इस शहर को किसी योजना में शामिल नहीं किया गया था । भागलपुर शहर में जर्जर पोल एवं तार के सुदृढ़ीकरण के कार्य दिनांक 8.3.2019 को आवंटित किया गया है । सर्वे का कार्य किया जा रहा है । प्राणवती लेन नीलकंठ नगर, सक्कुलाचक एवं शैलबाग कॉलोनी के जर्जर लकड़ी के पोल एवं तार बदलने का कार्य उक्त योजना में शामिल है, जिसे दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब से सरकार ने हैंडऑवर लिया है बिजली का भागलपुर का, पहले भागलपुर में 23 घंटा बिजली रहती थी, पूरे मेन्टेन

होते थे, लेकिन जब से लिया गया है, तब से 16 घंटे ट्रिपिंग होते रहता है और 16 घंटा बिजली है । एक भी तार 5 साल में नहीं बदले गये हैं, यह तो बोल रहे हैं, इन्होंने टाटा कम्पनी को दिया है, टाटा कम्पनी ने एक काम भी शुरू नहीं किया है, यह आपको पता होगा और सारे पदाधिकारियों को पता है और वहां पर एक भी योजना नहीं चल रही है..

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, मैं पूरक पूछ रहा हूँ कि यहां पर एक भी योजना शुरू नहीं किये गये हैं तो आप टाटा कम्पनी पर क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि यहां पर एक भी काम शुरू नहीं किया गया है, न तो तार बदलने का, न ट्रांसफर्मर बदलने का, इसपर माननीय मंत्री जी क्या कार्रवाई करेंगे ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि इधर ठेका आवंटन किया ही गया है, बीच में आचारसंहिता वगैरह भी थी । सर्वे का काम प्रगति पर है, दिसम्बर तक करने का लक्ष्य है ।

अध्यक्ष : दिसम्बर तक पूरा कर देंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-1029(श्री मो0 नेमतुल्लाह)

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, नहीं पूछेंगे । क्यों नहीं पूछेंगे .....

अध्यक्ष : नहीं पूछेंगे तो इसके आगे कुछ नहीं कहना है । 1030 श्री विद्यासागर केशरी । पर्यटन विभाग ।

(व्यवधान)

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : नेमतुल्लाह जी, मैं बोल दूँगा तो बहुत बातें खुल जायेगी । मैं यदि बोल दूं तो बहुत बातें खुल जायेगी महोदय ।

अध्यक्ष : चलिए पर्यटन विभाग का प्रश्न होने दीजिए ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0-1030(श्री विद्यासागर केशरी)

श्री कृष्ण कुमार ऋषि,मंत्री : महोदय, जिला पदाधिकारी, अररिया से विभागीय ज्ञापांक-1354 दिनांक 6.7.2019 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गई है । जैसे ही जिला पदाधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त होता है, उसपर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री विद्यासागर केशरी : महोदय, यह भद्रकाली मंदिर 500 वर्ष पुराना है । सीमांचल से काफी हजारों की संख्या में रोज पर्यटकों का आना-जाना है और यह आस्था भरा मंदिर है । मैं चाहूँगा कि इसको पर्यटक रोड मैप में शामिल किया जाय । वहां सौंदर्यीकरण एवं

जो व्यवस्था होनी चाहिए मंदिर के आस-पास, वह करवाया जाय, मेरा माननीय मंत्री जी से यही आग्रह है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1031(श्री प्रभुनाथ प्रसाद)</u>

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, 1. अस्वीकारात्मक है ।

2. अस्वीकारात्मक है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि अंगियाव प्रखंड अन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अजीमाबाद, किरकिरी संचालित है परन्तु भवन अत्यंत जर्जर होने के कारण सरकारी पंचायत भवन में दो चिकित्सकों के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है । भवन निर्माण के लिए बी0एम0एस0आई0सी0एल0,पटना से प्रस्ताव मांगा गया है, 30 बेड के रेफरल अस्पताल अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण प्रखंड स्तर पर ही प्रावधानित है । पंचायत स्तर पर कोई भी योजना सरकार के स्तर पर विचाराधीन अभी नहीं है ।

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, वह एक अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है और वहां पर सरकारी जमीन उपलब्ध है । वहां अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र जो है, उसका भी निर्माण अगर करा दिया जाता तो वह पिछड़ा क्षेत्र में यह सुविधा मिल जाती....

अध्यक्ष : ठीक है, आप यह सुझाव दे दीजियेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1032(श्री विजय कुमार खेमका)</u>

(व्यवधान)

श्री मंगल पाण्डेय,मत्री : महोदय,1. आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णिया जिले में कुल 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है । इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत कुल 70 चिकित्सा पदाधिकारी के पद के विरूद्ध सम्प्रति मात्र 17 चिकित्सा पदाधिकारी कार्यरत है । इन 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा प्रतिमाह औसतन 1,07,194 वाह्य रोगियो एवं 6712 अन्तर्वासी रोगियों को स्वास्थ्य सेवा दी जाती है ।

2. राज्य में महिला चिकित्सकों की भारी कमी है । राज्य में स्वास्थ्य सेवा में अपेक्षित सुधार लाने हेतु बिहार स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत 2425 विशेषज्ञ चिकित्सक एवं 4012 सामान्य चिकित्सक अर्थात 6437 चिकित्सकों नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है । नियुक्ति होने के उपरान्त उपलब्धता के आधार पर महिला चिकित्सा पदाधिकारियों की पदस्थापना आवश्यकतानुसार की जायेगी।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के जो माननीय सदस्य है, उनको बिहार की स्वास्थ्य की चिन्ता नहीं है ......

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए न । आपके प्रश्न का जवाब स्वास्थ्य मंत्री जी देंगे ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक ही पूछ रहा हूँ । अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि पूर्णिया जिला का यह सदर अस्पताल सीमावर्ती क्षेत्र में है, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ की काफी कमी है, सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है । लेकिन मेरा आग्रह होगा कि वहां पर स्त्री रोग विशेषज्ञ का पदस्थापन करें ।

तारांकित प्रश्न सं0-1033(श्री अशोक कुमार सिंह)

(व्यवधान)

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, 1. आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि शिवाजीनगर प्रखंड के भटौरा में प्रस्तावित स्वास्थ्य उपकेन्द्र के लिए भूमि उपलब्ध है । जबकि वारिशनगर प्रखंड के सतमलपुर में भूमि उपलब्ध नहीं है। लेकिन किराये के मकान में स्वास्थ्य उपकेन्द्र चल रहा है । भटौरा अवस्थित उपलब्ध भूमि पर स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन का निर्माण विहित प्रक्रिया के अनुसार शीघ्र प्रारंभ किया जायेगा ।

श्री अशोक कुमार सिंह : महोदय, वारिसनगर के सतमलपुर में भी जमीन उपलब्ध है, विभाग में इसकी सारे कागजात आ चुके हैं । मैं अनुरोध करता हूँ कि माननीय मंत्री जी इसपर जरा गौर करें ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1034(श्री सुबेदार दास)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नहीं पूछेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-1035(श्री मुजाहिद आलम)

(व्यवधान)

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2. उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक-2690 दिनांक 18.02.2007 के कंडिका-10 के बिन्दु सं0-ii पर चयन का आधार विज्ञापित शैक्षणिक योग्यता का ''प्राप्तांक के कार्य अनुभव एवं साक्षात्कार होगा'' के आधार पर किया गया है ।

3. उक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री मुजाहिद आलम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्रांक-3528 दिनांक 20.8.2018 जिसके द्वारा यह सभी जिले के सभी

सिविल सर्जन, जिला पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक की नियुक्ति में मैट्रिक, इन्टर, स्नातक, एम0बी0ए0 के प्राप्तांक के आधार पर ही उसकी बहाली होगी । इसलिए इसमें पूरी अनियमितता हुई है । इसलिए जब मेरीट लिस्ट निकला, मेधा सूची जारी हुआ, उस समय सारे प्राप्तांक को जोड़ा गया लेकिन बाद में जो है, इसको हेराफेरी करके बहाली किया गया । इसलिए मैं मांग करता हूँ कि इसकी जॉंच करायी जाय ।

अध्यक्ष : आप दे दीजियेगा ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, मैं इसको देख लूँगा ।

टर्न-6/शंभु/12.07.19

तारांकित प्रश्न सं0-1036 (श्री अभय कुमार सिन्हा)

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, 1-स्वीकारात्मक है ।

2-स्वीकारात्मक है ।

3-स्वास्थ्य उपकेन्द्र डिबरी का भवन निर्माण भूमि उपलब्धता संबंधी अभिलेख प्राप्त होने पर कराया जायेगा । उसके लिए जिला पदाधिकारी, गया को आवश्यक निदेश दे दिया गया है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1037 (श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, 1- उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 का उप संवेदक को राशि का भुगतान नहीं होने के कारण जुलाई 2017 से एक्सरे मशीन बंद था, अब राशि की भुगतान कर दी गयी है । एक्सरे मशीन दिनांक 08.07.2019 से चालू करा दी गयी है ।

2- उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पूर्व में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परसौनी के बाह्य कक्ष एवं अंत: कक्ष में इलाज कराने आये हुए मरीजों को एक्सरे कराने के लिए निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलसंड में रेफर किया जाता था जिसकी दूरी 6 कि0मी0 है । अब एक्सरे मशीन चालू अवस्था में है ।

3- उक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : महोदय, दो वर्षों से एक्सरे मशीन खराब है परसौनी का तो इसके लिए अधिकारी और पदाधिकारी पर कौन सी कार्रवाई करेंगे माननीय मंत्री जी ? दो वर्षों से खराब है ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्या ने ठीक विषय उठाया है । इसके लिए विभाग से संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा जा चुका है ।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : कब तक करवा देंगे ? समय सीमा बता दें ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : बहुत शीघ्र स्पष्टीकरण पूछा गया है, कार्रवाई होगी ।

तारांकित प्रश्न सं0-1038 (डा0 सी0एन0गुप्ता)(अनुपस्थित)

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष : व्यवस्था है कि अव्यवस्था है ?

श्री भाई वीरेन्द्र : जब आऊस आर्डर में नहीं है तो नहीं चलना चाहिए ।

अध्यक्ष : आप यह भी बता दीजिए कि जब सदन में डिस्आर्डर फैलाने वाले डिस्आर्डर का प्रश्न उठायें तब आसन को क्या करना चाहिए ? जो डिस्आर्डर फैलावें वही डिस्आर्डर का व्यवस्था उठावें तो आसन को क्या करना चाहिए ? आप बता दीजिए ।

तारांकित प्रश्न सं0-1039 (श्रीमती गुलजार देवी)

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2-स्वीकारात्मक है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि रेफरल अस्पताल मधेपुर पूर्व में अपने भवन में संचालित था । वर्तमान में भवन की स्थिति जर्जर होने के कारण इसका संचालन कुछ दूरी पर अवस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में किया जा रहा है। रेफरल अस्पताल मधेपुर का निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है । इसकी जॉच हेतु भवन निर्माण विभाग को लिखा गया है । इसके भवन की स्थिति का आकलन करते हुए जीर्णोद्धार अथवा रेफरल अस्पताल के समतुल्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के नये भवन निर्माण की संभावनाओं पर तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराने का निदेश निर्माण एजेंसी बी0एम0एस0आइ0सी0एल0 पटना को दिया गया है ।

श्रीमती गुलजार देवी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पी0एच0सी0 और रेफरल एक ही में चलता है । उसको अलग कब तक करेंगे मंत्री जी उसकी समय सीमा बता दें ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैंने अपने जवाब में इस बात का उल्लेख किया है कि रेफरल अस्पताल मधेपुर का निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है । वह जीर्णशीर्ण स्थिति में हो गयी है । उसका जॉच कराया जायेगा, चूंकि वह भवन निर्माण विभाग का बनाया हुआ है इसलिए उसकी रिपोर्ट आयेगी और उसके बाद हमने बी0एम0एस0आइ0सी0एल0, पटना को निदेश कर दिया उसका प्राक्कलन तैयार करने के लिए ।

तारांकित प्रश्न सं0-1040 (श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेय)

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : 1- आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि कबार अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के जीर्णशीर्ण अवस्था में होने के कारण स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन में संचालित है । यहां एक आयुष चिकित्सक डा0 अरविन्द कुमार, दो ए0एन0एम0 श्रीमती रमावती कुमारी एवं श्रीमती परीना कुमारी तथा एक स्टाफ ग्रेड नर्स श्रीमती संगीता कुमारी पदस्थापित हैं । यह सदर अस्पताल से मात्र 7-8 कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित है । अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कबार के जर्जर एवं अर्द्धनिर्मित भवन की स्थिति का आकलन कराते हुए जीर्णोद्धार अथवा नये भवन निर्माण की संभावनाओं पर तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की मांग निर्माण एजेंसी बी0एम0एस0आइ0सी0एल0, पटना से की गयी है ।

2- उपर्युक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेय : महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि ये गलत जानकारी दिया गया है वहां कोई कर्मचारी और डाक्टर नहीं बैठते हैं । माननीय मंत्री जी को गलत जानकारी दी गयी है । वहां भवन जीर्णशीर्ण अवस्था में है और लोग अतिक्रमण किये हुए हैं । उसका पुनर्निर्माण कराकर डाक्टर, नर्स और कर्मचारी को बैठने के लिए निदेश दिया जाय ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्या ने जो विषय उठाया है । मैंने चिकित्सक का नाम दिया है- डा0 अरविन्द कुमार और दो ए0एन0एम0 श्रीमती रमावती कुमारी और परीना कुमारी और स्टाफ ग्रेड नर्स संगीता कुमारी पदस्थापित हैं ।

अध्यक्ष : अतिक्रमण वाला देखवा लीजिए ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : उसको भी मैं देखवा लूंगा कि ये उपस्थित हैं या नहीं और अतिक्रमण वाला भी देखवा लूंगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-1041 (श्री सत्य नारायण सिंह)

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि उप स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा पदाधिकारी का पदस्थापन नहीं किया जाता है । इन केन्द्रों द्वारा टीकाकरण एवं प्राथमिक चिकित्सा की जाती है । इस हेतु स्वास्थ्य उप केन्द्रों में ए0एन0एम0 की पदस्थापना की जाती है । संदर्भित स्वास्थ्य उप केन्द्र में ए0एन0एम0 कार्यरत है ।

श्री सत्यनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी सरकार का कहीं जमीन नहीं है, लेकिन वहां सब बना हुआ है तो मैं आग्रह करूँगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था इतना सुदृढ़ कर रहे हैं तो वहां एक डाक्टर, एक ए0एन0एम0- ए0एन0एम0 अभी वहां नहीं है ।

अध्यक्ष : ठीक है, वो मंत्री जी देखवा लीजिए ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : जी ।

तारांकित प्रश्न सं0-1042 (श्रीमती अमिता भूषण)

अध्यक्ष : नहीं पूछेंगी ।

तारांकित प्रश्न सं0-1043 (श्रीमती पूनम देवी यादव)

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । खगड़िया जिला में 443 ए0एन0एम0, 156 जी0एन0एम0, 34 एल0एच0बी0, 4 नेत्र सहायक, 6 बी0सी0जी0, 22 अचिकित्सा सहायक, 32 परिधापक क्रमश: स्वीकृत पदों में से 216 ए0एन0एम0, 60 जी0एन0एम0, शून्य एल0एच0बी0, 2 नेत्र सहायक, शून्य बी0सी0जी0, 3 अचिकित्सा सहायक, 4 परिधापक कार्यरत हैं । बिहार कर्मचारी चयन अयोग द्वारा अनुशंसित 6480 अभ्यर्थियों की ए0एन0एम0 के पद पर नियुक्ति निमित्त जिला आवंटन की कार्रवाई अंतिम चरण में है । जी0एन0एम0, नेत्र सहायक एवं अन्य चिकित्सा सहायक के पदों की अधियाचना भेजी जा चुकी है ।

श्रीमती पूनम देवी यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि खगड़िया का एक मात्र अस्पताल 100 बेड का है और इन्होंने जी0एन0एम0, ए0एन0एम0 का जिक्र किया कि अधियाचना भेजी जा चुकी है तो हम कहना चाहते हैं कि ये सदर अस्पताल दार्जिलिंग से लेकर पटना तक में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है, जो जिला का अस्पताल है । क्या माननीय मंत्री जी जो रिक्त पद है, डाक्टर की कमी है और डाक्टर भी है तो बगल के जिले बेगुसराय में अपना क्लीनिक चलाते हैं । माननीय मंत्री जी क्या उस डाक्टर पर कार्रवाई करना चाहते हैं, जो हास्पीटल में नहीं रहकर निजी क्लीनिक चलाते हैं ?

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, मैं इसको देखवा लेता हूँ ।

टर्न-7/ज्योति/12-07-2019

तारांकित प्रश्न संख्या-1044(श्रीमती बेबी कुमारी)

श्री कृष्ण कुमार ऋषि, मंत्री : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । जिला पदाधिकारी से वहाँ की स्थिति के बारे में मांग की गयी हे । जैसे ही जिला पदाधिकारी की रिपोर्ट आती है अद्यतन कार्रवाई की जायेगी ।

श्रीमती बेबी कुमारी :अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द मंगवाकर पर्यटन स्थल को विकसित करें ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : महोदय, मैंने बोला कि जिला पदाधिकारी के यहॉं पत्र भेजा गया है जैसे वहॉं से रिपोर्ट आती है उसपर कार्रवाइ्र की जायेगी ।

अध्यक्ष : ठीक है, प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाय ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनाँक 12 जुलाई, 2019 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । श्री मो0 नेमतुल्लाह, श्री मो0 नवाज आलम एवं श्री समीर कुमार महासेठ । आज सदन में वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांग पर वाद विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 172 (3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है। अब शून्य काल ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय,.

अध्यक्ष : शून्यकाल तो आपका भी है । क्या है ?

श्री मो0 नेमतुल्लाह : जल जमाव की जो स्थिति है, पूरे बिहार में और पटना में तो देखिये कि पूरा पटना झील बना हुआ है अस्पतालों में मछलियाँ तैर रही हैं और जिला में जाईये तो समाहरणालय और अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड में मरीज इतने परेशान हैं इतने महत्वपूर्ण विषय को इस तरह से इग्नोर किया जायेगा तो इसपर एक चर्चा चलानी चाहिए ।

शून्य काल

अध्यक्ष : अब शून्य काल । श्री विनोद प्रसाद यादव ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत डोभी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दो कमरा में चल रहा है जिससे मरीजों के इलाज में काफी कठिनाई होती है । स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु अंचल द्वारा जमीन उपलब्ध करा दी गयी है । जनहित में अविलम्ब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डोभी के निर्माण की मांग मैं सरकार से करता हूँ।

श्री अशोक कुमार सिंह : महोदय, औरंगबाद जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल दाउदनगर के द्वारा रफीगंज प्रखंड में रफीगंज से चैंव पथ की मरम्मती हेतु डी.पी.आर. मई 2018 में ही भेजा गया है जो आजतक लंबित है बरसात के दिनों में आवागमन बंद हो गया है जनहित में यथाशीघ्र कार्यान्वयन कराने की मांग करता हूँ ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, हरसिद्धी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत क्षेत्रान्तर्गत हरसिद्धी तिरकौलिया दोनों प्रखंडो में एफ.सी.आई. गोदाम से ठीकेदारों के द्वारा सड़ा हुआ गेहूँ, चावल जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा आपूर्ति की जा रही है । कभी कभी जन वितरण दुकानदारों को कागज में आपूर्ति दिखला कर भारी कालाबाजारी की जा रही है अत: जॉच करवा कर कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

श्री अमित कुमार : महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रीगा,सुप्पी, मेजरगंज एवं बैरगनिया प्रखंड के क्षेत्रफल को मिलाकर लाखों आबादी को प्रशासनिक एवं अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अनुमंडल कार्यालय की स्थापना करावे ।

श्री मो0 नवाज आलम : महोदय, भोजपुर जिला के आरा के रमना मैदान को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड के ग्राम बघेजी के बीच से रेल लाईन क्रौस करती है जिससे स्थापित रेलवे ढाला को बंद किया जा रहा है जिससे गांव के एक छोर से दूसरे छोर के जाने में तीन किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है अतः सरकार से रेल विभाग के ढाला को बंद करने से रोक लगाने की अनुशंसा करने की मांग करते हैं ।

श्री सुबोध राय : अध्यक्ष महोदय, सुल्तानगंज नगर परिषद में कृष्णानंद उच्च विद्यालय के पीछे कस्तूरबा बालिका छात्रावास में चहारदिवारी का अभाव है एवं प्रांगण में जल जमाव से असुरक्षा एवं अस्वास्थ्यकर वातावरण बना रहाता है अतः सुरक्षा एवं स्वास्थ्य वातावरण हेतु मैं वहॉ चहारदिवारी निर्माण एवं आंगन ऊंचा कराने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री ललन पासवान : महोदय, रोहतास जिला अंतर्गत चेनारी प्रखंड के रघुनाथपुर से बरताली खुर्द होते हुए बरताली कला से एस. एच.67 तक कच्ची पथ है जिसमें लगभग 800 महादलित परिवार है । आवागमन बाधित अतः सरकार से मांग करते हैं उक्त कच्ची पथ को पक्की बनायी जाय ।

श्री अशोक कुमार सिंह, (क्षे0स0-203): अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला के नुआव प्रखंड के अंतर्गत मोरथ गांव के पास धर्मावती नदी पर पुल नहीं होने के कारण कैमूर जिला के लोगों को 20 कि.मी. घूमकर बक्सर रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है सरकार से धर्मावती नदी पर मोरथ गांव के पास पुल बनाने की मांग करता हूं ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, दिनॉक 9-06-2019 को मसरख थाना जिला सारन में जघन्य हत्या की गयी जिसका काण्ड संख्या 19/19 है । काण्ड के आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित परिवार दहशत में है । हत्यारोपित अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : श्री सुधीर कुमार ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव: अध्या महोदय, सरकार सूचना ग्रहण करे ।

अध्यक्ष : ठीक है, सरकार सूचना ग्रहण करेगी ।

श्री सत्यदेव सिंह : महोदय, आरोपित की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गयी है ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री सुधीर कुमार ।

श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जमुई जिलान्तर्गत खैरा एवं सिकन्दरा प्रखंड को सिंचाई उपलब्ध कराने वाली अपर क्यूल जलाशय योजना क्षतिग्रस्त हो गयी है । किसानों के खेतों में पूर्ण रुपेण पटवन नहीं हो पाती है जिस कारण किसानों का फसल नहीं हो पाती शीघ्र इस योजना का लाभ किसानों को दिलावें।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिलान्तर्गत कप्तान पुल के दक्षिण संथाल टोला लालगंज पंचायत में सौरा नदी से दक्षिण किसान टोला कवैया पंचायत में कमला घार के पास महादलित टोला को नदी के कटाव से खतरा है अत: मैं सरकार से उक्त स्थानों पर बाढ़ पूर्व कटाव रोधक कार्य कराने की शीघ्र मांग करता हूँ ।

श्री आनंद शंकर सिंह : महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत ग्राम पंचायत खेराबिन्द के ग्राम मंजुराही खैरा खैरी सूसनार, भोजाबिगहा में बिहार स्टेट ट्रांसमीशन कंपनी लि0 द्वारा हाई टेंश्शन वायर के टावर को स्थापित बिना किसानों के जमीन का उचित मुआवजा किया जा रहा है जिससे प्रशासन एवं किसानों के बीच तनाव व्याप्त है अत: आग्रह है कि सरकार किसानों के जमीन का उचित मुआवजा देकर टावर स्थापित करे ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत एन.एच.-28 पिपरा से कल्याणपुरी जाने वाली आर.डब्लू.डी. पथ जगह जगह गढ्ढे में तब्दील होने से वर्षा के पानी से जल जमाव से आवागमन बाधित है इस क्षेत्र की छात्र छात्राएं स्कूल नहीं जा पा रही है अत: हम सरकार से मांग करते हैं कि उक्त वर्णित पथ को तत्काल जीर्णोद्धार एवं पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहण कर जीर्णोद्धार कराने की मांग करता हूं ।

श्री रामबिशुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला के पीरो प्रखंड के कौरा पांचायत में पीरो कटैया राजवाहा केलाही कोठी से मथुरापुर तक 2.5 कि.मी. स्वीकृत सड़क में 2.3 कि.मी. सड़क का निर्माण हो चुका है । दो सौ मीटर सड़क स्थानीय जनता के आपत्ति के कारण अवरुद्ध है बचे हुए सड़क का निर्माण कराया जाय ।

श्री विद्यासागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के अमौआ पंचायत के मीरगंज परमान नदी घर से नरपतगंज प्रखंड के चकौड़वा तक बना रिंग बांध का पिछले 2017-18 में कटे भाग का मरम्मत आधा अधूरा करने से बाढ़ का खतरा बरकरार है । संवेदक एवं विभागीय लापरवाही के कारण बांध की पूर्ण मरम्मती नहीं की जा सकी । अत: बांध की पूर्ण मरम्मती एवं कार्रवाई की मांग करता हूँ ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, राज्य में एकाएक भारी वर्षा होने से ग्रामीण क्षेत्र के घनी आबादी वाले जगहों में जल जमाव हो रहा है । जल निकासी हेतु बनाये गए सभी नाला जाम है जिसके सफाई हेतु कोई योजना नहीं है । नाला की सफाई कराने तथा जल जमाव से जन जीवन को मुक्ति दिलाने हेतु सरकार शीघ्र निर्देश जारी करे ।

सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवानप : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला के कोढ़ा एवं फलका प्रखंड में मध्य विद्यालय से अपग्रेडेड हाई स्कूल में प्रयोगशाला के सामान के क्रय विक्रय में भारी अनियमितता हुई है । इसकी जॉच की मांग करती हूँ ।

श्री संजय कुमार तिवारी : अध्यक्ष महोदय, बक्सर जिला के सदर प्रखंड बक्सर में होने वाली पंचकोशी परिक्रमा के लिए अहिरौली, नंदाब, भभुअर, बुआॅव, बक्सर को अविलम्ब राशि मुहैय्या करा पंचकोशी यात्रा को अगहन माह के पहले कराने की मैं सदन से मांग करता हूँ ।

डा0 शमीम अहमद : महोदय, दिनॉक 10-0.7-2019 को दानापुर कचहरी में अपराधियों से मुठभेड़ में सिपाही प्रभाकर राज शहीद हो गए । हम सरकार से 50 लाख रुपये उनके पत्नी को पेंशन, बच्चों को पढ़ने का खर्च एवं बाल आरक्षित में बहाली और शहीद स्मारक बनाने की मांग करता हूँ ।

टर्न-08/12.07.2019/बिपिन

अध्यक्ष : श्री रामविलाश पासवान ।

श्री रामविलाश पासवान:अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती प्रखण्ड एवं कहलगॉव प्रखण्ड में ऑगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के चयन में घोर अनियमितता बरती गई है तथा पैसे लेकर चयन की जा रही है ।

अत: सरकार से उक्त प्रखण्डों में ऑगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका की चयन की उच्चस्तरीय जॉच कराने की मॉग करता हूँ ।

श्री सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत डुमरा प्रखंड में शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण होने उपरान्त भी बिचौलियों के बिना लाभुकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

अत: शौचालय निर्माण कार्य की जांच कराकर दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने के साथ ही लाभुकों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान करने की मांग करता हूं ।

श्री विरेन्द्र कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, प्रखर समाजवादी नेता गरीबों और वंचित समाज के अधिकारों के लिए अन्तिम क्षण तक लड़ने वाले बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री मुन्द्रिका सिंह यादव के आदमकद प्रतिमा जहानाबाद जिला समाहरणालय के प्रांगन में लगाने का सरकार से मॉग करता हूं ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिलान्तर्गत जहानाबाद प्रखंड के शकुराबाद-घेजन पथ से कालोपुर भाया उच्च विद्यालय शकुराबाद एवं जामुक पंचायत के परशुरामपुर से धुरू विगहा तक कच्ची सड़क होने से वहां पठन-पाठन करने वाले छात्र/छात्राओं को काफी परेशानी होती है । शीघ्र पक्कीकरण करावें ।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखण्ड स्थित ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत सिमरी से सिंहवाड़ा (भाया हनुमाननगर-रामपुरा) पथ काफी जर्जर अवस्था में है जिससे आवागमन में काफी परेशानी होती है ।

इस पथ को अविलम्ब निर्माण कराया जाय ताकि आवागमन सुचारू रूप से बहाल हो सके ।

श्रीमती भागीरथी देवी: अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा अन्तर्गत दो अनुमण्डल नरकटियागंज एवं बगहा है जो नगर परिषद अंतर्गत है । नगर परिषद में आने वाले दलित महादलित प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं ।

मैं मांग करती हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना उन्हें उपलब्ध कराई जाए।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचना ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा...

अध्यक्ष : नहीं, शून्यकाल नहीं है अब । इनको बोलने दीजिए ।

श्री प्रहलाद यादव: अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : क्या है प्रहलाद जी ?

श्री प्रहलाद यादव : अध्यक्ष महोदय, बेगुसराय जिला में 10 तारीख को पिपरिया प्रखंड के चंदनिया गांव में पांच आदमी नाव दुर्घटना में डूब गया और उसके रास्ते में दुर्घटना होती है और राहत कार्य भागलपुर से आता है 1.00 बजे । यही स्थिति वहां की है । दूसरी घटना 11 तारीख को हलसी प्रखंड में हुआ है लखीसराय में । आठ दलित बेचारा को ट्रक कुचल दिया । 10 से ज्यादा घायल है और सबसे दुर्भाग्य है कि सदर हॉस्पिटल में कोई भी इलाज की व्यवस्था नहीं है । हम गए वहां, सबको कहे, डॉक्टर को बुलाए । उसके बाद तीन सीरियस जो है कल आठ बजे रात को पी.एम.सी.एच. में आया है । तीनों को जमीन पर अभी तक सुलाए हुए है । मुख्यमंत्री जी, पेपर में हम पढ़े हैं आज, माननीय मुख्यमंत्री जी दु:ख व्यक्त किए हैं । कहा कि सारा खर्च जो है हम सरकार के तरफ से दिलवाएंगे । तीन आदमी जो जमीन पर पी.एम.सी.एच. में लेटा हुआ है, क्या उसका कोई उपाय सरकार करेगी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी इसे देखवा लीजिए । सामूहिक दुर्घटना है ।

श्री प्रहलाद यादव: और महोदय, सबसे बड़ी बात है महोदय, डॉक्टर के लापरवाही, प्रशासन के लापरवाही के चलते ...

अध्यक्ष : ठीक है । मंत्रीजी देख लेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : हो गई बात ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष : क्या है ?

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा शहर के लहेरियासराय थाना के 3200 मीटर के अंदर 10 जुलाई को सुबह सात बजे श्री गणेश ज्वेलर्स के घर में 10 से ऊपर अपराधी घुस गए । डकैती की ....

अध्यक्ष : ठीक है, लिखित सूचना सरकार को दे दीजिए ।

अब ध्यानाकर्षण सूचना लिए जाएंगे ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी सूचना पढ़ें ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: अध्यक्ष महोदय, राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 64,47,392 पेंशनधारियों की संख्या है । केन्द्र सरकार ने 1 अप्रैल, 2016 से पेंशन योजना में आधार, DBT के माध्यम से भुगतान की अनिवार्यता लागू कर दी लेकिन 17,82,282 पेंशनधारियों का आधार कार्ड नहीं बनने के कारण वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 से पेंशन के लाभ से वंचित हैं । दिनांक 05.01.2018 से कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना में Pre Paid Card के माध्यम से लाभुकों को भुगतान किया जाना था लेकिन वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के किसी जिले में राशि का भुगतान नहीं किया गया । मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, कबीर अन्त्येष्टि योजना, कन्या विवाह योजना के लाभ से भी बिहार के 1,20,000 लाभुक 2016-17, 2017-18, 2018-19 से वंचित हैं ।

इन्दिरा गॉंधी राष्ट्रीय वृद्धा अवस्था, विधवा, नि:शक्तता पेंशन योजना, लक्ष्मी बाई राज्य सामाजिक सुरक्षा, बिहार नि:शक्तता वृद्धजन पेंशन योजना में 400 रू0 प्रतिमाह दी जाती है । अन्य राज्य जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना में 1000 रू0, हरियाणा में 1800 रू0, आंध्रप्रदेश में 2000 रू0 प्रतिमाह पेंशन की राशि दी जाती है।

अत: पेंशन राशि में वृद्धि करते हुए उक्त वंचित लाभुकों को पेंशन योजना का लाभ देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृट करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, समाज कल्याण ।

श्री रामसेवक सिंह, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पी.एफ.एम.एस. स्वीकृति एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा पेंशनधारियों को उनके नाम से खोल गए बैंक खाते में भुगतान किया जाता है । आधार कार्ड आधारित भुगतान राज्य में लागू नहीं है । अत: आधार कार्ड नहीं बनने के कारण किसी पेंशनधारियों

का पेंशन बाधित नहीं किया जाता है । राज्य में पेंशन भुगतान की वर्तमान प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी है जिसमें ऑनलाइन ससमय बड़े पैमाने पर 63,25,024 पेंशनधारियों का माह मार्च 2019 तक भुगतान किया जा चुका है एवं अप्रैल से जून माह तक का भुगतान प्रक्रियाधीन है । वर्तमान समय में कबीर अंत्येष्टि योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवार के लिए किसी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर उनके अन्त्येष्टि क्रिया हेतु परिवार को तीन हजार रूपया की दर से एकमुश्त सहायता दी जाती है । इस योजना अंतर्गत लाभुकों को त्वरित भुगतान हेतु प्रत्येक पंचायत के खाता में पांच लाभुकों के लिए 15000 रूपया, प्रत्येक नगर पंचायत में 10 लाभुकों के लिए 30 हजार रूपया, प्रत्येक नगर पर्षद में 20 लाभुकों के लिए 60 हजार रूपया, प्रत्येक नगर निगम में 30 लाभुकों के लिए 90 हजार रूपया वन टाइम ऐडवांस के रूप में उपलब्ध कराई गई है ।

अध्यक्ष महोदय, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पंचायत के खाता में उक्त राशि को लाभुकों को भुगतान करने के पश्चात् यथाशीघ्र उसके इंट्री सुविधा ई-सुविधा पोर्टल पर कर दी जाती है लेकिन अविलंब ई-सुविधा पोर्टल के माध्यम से स्टेट लेवेल द्वारा राशि उक्त खाते में रिमुभर कर दिए जाएं जिससे पंचायत, नगर निगम, नगर पंचायत के खाता वन टाइम ऐडवांस की राशि हमेशा उपलब्ध रहे ।

अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना राष्ट्रीय पारिवारिक योजना, कबीर अन्त्येष्टि योजना एवं कन्या विवाह योजना अंतर्गत सभी स्वीकृत लाभुकों को वित्तीय वर्ष 2016-17, वित्तीय वर्ष 2017-18, वित्तीय वर्ष 2018-19 में लाभान्वित किया गया । गत् तीन वित्तीय वर्षों में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्न प्रकार है -

कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना में अध्यक्ष महोदय, 2016-17 में पांच हजार लाख लाभुकों की संख्या है, 16,66,666 और 2017-18 में 4824 है ...क्रमशः

टर्न : 09/कृष्ण/12.07.2019

श्री रामसेवक सिंह,मंत्री(क्रमशः) महोदय, 2016-17 में लाभुकों की संख्या है 16,66,666 और 2017-18 में 4824 इसमें लाभुकों की संख्या है 16,08,000 । महोदय, 2018-19 में व्यय की राशि है 2715.6 लाख और इसमें लाभुकों की संख्या है 45,907 । वैसे ही अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय पारिवरिक लाभ योजना में 2016-17 में जो राशि दी गयी, जो व्यय की गयी है 7989.54 लाख और लाभुकों की संख्या है 39,947 । महोदय, 2017-18 में जो राशि विमुक्त की गयी वह है 7,200 लाख और लाभुकों की संख्या है 36 हजार । 2018-19 में जो राशि व्यय की गयी है उसमें है

837.20 और लाभुकों की संख्या है 4,186 । महोदय, उसी तरह मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना में 2016-17 में 650 लाख और लाभुकों की संख्या है 3250 । उसी तरह 2017-18 में जो व्यय की गयी राशि है 500 लाख और लाभुकों की संख्या है 2500 और 2018-19 में जो राशि व्यय की गयी वह है 39.40 और लाभुकों की संख्या है 197 ।

अध्यक्ष महोदय, उसी तरह से कन्या विवाह योजना में 2016-17 में जो व्यय की गयी राशि है 2,158.54 और लाभुकों की संख्या है 42,739 और इसी तरह कन्या विवाह योजना में 2017-18 में जो व्यय की गयी राशि है 3815.87 है और लाभुकों की संख्या 75,559 है और 2019-18 में जो राशि व्यय की गयी है वह है 4651.39 और लाभुकों की संख्या है 92 हजार 76 ।

अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 80 वर्ष या उससे अधिक आयुवर्ग के बी0पी0एल0 परिवार के वृद्धजन को केन्द्र सरकार द्वारा 500 एवं 60 से 79 के आयु वर्ग को बी0पी0एल0 वृद्ध जन को 200 रूपया केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है और राज्य सरकार द्वारा 200 रूपये का अनुदान दिया जाता है और 45,04,683 पेंशनधारियों में से भारत सरकार 29,96,472 कैप निर्धारित है एवं निर्धारित कैप द्वारा पेंशन की राशि राज्य सरकार को विमुक्त की जा रही है । महोदय, कैप के अतिरिक्त 13,08,211 पेंशनधारियों को पूरी पेंशन की राशि 400 रूपया राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जा रहा है ।

महोदय, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजनान्तर्गत 1,21,410 पेंशनधारियों एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनान्तर्गत 5,58,407 पेंशनधारियों को भी 400 रूपया प्रति माह पेंशन में से केन्द्र सरकार द्वारा 300 और राज्य सरकार द्वारा 100 रूपया वहन किया जाता है ।

महोदय, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत 6,03,065 पेंशनधारियों को बिहार नि:शक्ता पेंशन योजनान्तर्गत 7,66,674 पेंशनधारियों को पूर्णत: राज्य सरकार द्वारा 400 रूपया भुगतान किया जाता है। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजनान्तर्गत भी पूर्णत: राज्य सरकार 60 से 79 वर्ष की आयु वर्ग के वृद्ध को एवं उससे 80 या उससे अधिक वृद्ध को 500 रूपया प्रति माह पेंशन दिये जाने का प्रावधान है । इस योजना में अनुमानित 36 लाख पेंशनधारियों को पेंशन हेतु वित्तीय वर्ष में 1800 करोड़ का व्यय भार संभावित है ।

इस प्रकार सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत अन्य राज्यों की तुलना में पेंशनधारियों की संख्या अत्यधिक है एवं राज्य सरकार द्वारा अत्यधिक राशि का व्यय किया जा रहा है । अत: तत्काल पेंशन की राशि वृद्धि का प्रस्ताव नहीं है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : माननीय मंत्री जी ने विस्तार से उत्तर दिया ।

अध्यक्ष : जितना विस्तार से प्रश्न से अपेक्षा नहीं थी, उतना विस्तार से इन्होंने उत्तर दिया ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : नहीं, महोदय । वही खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात है । इन्होंने योजनाओं का उल्लेख किया है, उसमें कितना भुगतान किया जाना है, लाभुकों का उल्लेख किया है मगर हमने जो स्पेसिफिक पूछा है, मैं माननीय मंत्री जी को बता दूं कि सरकार के द्वारा ई-लाभार्थी पोर्टल जारी है, उसको आज ही मैंने देखा है और उसके मुताबिक महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ई-लाभार्थी पोर्टल में जो आंकड़े दिये गये हैं कि 64,47,392, में 17,82,282 लाभार्थी आधार कार्ड नहीं बनने के कारण तथा जिन लाभार्थियों का CSP और को-ऑपरेटीव बैंक में खाता खुला है, उस बैंक का IFSC CODE नहीं रहने के कारण 1,55,278 लाभार्थियों को, कुल 19,37,560 पेंशनधारियों को वर्ष 2016-17 से अबतक पेंशन के लाभ से वंचित हैं । क्या यह बात सही है ? और इसी में मेरा दूसरा पूरक है कि जो लोग सेवा अधिकार अधिनियम के तहत 2013 से अप्रील, 2019 तक 12,80,347 लाभुकों ने पेंशन के लिये राज्य के 38 जिलों में RTPS काउंटर पर आवेदन जमा की है, जिनमें से 3,48,678 लाभुकों का पेंशन स्वीकृत किया गया है, जिसमें 1,51,140 लाभार्थियों को पेंशन की राशि दी गयी तथा 1,97,538 लाभार्थी अभी भी पेंशन के लाभ से वंचित हैं ।

अध्यक्ष : आप भी माननीय मंत्री जी से कम फिगर नहीं दे रहे हैं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : महोदय, हम भी लंबा-लंबा 3 पूरक प्रश्न पूछ लेंगे । चलिये, इतने का ही जवाब माननीय मंत्री जी दे दीजिये ।

अध्यक्ष : पहले माननीय मंत्री जी ने कहा है और आप ने जो पूछा है, उसी में फर्क है । फर्क यह है कि आपने जिस पोर्टल का हवाला दे कर कहा है कि आधार कार्ड नहीं बनने के कारण पेंशन रोक दिया गया है या नहीं मिल रहा है । मंत्री जी ने कहा है कि आधार कार्ड नहीं बनना, यह पेंशन बंद करने का कोई कारण नहीं होता है, किसी का आधार कार्ड नहीं रहने के कारण हमने पेंशन नहीं रोका है । यह बात माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है । यही कहा है न आपने ?

श्री रामसेवक सिंह,मंत्री : जी ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : महोदय, माननीय मंत्री सिर्फ यही स्पष्ट रूप से बता दें कि जिन योजनाओं का हमने जिक्र किया है, वह जो स्वीकृत है या जो स्वीकृति के पाईप लाईन में है, वे कि तने हैं और जो स्वीकृत हैं, कुल कितने लाभुकों को अबतक अप टू डेट कितना पेंशन भुगतान किया गया है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने बहुत विस्तार से बताया है । हां, आप बोलिये ।

श्री सदानन्द सिंह : महोदय, हम इसी में एक जोड़ देते हैं । माननीय सदस्य श्री सिद्दीकी जी का ठीक प्रश्न है । माननीय मंत्री जी का उत्तर है वह एकतरफा है कि हमने लाभुकों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया लेकिन लाभुकों में कितने छूट गये और इन कारणों से लाभुकों को लाभान्वित नहीं किया गया है, उस के संबंध में माननीय मंत्री जी ने कोई जानकारी नहीं दी है । उसी से सारी जानकारी मिल जायेगी ।

श्री रामसेवक सिंह,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किये हैं, उसको देख लिया जाय। 64,47,392 पेंशनधारियों की बात इन्होंने की है । अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में कहा है कि 63,25,024 लाभुकों का भुगतान मार्च माह तक कर दिया गया है । जो अवेशष है, जो बचे हुये हैं । अध्यक्ष महोदय, इनका कहना था कि 17,82,282 लोग वंचित हैं । मेरा इसमें कहना है कि लाभुकों की संख्या जो अवशेष बची हुई है, इनकी संख्या 1,22,368 ही है । इसका कई कारण है अध्यक्ष महोदय । इसमें कारण है कि कई लाभुकों का खाता ही नहीं खोला गया है और कई लाभुकों की मृत्यु भी हो चुकी है और कई लाभुकों का कई तरह से पेंशन लेने के उसमें गड़बड़ी के चलते भी उनका माईनस हुआ है । इसलिए मेरा स्पष्ट कहना है कि जो लाभुक अबतक बचे हुये हैं, उनका निश्चित रूप से विभाग से निर्देश दिया गया है, उन वंचित लोगों को जल्द से जल्द हम भुगतान कराने की कार्रवाई करेंगे अध्यक्ष महोदय ।

टर्न-10/अंजनी/12.07.19

अध्यक्ष : मंत्री जी का कहना है कि किसी का आधार कार्ड नहीं बनने के आधार पर उसका पेंशन नहीं रोका जा रहा है । दो कारण बता रहे हैं किसी-किसी लाभुक का बैंक से जो टेली कराया मतलब जोड़ा जाता है, लिंक किया जाता है, वह प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण वह रूका हुआ है । जो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि दो लाख बचा हुआ है, उसको हम करा देंगे ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने तो स्वीकार कर लिया...

अध्यक्ष : एक मिनट । इस ध्यानाकर्षण सूचना के निष्पादन होने तक इस सदन की कार्य अवधि बढ़ायी जाती है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : माननीय मंत्री जी ने तो मान ही लिया कि एक लाख कुछ जो आंकड़ा बता रहे हैं, वह अभी बाकी है इस योजना के लाभ से । महोदय, सरकार के द्वारा जो ई-सुविधा रिपोर्ट है और पोटल में जारी है, उसके मुताबिक 11.7.19 का प्रिंट है हमारे पास, आप कहियेगा तो आपको मैं एवेलेबुल करा दूंगा । जिसमें राज्य के 38 जिलों में 48,909 कबीर अन्त्योष्टि के लाभार्थी में 1,756 आवेदनों का सत्यापन प्रखंड

के स्तर पर नहीं हो पाया है, जिसके कारण वे उस लाभ से वंचित हैं, क्या यह बात सही है ? एक तो यह और तीसरा में लास्ट में ही पूछ लेता हूँ या तीसरा पूछने दीजिए ।

अध्यक्ष : आप पूछ ही लीजिए । दोनों का साथ ही जवाब दे देंगे ।

माननीय सदस्य ने सीधा पूछा है कि कबीर अन्त्योष्टि में जो आपने कहा है कि आपके पोटल पर है, जो कुछ लोगों का है, जिनकी मृत्यु की सूचना है, उनके बारे में प्रखंड से सत्यापन नहीं होने के कारण उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है, उन्होंने सिर्फ इतना पूछा है । अगर है तो उसको शीघ्र करा दीजिए ।

श्री रामसेवक सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उस राशि को हमलोगों ने ग्रामपंचायतों में, एक पंचायत में पांच लाभुक का पैसा पंचायत के खाता में दे दिया गया है और उसी तरह मैंने बताया कि नगर पंचायत में दस लाभुक और नगर परिषद में 20 लाभुक और नगर निगम में 30 लाभुकों को पैसा दे दिया गया है उनके खाते में, वहां लाभुकों के खाते में पैसा कबीर अन्त्योष्टि की राशि का देने का प्रश्न ही नहीं है, वह पैसा तो नगद देने का प्रावधान है, क्योंकि मृत्यु होने के बाद वह कफन और लकड़ी के लिए पैसा दिया जाता ाहै, जो बी0पी0एल0 से जुडे हुए परिवार हैं तो उसे खाता में भेजने का प्रश्न कहां है ?

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, मैं अंतिम और तीसरा प्रश्न पूछ रहा हूँ । सरकार तो कह रही है कि नौ गुणा बजट हमने बढ़ाया है और 2 लाख करोड़ से भी ज्यादे का बजट इस बार पेश हुआ है सदन में और उसपर विभिन्न विभाग के डिमांड पर भी बहस हो रहा है तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जब 2 लाख 5 हजार करोड़ से ज्यादे का आपका बजट है तो क्या बजटानुसार आपकी प्राथमिकता इन योजनाओं के लिए नहीं है ताकि जिस तरह से तमिलनाडू, तेलंगना, हरियाणा, आंध्रप्रदेश जैसे राज्यों में जो एक हजार से दो हजार तक पेंशन की राशि दी जाती है, तब जब नौ गुणा बजट आपका बढ़ा है और पैसा आप सरेंडर करते हैं तो इन गरीबों की योजनाओं में राशि का उपबंध करना क्या जरूरी नहीं है ?

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक तो इन्होंने जो पूछा है, उन्होंने उत्तर दे दिया। अब राज्य सरकार ने एक नयी योजना की शुरूआत कर दी है- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, उसके अंतर्गत जिस व्यक्ति की चाहे जो आमदनी हो, पहले का रिश्ता बी0पी0एल0 से था, अब चाहे बी0पी0एल0 हो या ए0पी0एल0 हों, जिनको अगर किसी प्रकार का पेंशन नहीं मिलता है, मान लीजिए कि सरकारी नौकरी में रिटायर किये, उनको पेंशन मिलता है लेकिन बाकी ऐसे व्यक्ति जिनको इस तरह की किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, वैसे तमाम व्यक्तियों को स्त्री हो या पुरूष 60

साल की आयु पूरा करते ही उनको मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन योजना का लाभ दिया जायेगा और अभी इतने कम समय में इसकी शुरूआत की गयी है । मार्च से इसका सर्वेक्षण और लोगों का ऐप्लीकेशन मांगा गया और इसको लॉंच भी कर दिया गया । जब कि हमलोगों का लक्ष्य था कि उसका ऐप्लीकेशन आयेगा, उसकी जांच हो जायेगी, इसके बाद शायद हमलोग इसको शुरू कर पायेंगे, अगस्त महीने से लेकिन पिछले महीने ही इसकी शुरूआत हमलोगों ने करा दी । एक लाख से भी ज्यादा पेंशनधारियों को पेंशन का भुगतान उनके एकाउंट में होने लगा और इसके लिए पूरा प्रचारित किया जा रहा है कि जिनकी भी आयु 60 साल की हो गयी और उनको अगर किसी प्रकार का पेंशन नहीं मिल रहा है तो उस योजना का लाभ लें और इसके लिए हमलोगों का एक अन्दाज है कि 30 लाख से ज्यादा होंगे और उसके लिए 1800 करोड़ रूपये की जरूरत अतिरिक्त पड़ेगी । अब तक जितने पेंशन योजनाओं में समाज कल्याण विभाग के द्वारा चाहे केन्द्र की योजना हो या राज्य की योजना हो, केन्द्र की जो योजना होती है, उसमें केन्द्र सरकार एक हिस्सा देता है, राज्य सरकार को एक हिस्सा देना पड़ता है, इसको मिलाकर कई हजार करोड़ रूपये उसमें खर्च होते हैं लेकिन उसके अलावे जो बचे हुए हैं, जिसका आकलन 2011 की जनगणना के आधार पर यह किया गया तो यह आकलन आया है कि लगभग एक वर्ष में 1800 करोड़ रूपया एडीशनल की आवश्यकता पड़ेगी, अतिरिक्त राशि की आवश्यकता पड़ेगी, इसको ध्यान में रखते हुए ही इस स्कीम को लॉंच कर दिया गया, अब कोई नहीं है । आप दूसरा पेंशन की राशि के बारे में पूछ रहे हैं और उदाहरण किसका दे रहे हैं सिद्दिकी साहेब, वित्त मंत्री भी रहे हैं और इसमें जितने लोग का नाम देख रहे हैं, अवधेश जी पता नहीं चले गये हैं । हम देख रहे हैं कि आलोक कुमार मेहता, सहकारिता मंत्री रहे हैं, आप खुद वित्त मंत्री रहे हैं, गफूर साहेब भी मंत्री रहे हैं, अभी तो नहीं हैं, गायब हैं, हैं नहीं, आप जो सवाल उठा रहे हैं और अपनी तुलना आप कर रहे हैं तमिलनाडु से, तेलंगाना से, हरियाणा से और आंध्रप्रदेश से । उनकी आमदनी क्या है ? पर-कैपिटा इनकम क्या है और आपका पर-कैपिटा इनकम क्या है, पर-कैपिटा इनकम का ग्रोथ और जी0डी0पी0 का ग्रोथ, आप वित्त मंत्री रहे हैं तो वित्त मंत्री के रूप में आपको तो यह सब सोचकर लाना चाहिए था पहले कि हम इस स्थिति में हैं कि यह राशि बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं आपने । आपको आज हम बता देते हैं कि जो पर-कैपिटा इनकम है अपने बिहार का, वह 38,000 से थोड़ा ज्यादे है, 38,800 इसके आस-पास है यानी 40 हजार से भी कम, एवरेज जो देश का पर-कैपिटा जो इनकम है, उससे काफी कम है, इसलिए तो हमलोग इस आधार पर विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते हैं तो ऐसी स्थिति में

जिन राज्यों का आप नाम ले रहे हैं, इनका ऐवरेज से ज्यादा है तो जो राज्य जिसके यहां पूरी सम्पत्ति है और जो विकसित राज्य की श्रेणी में है, आप उससे अपने पिछड़े राज्य की तुलना, पिछड़े राज्य जो हैं, क्या कर सकते हैं ? यह सवाल उठा सकते हैं लेकिन आप इसको एक्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं । अभी तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमलोगों का सामर्थ्य है, जो हमलोगों की आर्थिक स्थिति है, उसके आधार पर तो हमलोगों ने शुरू कर दिया कि सबको मिलेगा लेकिन आप तुरंत कहियेगा कि इतना राशि बढ़ा दो तो जरा जोड़ लीजिए, वित्त मंत्री रहे हैं, कितना हजार करोड़ रूपये की जरूरत पड़ेगी और वह पैसा कहां से लायेंगे और जो बजट बढ़ रहा है तो कोई एक काम में, इसके चलते बढ़ रहा है, बजट बढ़ रहा है तो रोड बन रहा है, कई तरह के और काम हो रहे हैं, पुल बन रहा है, एक नहीं विकास की अनेक योजनायें हो रही हैं, डेवलपमेंट का काम हो रहा है । बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, इर्रीगेशन का काम, हर तरह का काम, एग्रीकल्चर रोड मैप है, उसको इम्पलीमेंट करने के लिए जो काम करना है तो इतनी तरह की योजनायें हैं, जिस पर राशि खर्च होगी । तो इसलिए यह सोचना कि भई दो लाख करोड़ रूपये का बजट आ गया वार्षिक तो आप यह कर दीजिए । यह संभव है ? विकसित प्रदेश के बराबर आपकी राशि है, उनका पर-कैपिटा इनकम और आपका पर-कैपिटा इनकम क्या है तो ऐसी स्थिति में हम नहीं समझते हैं कि इच्छा रखना तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन इस पर क्या अमल अभी कर सकते हैं । जब तक आप एक विकसित प्रदेश नहीं बन जायें, तबतक इन चीजों में आप कितनी राशि बढ़ा सकते हैं और इतनी ऐसी स्थिति में भी तब भी यह निर्णय ले लिया गया कि 60 साल के उम्र वाले हर स्त्री-पुरूष को जिनको अन्य प्रकार का कोई पेंशन नहीं मिलता है, ए0पी0एल0 हों, बी0पी0एल0 हों, सबको इवेन ए0पी0एल0 वाले को जो इच्छुक होंगे, हम जबर्दस्ती तो देंगे नहीं, वे एप्लाई करेंगे, उनका एकाउंट खुलेगा और उसके बाद उनके एकाउंट में ट्रांसफर हुआ है । एक दिन बटन दबाकर सारे के एकाउंट में पैसा गया तो यह काम किया जा रहा है । तो कृपा करके इन चीजों पर नहीं, आपने पहले जो कहा कि कौन छूट गया है, वह सब बात अपनी जगह पर है, उसको समाज कल्याण विभाग जरूर देखेगा कि किसी कारण से जो वैलिड है, जिसको मिलना चाहिए, अगर उसको नहीं मिल रहा है तो उसपर पूरी कार्रवाई करें ।

क्रमशः.....

टर्न-11/राजेश/12.7.19

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, क्रमशः इसको मोनेटर किया है हमने बहुत और मोनेटर करके यहाँ बढ़ा है कि इतने रुप तक वह पहुंच गया है, अगर और इसमें जो भी होंगे उपयुक्त व्यक्ति जिनको मिलना चाहिए पुरानी योजनाओं के कारण, उनको जरुर मिलेगा और उनको बकाया जितने दिनों से नहीं मिला है, बकाये राशि का भी भुगतान होगा ।

श्री अब्दुल बारी सिदिदकीः महोदय-महोदय, ...(व्यवधान)

अध्यक्षः अब क्या है, अब तो हो गया ।

श्री अब्दुल बारी सिदिदकीः महोदय, चूंकि मुख्यमंत्री जी ने हमारे ध्यानाकर्षण को गंभीरता से लिया है और उन्होंने यह भी बताया कि वैसे व्यक्ति जो किसी तरह की योजना से छूट गये हैं, उनके लिए एक नयी योजना चालू की गयी है । महोदय, जहाँ तक उन्होंने कहा है कि जो अन्य विकसित राज्य हैं, उनकी तुलना में जो हमारा गरीब राज्य है उसके बजट का जो आकार बढ़ा है वह अन्य योजनाओं के लिए बढ़ा है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जरुर यह जानना चाहूंगा कि जो बजट है हमारा तो उसमें जब भी कोई योजना हम बनाते हैं, तो अपना पैर उतना ही फैलाते हैं, जितनी बड़ी चादर होती है, तो मान लीजिये कि अपनी जो प्रॉयरिटी डिफरेंट मद में फिक्स की है, तो महोदय उसीतरह से जो ये योजनाएँ हैं, तो चूंकि पैसा आप कितना लैप्स करते हैं हर साल, तो गरीबों के लिए अगर योजना में लाभ बढ़ाया जाय या पहुंचाया जाय, तो यह तो मांग करना हमारा दायित्व है ।

अध्यक्षः ठीक है । आपने मांग किया, सरकार ने जवाब दिया और श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव जी का ध्यानाकर्षण पुट हुआ, जो अगले दिन तक के लिए स्थगित रहेगा ।

अब सदन की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-12/सत्येन्द्र/12-7-19

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

वित्तीय कार्य

श्री भाई वीरेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, आज पथ निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर डिमांड है और सत्ता पक्ष की ओर से मात्र 5 ही मंत्री उपस्थित हैं ।

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री: मैं पटना साहिब से आता हूँ महोदय और गुरू गोविन्द सिंह जी का वह जन्म स्थान है महोदय, सवा लाख से एक लड़ाऊं तब उनका नाम गुरू गोविन्द कहलाया, हम उस जगह से आते हैं, एक ही पर्याप्त है आपके लिए, बाकी की क्या जरूरत है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, पथ निर्माण विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए समय दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय जनता दल	60 मिनट
जनता दल यूनाईटेड	52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	41 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	19 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	01 मिनट
निर्दलीय	03 मिनट

माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' पथ निर्माण विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 70,05,56,28,000/-(सत्तर अरब पांच करोड़ छप्पन लाख अट्ठाइस हजार) रू0 से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष: इस मांग पर माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, श्री ललित कुमार यादव, श्री सदानन्द सिंह, श्री भोला यादव, श्री महबूब आलम, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री रामदेव राय से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो व्यापक हैं जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी का प्रस्ताव प्रथम है, अतएव माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव ।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'इस शीर्षक की मांग 10/-से घटायी जाय।'

अध्यक्ष महोदय, इनका जो 2018-19 के अपेक्षा 2019-20 का जो प्रस्तावित बजट है महोदय, उसमें 1.05 प्रतिशत का मात्र बढ़ोत्तरी है महोदय । महोदय, आज पथ निर्माण विभाग के अनुदान मांग पर सदन में वाद विवाद है जिस पर सदस्य अपनी अपनी राय रखेंगे । महोदय, उसी संबंध में मैं भी अपनी राय यहां रखना चाहता हूँ । बजट महोदय या अनुदान मांग, ये तो संसदीय प्रणाली का भाग है ,प्रस्तुत होता ही रहता है लेकिन उस अनुदान मांग में जो आप सदन से अनुमति देते हैं राशि खर्च करने की, वह महोदय प्रावधानित राशि का नियमानुसार क्रमवद्ध तरीके से खर्च करने का उत्तरदायित्व जो सरकार की होती है उसमें यह वर्त्तमान सरकार केवल आश्वासन और जुमले में विश्वास करती है महोदय, लगता है कि धरातल पर वह सही रूप से नहीं उतर पाता है । महोदय, आज पथ निर्माण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर वाद विवाद हो रहे हैं । पथ की महत्ता महोदय हमलोग समझते हैं कि किसी राज्य का पथ और राज्य का जो आईना, एक तरह से कह सकते हैं जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से औद्योगिक रूप से पथ का जो विकास की गति और पथ की जो गुणवत्ता और पथ की महत्ता है महोदय तो सारी चीज को आकलन का समाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, औद्योगिक क्षेत्र का उस राज्य का एक पैमाना होता है महोदय। महोदय, सड़क निर्माण हो रहे हैं, यह अच्छी बात है महोदय, माननीय मंत्री जी को हम इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं लेकिन सही तरीके से निर्माण हो महोदय, इस पर भी इनकी निगरानी मंत्री महोदय के सरकार की होनी चाहिए महोदय । महोदय, जब तेजस्वी जी उपमुख्यमंत्री थे पथ निर्माण विभाग के हैसियत से थे तो समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने की नियत तिथि तय रहती थी और उसपर ही प्रोजेक्ट को पूरा किया जाता था महोदय, उस समय उदघाटन की तिथि नियत होती थी और उससे होता था महोदय कि समय का बचत भी होता था और जनसरोकार का काम भी जनता के बीच चरणबद्ध तरीके

से पहुंचाया जाता था । महोदय, सड़क सुरक्षा मानकों की मोनेटरिंग हेतु रोड सेल्फी सेल का गठन किया गया था जो लगभग वह समाप्ति की दिशा में है जो तात्कालीन पथ निर्माण मंत्री थे और इस तरह से तेजस्वी जी जो थे, अनेक तरह के ये फैसले लिये थे, टेंडर के भी कार्य का फाईल जो मंत्री के पास आता था, उन्होंने वह भी निर्णय लिया कि मंत्री के पास वह फाईल नहीं आवे । महोदय, हम माननीय मंत्री, नन्द किशोर बाबू से, ये तो शेरो शायरी के माहिर हैं और इनका जिस तरह से ये अपनी पार्टी में, अब नन्द किशोर जी आगे हैं कि सुशील मोदी जी आगे है, जैसे इस प्रतियोगिता में खड़ा आगे रहते तब यदि बिहार का पथ, यदि बिहार के उस दिशा में ये काम किये रहते तो हमलोगों को प्रसन्नता होती लेकिन पथ का महोदय, पथ की ये हालत है पूरे बिहार का, हम आपको आईना दिखाना चाहते हैं महोदय, इनका सिवान-छपरा मुख्य सड़क है, उसकी ओर और हम अपने क्षेत्र की जो एक मनीगाछी-घनश्यामपुर सड़क है महोदय, माननीय मंत्री जी इसी सदन में विभाग की गलती से, भूल से 0-5 कि0मी0 महोदय छूट गया था और 6-20 कि0मी0 हो गया था, माननीय मंत्री जी ने कहा 2017 में ही कहा कि इसको मैं अधिगृहित करता भी हूॅ और कार्य भी हम करायेंगे । लेकिन उसमें जाईएगा तो सबसे बड़ा दोषी आप है, ये 14 साल का 15 साल का एन0डी0ए0 का जो सरकार रहा है, सबसे लंबे अर्से तक आप मंत्री रहे हैं लगभग 12 साल से, 11 साल से आप मंत्री रहे हैं, ये जिम्मेवारी आपकी है, इतने लंबे अर्से तक कोई नहीं रहें । लोग आये किन्हीं के ध्यान उस पर आया, नहीं आया आये गये, प्रेम कुमार जी भी थे कुछ दिन के लिए थे सिद्दिकी साहब बहुत पहले रहे हैं, ये 15 साल का एन0डी0ए0 का जो काल खंड है, मैं उसका जिक्र करता हूॅ, महोदय सबसे लम्बे, इलियास हुसैन साहब बहुत पहले थे, जब आप नहीं थे इस सदन के सदस्य तब वे थे । महोदय, तो लम्बे अर्से से, लम्बे काल खंड तक नन्दकिशोर बाबू मंत्री रहे हैं इसलिए पथ की दुर्दशा का, यदि असली हकदार हैं तो यही हैं दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है । आज अपने क्षेत्र मनिगाछी-घनश्यामपुर कह रहे थे, जीरो से साढ़े पांच कि0मी0 छोड़ दिया है महोदय, विभाग की तकनीकी भूल हुई होगी गलती से और 6 से 20 कि0मी0 जो शुरू कर दिया, इन्होंने कहा 2017 में फिर हमलोग 2018 में दूसरे माध्यम से इसी सदन में एक प्रश्न लाये कि उस सड़क पर यातायात अवरूद्ध है माननीय मंत्री जी कम से कम उसमें मोटरेबुल करवा दीजिये।

(क्रमशः)

टर्न-13/मधुप/12.07.2019

...क्रमशः...

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, दो-दो बार, मंत्री जी कहें तो हम इनको आश्वासन संख्या भी दे देंगे कि इनका क्या आश्वासन है । 2017 में भी और 2018 में भी, दो बार आश्वासन- एक बार अधिग्रहित करने का, पिछले बार इन्होंने कहा कि जो वह रोड है उसको हम देखेंगें । महोदय, दो-दो आश्वासन है । इसी तरह से चिकनी से देवना सड़क है, उसमें भी आश्वासन है, वह भी 2017 में आश्वासन है । दोनों पथ की यह स्थिति है कि यातायात बंद है । पथ निर्माण मंत्री जी, जितना भी आप कॉलर टाईट कर लीजिये, शेरो-शायरी पढ़ लीजिये लेकिन आपका आश्वासन झूठा है । झूठा आश्वासन सिर्फ सदन का अपमान नहीं है, सभी माननीय सदस्यों का अपमान है । आप 2017 में आश्वासन देते हैं, 2018 में आश्वासन देते हैं । अध्यक्ष महोदय, हमलोग आसन से आग्रह करेंगे कि सरकार को एक पत्र लिखा जाय, इनको आश्वासन मंत्री बनाया जाय । 2017 में आश्वासन, 2018 में आश्वासन और इनका अभी पथ निर्माण विभाग का 100 से उपर आश्वासन विधान सभा में लम्बित है । किस वित्तीय नियमावली की बात करते हैं ? जो सदन में आप ही का एश्योरेंस है, कोई दूसरे माननीय मंत्री का एश्योरेंस नहीं है । आज छोटा-सा बारिश हुआ है महोदय, रास्ता बंद है, हमलोग क्षेत्र नहीं जा सकते हैं । शर्म करना चाहिये, 2017 में आश्वासन होता है, 2018 में आश्वासन होता है, आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन और मंत्री जी जुमलेबाजी और शेरो-शायरी में विश्वास करते हैं । अब देखियेगा माननीय मंत्री का जब उत्तर होगा तो ऐसा शेरो-शायरी पढ़ेंगे, लगेगा कि कोई यहाॅं पर मुशायरा हो रहा है । लेकिन महोदय, आसन सर्वोपरि है, मंत्री नहीं बड़ा होता है, सदन और आसन बड़ा होता है । माननीय मंत्री जी जिस तरह से झूठा आश्वासन सदन में देते हैं, हमलोग एक चीज आसन से आग्रह करेंगे कि इसपर आसन कोई निर्णय ले, नहीं तो आश्वासन मत दिलवाइये, महोदय । सदन में यदि आश्वासन दिलवाते हैं तो आश्वासन समिति भी बनी हुई है, कितना कार्यान्वयन होता है, देखवा लीजिये । आप जलवायु परिवर्त्तन, जल संचय और पर्यावरण पर अभी आप एक सेमिनार बुला रहे हैं । महोदय, आप एक सेमिनार यह क्यों नहीं बुलाते हैं कि सदन की कमिटी में किस विभाग के कितने लम्बित मामले हैं । 100-100 आश्वासन हैं पथ निर्माण विभाग का, मंत्री जी कह रहे हैं कि मेरा पथ चमक रहा है । एक बार आप देख आइये महोदय, बिहार के पथ निर्माण विभाग के सड़कों की क्या हालत है । ट्रैफिक बंद है, महोदय । हम यही मनीगाछी-घनश्यामपुर बताते हैं, चिकनी से देवना बताते हैं, मुरिया से सोनकी बताते हैं, सब आश्वासन है आपका । पथ निर्माण विभाग कहता है कि हम क्यों करें ? अभी

हमने टेन्डर नहीं किया है । ग्रामीण कार्य विभाग कहता है कि मैं क्यों करूं ? वह तो पथ निर्माण विभाग ने हमसे एन0ओ0सी0 ले लिया, हैंड-ओवर ले लिया । महोदय, जनता का क्या कसूर है ? नन्दकिशोर बाबू को पटना सिटी और भारतीय जनता पार्टी का जहॉं-जहॉं एम0एल0ए0 है, वही क्षेत्र इनको दिखाई पड़ता है । ये बिहार सरकार के मंत्री हैं, बिहार की जनता द्वारा मंत्री हैं या नन्दकिशोर बाबू केवल भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं ? ये बताना होगा इनको । यदि आप भारतीय जनता पार्टी के केवल मंत्री हैं, बिहार सरकार के मंत्री नहीं हैं, यह बिहार की जनता के लिए आप उत्तरदायी नहीं हैं तो आपको जवाब देना चाहिये ।

महोदय, हमलोग क्षेत्र नहीं जा रहे हैं । एक इसी तरह से महोदय, मुरिया में इनका नाला निर्माण का, इनका अनुमोदन भी प्राप्त है, 20 हजार गॉंव की आबादी है और पथ निर्माण विभाग का सबसे पुरानी सड़क है, दोनों तरफ मस्जिद है, लोग हैं, दो दिन की बारिश में सबके घर में पानी चला गया है । महोदय, हमलोग क्षेत्र भी जायं तो कैसे जायं । ये कह दें कि केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही अपने क्षेत्र जायं, दूसरे पार्टी के लोग जो जीतेंगे उनके क्षेत्र में काम नहीं होगा, हमारा कमीटमेंट है भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के लिये, भारतीय जनता पार्टी को जो वोट दिया है उसके लिये । लेकिन उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी होंगे, वे भी उस सड़क से आते होंगे, वे भी वहॉं अवस्थित होंगे, उनके भी वोट का ये अपमान कर रहे हैं ।

महोदय, मेरी पार्टी की ओर से बहुत माननीय सदस्य बोलने वाले हैं लेकिन हम....

अध्यक्ष : उनकी तो आपने मदद की ही है । जो और लोग बोलने वाले हैं, आप लगातार उन्हीं की मदद कर रहे हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : हॉं, लगातार मदद करते हैं, महोदय । मैं समय-सीमा का उसमें ध्यान रखा हूँ।

अध्यक्ष : आपने जो समय का आवंटन भेजा है, उसमें आपके लिए समय शून्य मिनट है ।

श्री ललित कुमार यादव : ठीक है, महोदय । शून्य मिनट है लेकिन आप भी समझते हैं ।

अध्यक्ष : बिल्कुल । इसीलिये तो आप बोल रहे हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : जो मेरे बोलने के बाद समय बचेगा, आप उसी में से सभी माननीय सदस्यों को दे देंगे

अध्यक्ष : ठीक है । एकदम । आसन आपसे पूर्ण सहयोग करेगा ।

श्री ललित कुमार यादव : आसन मर्यादा समझता है, महोदय ।

महोदय, जिस तरह से इनके सड़क की हालत है, हम कटौती प्रस्ताव....

अध्यक्ष : ....दुख के साथ लाये हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : दुख के साथ लाये भी हैं और लाना मेरा कर्त्तव्य है । हम महोदय, विपक्ष में हैं, हमारा दायित्व है सरकार को आईना दिखाना । सरकार हर मोर्चे पर विफल है । जो पथ निर्माण विभाग का कार्य है, एक गुणवत्ता का सवाल करते हैं । हम दो उदाहरण देना चाहते हैं, आप देखवा लीजिये । अललपट्टी गुमटी से गंज चौक तक - दो साल हुआ है माननीय मंत्री जी, उस पथ के बने हुये और वहीं धोई चौक से खुटवारा - मात्र एक ही साल हुआ है, शायद आप मंत्री रहते तो वह भी पथ नहीं बनता, ललन सिंह थे और वह देखे, बाईपास है, तो उसके महत्व को देखा, ललन सिंह पथ निर्माण मंत्री थे, उन्होंने सदन में मेरे वक्तव्य पर, उसी वक्त फोन किया और दूसरे दिन रोड में हाथ लग गया, ललन सिंह, मंत्री थे । आप इन दोनों रोड की जॉंच करा लीजिये, ललन सिंह मंत्री थे । हम धन्यवाद देते हैं उनको ।

अध्यक्ष : मतलब, आप क्या कह रहे हैं ? आपका काम पूर्व मंत्री ने कर दिया, इसकी ये जॉंच करा लें ?

श्री ललित कुमार यादव : यह नहीं कह रहे हैं । महोदय, पूर्व मंत्री को धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने सदन की मर्यादा को रखा, गम्भीरता से लिया और देखा कि रोड आवश्यक है तो दूसरे दिन ही, आपका नहीं जो आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन, कितना आश्वासन, आपको आश्वासन मंत्री क्यों नहीं बनाया जाता है ? हमलोग माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि एक विभाग और दीजिये, इनको आश्वासन मंत्री बनाइये ।

अध्यक्ष : ललित जी, आपको सरकार ने या मंत्री जी ने जो आश्वासन दो साल पहले दिया, फिर पिछले साल दिया, अगर वही आश्वासन इस बार भी देते हैं तब तो बात स्पष्ट है न कि सरकार अपने बात पर कायम रहती है ।

श्री ललित कुमार यादव : कायम है । महोदय, आसन से भी आप एक निर्देश दीजिये कि इनको सरकार आश्वासन मंत्री बना दे । ऐसा आश्वासन मंत्री बनावे कि कभी वे कामयाब न हों ।

अध्यक्ष : उससे आपकी समस्या का समाधान होगा ?

श्री ललित कुमार यादव : नहीं, हमको चिन्ता है, सदन की भी गरिमा है ।

अध्यक्ष : फिर तो आपको हर बार आश्वासन देते जायेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : सदन की भी गरिमा होती है, महोदय । आपने संसदीय प्रणाली में आश्वासन समिति बनाया है । आज आश्वासन समिति की क्या हालत है, अध्यक्ष की हैसियत से यह भी अधिकार है मोनिटरिंग करने का ।

हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि आश्वासन दीजिये तो उसको पूरा करिये । यदि आप आश्वासन से लम्बित कार्य नहीं करा सकते हैं तो नहीं दीजिये । माननीय मंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि जो दो पथ के बारे में कहा है, मनीगाछी-बोहरवा 0-5.5 कि0मी0, दूसरा तारसराय से सोनकी, इन पथों में यातायात अवरूद्ध हो गया है, मंत्री जी । हमलोग क्षेत्र नहीं जा सकते हैं । हम आसन से आग्रह करते हैं कि कम से कम उसको मोटरेबुल करा दीजिये ताकि ट्रैफिक चालू हो जाय । पथ निर्माण विभाग की यह हाल होगी, ग्रामीण कार्य विभाग को कहते तो कुछ कर भी सकते । वे कहते हैं कि हमने पथ निर्माण विभाग को दे दिया । मंत्री जी, आपसे हम आग्रह करेंगे कि जॉच करवा लीजिये कि जो मैं कह रहा हूॅ उसमें सत्यता है या नहीं । यातायात बंद है कि नहीं । यदि बंद है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चलते हैं, जनता दल यूनाइटेड के भी लोग चलते हैं, समस्त बिहारवासी चलते होंगे ।

...क्रमशः...

टर्न-14/आजाद/12.07.2019

..... क्रमशः .....

श्री ललित कुमार यादव : आप इसको कृपया जनहित में जनसरोकार के मामले को लेकर जनता के लिए कम से कम मंत्री में जैसे आप शेरो-शायरी करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, कॉलर टाईट करते हैं, कम से कम दो दिन में आप इसको मोटरेबुल करा दीजियेगा तो हम समझेंगे कि बिहार सरकार के मंत्री श्री नन्दकिशोर बाबू में कुछ इच्छाशक्ति कार्य करने की है तो बिहार तरक्की करेगा । महोदय, ...

अध्यक्ष : ललित जी, पूरे मंत्रिपरिषद् में एक-दो मंत्री तो हैं जो शेरो-शायरी करते हैं । आपकी क्या इच्छा है ?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, कुछ काम भी होना चाहिए । केवल शेरो-शायरी से ...

अध्यक्ष : यानी आपका कहना है कि केवल शेरो-शायरी न हो, काम भी हो ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, काम ज्यादा हो, काम की प्राथमिकता हो और मंत्री जी को तारसराय मुरीया नाला का कहें यानी सबके घर में पानी है । अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगे क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग से दूरी कितना है । लेकिन माननीय मंत्री जी, आपसे मेरा निवेदन है कि आप इसको भी देखवा लीजिए, सबके घर में पानी है ।

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : आप मो0 नवाज आलम से पूछ लीजिए न, आप ही के पीछे बैठे हुए हैं, आपके ही पार्टी के हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : हम भी देख रहे हैं । आप पता कर लीजिए कि एक गांव की आबादी 20हजार है, 2-3 पंचायत के गांव हैं और पी0डब्लू0डी0 की सड़क है, पी0सी0सी0 सड़क बनी हुई है, लेकिन घर लोगों का नीचा हो गया है । नाला नहीं होने के कारण लोगों के घर में, मस्जिद में , नमाजी को नमाज पढ़ने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी से ऊपर उठकर उसको देखिए । मस्जिद-मंदिर में आप नहीं बंट जाईए । अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत, बहुत आभार प्रकट करता हूँ .....

अध्यक्ष : समय तो आपका ही था, आपने अपने लिए ले लिया ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आपने दिया, उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

अध्यक्ष : ठीक है, धन्यवाद । माननीय सदस्य श्री मुजाहिद आलम ।

श्री मुजाहिद आलम : अध्यक्ष महोदय, माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नन्दकिशोर यादव द्वारा जो 70,05,56,28,000/-रू0 की जो अनुदान मांग प्रस्तुत की गई है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और विपक्ष द्वारा जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसके विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

महोदय, आप सब लोग जानते हैं कि रोड, आर0सी0डी0 जो पहले पी0डब्लू0डी0 के नाम से जाना जाता था, आर0सी0डी0 इन बिहार प्लेज इम्पोंटेंट एंड पायलोट रोल फॉर द सोसियो इकोनोमी एजुकेशनल एंड इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट ऑफ बिहार, आप जब आंकड़ों पर गौर करेंगे तो बिहार में 65 फिसदी लगभग गुड्स सामानों की जो ढुलाई होती है, वह रोड के माध्यम से होती है । वही पर पैसेंजर जो होते हैं, उसका 90 प्रतिशत से ज्यादा पैसेंजर बिहार में सड़क मार्ग से सफर करते हैं, इसीलिए पथ निर्माण विभाग और सड़कों का बिहार के सोसियो इकॉनोमी एजुकेशनल एंड इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान है । हमारे नेता श्री नीतीश कुमार ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने एक लक्ष्य रखा कि हम बिहार के जो सबसे दूर का जिला है, दूर का स्थान है और वह स्थान किशनगंज जिला है, जहां से मैं खुद बिलौंग करता हूँ, उसको राजधानी पटना में 6 घंटे में पहुँचाना है और इस लक्ष्य को बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग ने प्राप्त कर लिया है । हमारे नेता नीतीश कुमार और माननीय मंत्री श्री नन्दकिशोर यादव जी ने अब लक्ष्य रखा है कि अब जो बिहार का सबसे दूर का जिला किशनगंज है, उसको 5 घंटे में राजधानी पहुँचाने का काम करेंगे जिसके लिए जितने भी इससे कनेक्टींग रोड है, स्टेट हाईवे है, सबको स्ट्रेन्थिंग रेजिग, स्ट्रैन्थिंग का काम चल रहा है । मैं जब आज से 20 वर्ष पहले पटना पढ़ने के लिए आता था तो उस वक्त बस से 12 से 14 घंटे पटना आने में समय लगता था और

आज हम 5 से 6 घंटे में किशनगंज से राजधानी पटना पहुॅंच जाते हैं । यह बिहार सरकार की और हमारे नेता नीतीश कुमार की बहुत बड़ी उपलब्धि है । अभी जो बिहार में पथ निर्माण विभाग द्वारा अनेकों योजनायें चलायी जा रही है, जैसे गंगा पथ, यह 20.5 कि0मी0 की जो सड़क है, जो फोरलेन का है और इस सड़क पर बहुत तेजी से काम चल रहा है । जब यह सड़क बनकर तैयार हो जायेगा तो मैं समझता हूॅं कि यह बिहार और पटना राजधानी का एक पर्यटन को भी बढ़ावा देगा । जिस तरह से आज मुम्बई में लोग मेरीन ड्राइव समुद्र के किनारे जिस तरह से रोड बना हुआ है, उसका एक दूसरा रूप होगा । उसी तरह से एम्स, दीघा रोड, इसी तरह और बहुत सारी सड़कों का और पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है । हमारे यहां पर बोर्डर पर एक रोड जो पथ निर्माण विभाग के तरफ से चल रहा है, जो एन0एच0-28बी पश्चिमी चम्पारण से प्रारंभ होकर पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी मधुबनी, सुपौल, अरिया, किशनगंज जिला के बंगाल सीमा में गलगलिया तक जो है, वह पहुॅंचता है और इस सड़क का काम पहले भू-अर्जन के कारण उसमें थोड़ा विलम्ब हो रहा था, अब इस कार्य में बहुत तेजी से हो रहा है और इस सड़क के बन जाने से बिहार के किशनगंज सहित अन्य जितने भी जिलों से यह सड़क गुजरती है, उत्तरप्रदेश और दिल्ली जाने में मैं समझता हूॅं कि 8 से 10 घंटे कम समय लगेगा । अभी पथ निर्माण द्वारा जो उसका बिहार राज्य पुल निर्माण निगम है, पुल निर्माण निगम द्वारा 2170 पुलों का निर्माण कराया जा चुका है, 232 पर कार्य चल रहा है । पथ प्रमंडल द्वारा 91 पुलों का निर्माण कराया जा चुका है, मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत 5135 पुलों का निर्माण कराया गया है । यह योजना पहले बन्द हो गई थी लेकिन फिर से इसे माननीय मुख्यमंत्री ने चालू करने का निर्णय लिया है । 34 आर0ओ0बी0 रेलवे ओवरब्रीज बन रहे हैं, जिसमें से 31 का काम पूर्ण हो चुका है, 3 पर काम चल रहा है ।

(इस अवसर पर श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह ने माननीय सभापति का आसन ग्रहण किया)

हमारे किशनगंज जिला जो बिहार के सबसे दूरी पर है और यहां पर माननीय मंत्री नन्दकिशोर जी भी बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि किशनगंज जिला की जितनी भी पथ निर्माण विभाग की समस्या है, उसपर विशेष ध्यान देकर किशनगंज जो बहुत दूर का जिला है, उसको नजदीक लाने का काम करेंगे । डी0बी0बी0पी0टी0 सड़क जो पथ निर्माण की एक सड़क है, जिसपर अभी काम चल रहा है और उस सड़क पर अभी कनकनी नदी से कटाव हो रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आज ही सबेरे से कनकनी के जलस्तर में वृद्धि हुआ है, सैंकड़ों ग्रामिणों का फोन आ रहा है कि वहां नदी का कटाव रोड को कर रहा है लेकिन विभाग में

उसका प्रोटेक्शन का कार्य लंबित है, जिस कारण कंट्रेक्टर द्वारा काम नहीं किया जा रहा है । उसी तरह से एस0एच0-99 जो बी0एस0आर0डी0सी0एल0 के अन्तर्गत है, उसके प्रबंध निदेशक भी यहां बैठे हुए हैं, जो हमारे किशनगंज जिले से ही आते हैं । यह सड़क वायसी में एन0एच-31 एक्सप्रेसवे से नेपाल सीमा को बोर्डर रोड में जोड़ने का काम करता है । इसी रोड में एक बरबट्टा है जो किशनगंज जिले की दूसरी सबसे बड़ी मंडी है, उस बरबट्टा मार्केट में 12 महीना पानी लगा रहता है, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इसका डी0पी0आर0 बन रहा है, बरबट्टा मार्केट में जो वाटर लॉगिंग की समस्या है, उसका समाधान के लिए उसपर नाला बनवाने का काम करेंगे । हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने 2010 के चुनाव में टेढ़ागाछ किशनगंज जिला का एक प्रखंड है, जो नेपाल और अररिया जिला से घिरा हुआ है । वहां जाने के लिए कोई भी सीधा सम्पर्क नहीं है। 2017 के बाढ़ में बाढ़ राहत के लिए जिला प्रशासन के लोगों को नेपाल होकर जाना पड़ रहा था । वहां पर लौचा नदी में एक पुल बन रहा है बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा लेकिन पुल का काम, एप्रौच का काम पिछले दो महीने से रूका हुआ है । जमीन मालिकों के जमीन का जो भू-अर्जन किया गया है, उन लोगों के द्वारा पैसे की मांग की गई है तो मैं समझा हूँ कि उस मामले पर ध्यान देंगे और जल्दी से लौचा पुल का काम शुरू कराने का काम करेंगे । किशनगंज-बहादुरगंज जो सड़क है, वह जिले के 65 प्रतिशत की आबादी को जोड़ती है और नेपाल सीमा से लेकर आपको पूर्णिया जिला, अररिया जिला को जिला मुख्यालय से कनेक्ट करता है। इस सड़क में सड़क कम चौड़ा होने के कारण बहुत दुर्घटनायें होती है । इसलिए सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इस सड़क का भी डबलीकरण होना चाहिए । ठाकुरगंज में गलगलिया में नेपाल सीमा पर नेपाल सरकार और भारत सरकार द्वारा मैची नदी पर एक ब्रीज बनाया गया है, उसका एप्रौच बंगाल सरकार के बोर्डर पर है, वह चाह रहा है कि हम अपने यहां ले जाय तो हमको उससे आर्थिक लाभ होगा, जिसका प्रस्ताव विभाग में लंबित है । मैं आग्रह करूंगा कि उसका एप्रौच बिहार में लाकर गिराना है, वह मात्र 600 मीटर का है, उसको भी करने का कृपा करेंगे ।

.... क्रमशः ......

टर्न-15/शंभु/12.07.19

मो0 मुजाहिद आलम : क्रमशः...इसी तरह से टेढ़ागाछ को जोड़ने के लिए जो मटियारी और आसुरा घाट में पुल की जरूरत है और अड़राबाड़ी डा0 कलाम कृषि कॉलेज जो 1 हजार करोड़ की लागत से बना है । सभापति महोदय, वहां पर जब माननीय मुख्यमंत्री 2014

में उसके शिलान्यास में गये थे फिर 2015 अगस्त में उसके उद्घाटन में गये थे तो वहां लोगों द्वारा अड़राबाड़ी कृषि कॉलेज के सामने एक पुल की मांग महानन्दा नदी में की गयी थी । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इसपर भी गौर करेंगे । कठामठा टप्पू पार्ट वन, पार्ट टू ये 30 कि0मी0 ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क है, इसको पथ निर्माण में अधिगृहित करने की कृपा करेंगे । उसी तरह से कजला मौनी मुहम्मदपुर, उसी तरह से गाछपारा से नोनिया टोली, कनियाबाड़ी से अनारकली, डी0बी0-50 इन सड़कों का ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण में अधिग्रहण होने से इस क्षेत्र के लोगों को आवाजाही में बहुत आसानी होगी । एक सड़क है मस्तान चौक बस्ताकोला बरबट्टा रोड- मस्तान चौक बस्ताकोला रोड जिसका काम पूर्व से चल रहा है, काम धीमी गति से चल रहा है मैं आग्रह करूँगा माननीय मंत्री जी से कि इसके कार्य में तेजी लाने की कृपा करेंगे । दूसरी एक समस्या है डी0बी0-50 जो एक रोड है उसका आर0डब्लू0डी0 से 44 कि0मी0 रोड का पथ निर्माण में अधिग्रहण हुआ है उसमें उस रोड का बिशनपुर से चैनपुर जो भाग है उसमें 3.75 कि0मी0 का, लेकिन बिशनपुर से 1.75 कि0मी0 जो कैरी बिरपुर एस0एच0-99 में मिलता है वह छूट गया है उसको जोड़ने का काम करेंगे । इसके अलावा पथ निर्माण विभाग द्वारा बहुत सारी सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है । सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । महोदय, यहां पर खाद्य उपभोक्ता मामले के भी मंत्री हैं उनके बजट अनुदान मांग पर भी आज चर्चा है । हमारे यहां किशनगंज जिले में 350 जन वितरण प्रणाली के दूकानदारों का पद रिक्त है, मैं आग्रह करूँगा कि उसको जल्द भर देंगे । जिले का सबसे बड़ा प्रखंड कोचाधामन है, वहां पर आपूर्ति पदाधिकारी का पद रिक्त है । वहां एक पोठिया प्रखंड है और वहां के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पर कई गंभीर आरोप है, पूर्व में भी इसकी लिखित सूचना दी गयी थी जनप्रतिनिधियों के द्वारा, वह विभाग से भी कई बार दंडित किया गया है श्री अमित कुमार जो बंगाल में बिचौलियों के साथ मिलकर कार्य करते हैं, माननीय मंत्री जी इस मामले को भी देखने का काम करेंगे । सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया है इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : सभापति महोदय, आज पथ निर्माण विभाग के अनुदान मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सभापति महोदय, दीवाली यूं ही नहीं मन गयी, दीया को रातभर जलना पड़ा है । आज बिहार में विकास ने जो एक नयी अंगड़ाई ली है- हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री नीतीश कुमार जी एवं उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी के कुशल वित्त प्रबंधन ने विकास के क्षेत्र में एक नयी इबारत लिखी है जो

पूरे बिहार में दिख भी रहा है । विकास के कैनवास पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के द्वारा जो रंग भरे जा रहे हैं और जो चित्र उकेरा गया है । आज पूरे देश के अन्य राज्य भी उसका अनुशरण कर रहे हैं । खासकर के पथ निर्माण विभाग के विभागीय मंत्री हम सबों के नेता श्री नन्दकिशोर यादव जी ने बिहार के ऐतिहासिक सड़क, पुल एवं संचार के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक परिवर्तन लाया है उसके लिए हम हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं । विभागीय मंत्री की स्पष्ट सोच और दिशा ने बिहार के विकास में एक नयी भूमिका अदा की है । सभापति महोदय, जब इरादा बना लिया एन0डी0ए0 सरकार ने उड़ान का फिर देखना फिजूल है कद आसमान का । महोदय, बिहार को उत्तर और दक्षिण बिहार में पतित पावनी गंगा नदी ने बांटा है । इसके पूर्व उसपर 4 पुल निर्मित थे, लेकिन एन0डी0ए0 सरकार ने 6 पुलों का निर्माण कर एक ऐतिहासिक कदम उठाने का काम किया है । खासकर के और भी जितनी नदियां हैं चाहे वह सोन हो, गंडक हो, कोशी हो सभी नदियों पर पुल का जाल बिछाने का काम एन0डी0ए0 सरकार ने किया है । इसी के कारण जहां इतना कष्ट था विगत 15 साल और इस 15 साल के अंतर को देखें तो मैं आरोप-प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, समय की कमी है । लेकिन एक बेहतर बदलाव, एक क्रांतिकारी बदलाव बिहार में देखने को मिला है- खासकर के हम अपने माननीय मंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहेंगे कि जितने भी रेल समपार फाटक है उसपर रेल के साथ इन्होंने जो एम0ओ0यू0 साइन किया है, हस्ताक्षर किया है उसका एक स्थायी समाधान जितने भी रेल गुमटी हैं उसपर पुल बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है । बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 जो आज से 13-14 वर्ष पहले घाटे में चला करता था, आज बिहार ही नहीं पूरे देश में उसकी एक साख बनी है । उस साख के कारण इसकी जो आमदनी हुई है उससे कई सामाजिक क्षेत्रों में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने अपना योगदान भी दिया है । यह बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब फर्स्ट एन0डी0ए0 की सरकार बनी उन्होंने घोषणा की थी एक संकल्प लिया था कि हम बिहार के किसी भी कोने से पटना 6 घंटे में पहुंचेंगे, लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी, सुशील जी और नन्दकिशोर जी के प्रति धन्यवाद देना चाहेंगे उस 6 घंटे को भी हमारे विभागीय मंत्री ने 5 घंटे करने का संकल्प लिया है और जल्द ही हम बिहार के किसी भी कोने से 5 घंटे में पटना पहुंचने में सफल होंगे । जब सड़कें काफी अच्छी बनी तो सड़कों की दुर्घटनाएं धीरे-धीरे बढ़ती चली गयी । परिवहन विभाग के साथ-साथ जो पथ निर्माण विभाग है उसने भी सड़क सुरक्षा के संबंध में एक स्पष्ट रूप से योजना बनायी है । हम आशा करते हैं कि आनेवाले दिनों में क्योंकि जानमाल की व्यापक क्षति हो रही है दुर्घटनाओं से तो इसपर एक ठोस

कदम हमारी सरकार और हमारे विभागीय मंत्री उठाना चाहेंगे । सभापति महोदय, उग्रवाद के क्षेत्र में भी जो बिहार वर्षों से तपता रहा है इस क्षेत्र में भी एक संचार का बेहतर माध्यम सड़क के रूप में इन्होंने निर्माण करके उन क्षेत्रों को भी सामान्य करने का एक बेहतर प्रयास किया है । ओ0पी0आर0एम0एल0 के द्वारा पथों की गुणवत्ता जिसकी चर्चा हमारे नेता कर रहे थे, विपक्ष के नेता कर रहे थे उन्हें नहीं पता है कि पथ निर्माण विभाग ने स्पष्ट रूप से इस दिशा में काम करना शुरू किया है और किसी भी इस तरह के गुणवत्ता में कमी होगी उसको हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी । सभापति महोदय, समय की कमी है इसलिए हम अपने क्षेत्र के कुछ ऐसे सवाल जिसपर काम हो रहा है, लेकिन उसके पूर्णता की अपेक्षा करते हैं । सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से कहना चाहते हैं कि कटिहार बारसोई पथ प्रमंडल के अन्तर्गत कई महत्वपूर्ण सड़कें हैं जो कि मात्र साढ़े 3 मीटर चौड़ी है और आवागमन का जो दबाव है उसके कारण हम अपेक्षा करेंगे कि उसे साढ़े 5 मीटर इन्टरमीडियेट रोड में उसे परिवर्तित किया जाय । सपनी हसनगंज भाया भसना और चन्द्रमा चौक, सालमारी से आजम नगर, बस्तौल चौक से सोनैली, प्राणपुर से रोसना होते हुए बांध तक और....क्रमशः

टर्न-16/ज्योति/12-07-2019

क्रमशः

श्री तार किशोर प्रसाद : और एक हमारी पुरानी मांग है । आपने कटिहार रघुनाथ पुर जिसे बलरामपुर पथ भी कहते हैं, उसे हम सबों के आग्रह पर राज्य उच्च पथ में परिवर्तित किया है । उसका चौड़ीकरण जो राज्य पथ का स्पेसिफिकेशन होता है उस मानक के अनुसार उसका चौड़ीकरण करना चाहेंगे, खास करके एक जो हमारा आग्रह है कि ..

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): अब आप समाप्त करें ।

श्री तार किशोर प्रसाद : एक हमारा आग्रह है कि कटिहार नगर में के.पी.आर.एफ. विभागीय पथ है जो कटिहार नगर के झूड़ीपट्टी से महमूदचौक तक जाती है और यह स्ड़क एकमात्र सड़क है जिसका हम बेहतर ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं, इस सड़क पर कई इंस्टीच्व्युशन है, मेरा आग्रह है कि इसके दोनों ओर नाली के निर्माण के साथ साथ पथ का सौन्दर्यीकरण और जो उसके फ्लैंक्स हैं उसमें फ्लेवर्स लगाने का काम करेंगे । आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि कटिहार पूर्वोतर बिहार का बेहतर शहर है लेकिन जाम की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है । एक फ्लाई ओवर निश्चित रुप से कटिहार शहर में बने, इसपर हम आपका ध्यान

आकृष्ट करना चाहते हैं । खास करके कटिहार नगर में एन.एच. 1,3,1ए है । गौशाला -रेल गुमटी उसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है । मेरा आग्रह होगा कि राज्य मार्ग मंत्रालय को वह संचिका भेज कर उसकी स्वीकृति दिला कर उस काम को आप शीघ्र प्रारम्भ करवायेंगे । हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाह रहे हैं कि आपके प्रति आभार भी प्रकट करना चाहते हैं कि जिस समय झारखण्ड और मनिहारी के बीच में, आपने पुल निर्माण की पहल की और वह स्वीकृत भी किया, भारत सरकार ने, उसी समय पूर्णिया कटिहार- मनिहारी- आमदा पथ को एन.एच. में परिवर्तित करके उसपर काम करने का एलान भी किया और प्रयास भी किया उसको आप जल्द से जल्द पूरा करवायेंगे, यह हमारा आग्रह है । महोदय, हमारे माननीय अरुण सिन्हा जी के क्षेत्र का एक मामला है जो पटना के न्यू बाई पास के उत्तर मीठापुर से भूतनाथ रोड तक जो नाला निर्माण का कार्य चल रहा है, वह अधूरा है और दूसरी तरफ इस आर.सी.सी. नाला के किनारे सर्विस नाला बनाया जाय, यह इनका आग्रह है और अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ‘‘ लहरों की शाहील की दरकार नहीं होती, हौसला बुलन्द हो तो कोई दिवार नहीं होती, जलते हुए चिराग ने आंधी से कहा कि उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती ।’’ यह सरकार जिस दिशा में जा रही है आने वाले दिनों में एक स्वर्ण काल के रुप में इस सरकार का कार्यकाल जाना जायेगा इन्हीं शब्दों के साथ हम पथ निर्माण मंत्री जी को हृद्‌य से धन्यवाद देते हैं कि यह एक ऐतिहासिक बजट होगा ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): माननीय सदस्य श्री अवधेश कुमार सिंह, आपका समय 4 मिनट ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : सभापति महोदय, आपने समय कम दिया है । सभापति महोदय, हमारे विपक्ष के साथी जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, उसके समर्थन में खड़ा हैं और चूँकि नंद किशोर जी, पी.डब्लू.डी. के मंत्री हैं । हम इनकी कुछ गाथाएं सदन में सुनाना चाहते हैं । पी.डब्लू.डी. का जो, ये मिला है, ओ.पी.आर.एम.सी. फेज -11 इसमें हम देख रहे हैं कि नंद किशोर बाबू जो गया जिला के काम का जो लिस्ट बनाए हैं, उस काम में इस गया जिला में जो 26 ब्लौक का जिला है और 10-11 एम.एल.ए. यहॉ से आते हैं । मगर लगता है कि सिर्फ गया शहर ही भाजपा के खाते में है इसलिए गया शहर के जितने गली और नली को पी.डब्लू.डी. बना रहा है जैसे वह नगर विकास हो, हम यही आपका किताब पढ़ रहे हैं देख लीजिये, पृष्ठ 45 पर देखिये न । गया शहर का रोड बना रहे हैं। नंद किशोर बाबू और भी है(व्यवधान) हॉ , ठीक है भाजपा को करना चाहिए चूँकि तारकिशोर जी ने दीपक जलाया है यहॉं, इसलिए चाहते हैं कि दीपक नहीं बुझने दीजिये, कमल खिलाने की

बात भूल जाईये । नंद किशोर बाबू गया गए थे, एक आर.ओ.बी. हमलोगों ने पास कराया था, नीतीश कुमार जी से भारत सरकार उस समय यू.पी.ए. की गवर्नमेंट थी, उसका उद्घाटन करने गए थे, नंद किशोर जी वहाँ जो मानपुर में जो जगजीवन कॉलेज अबगिला रोड है, उसका एसकेलेटर रोड बनाने की नंद किशोर बाबू घोषणा करके आए थे, हम सोचे नंद किशोर बाबू एक बहादुर मंत्री इस राज्य के हैं । उस भाषण को इस वक्तव्य में लायेंगे मगर दुख हुआ कि उसका कहीं जिक्र नहीं है जो पेपर मुझे दिया गया । हम आपसे आग्रह करेंगे कि एसकेलेटर बनेगा या नहीं बनेगा आपने घोषणा की है जनता आपसे पूछेगी मगर जगजीवन कॉलेज से अबगिला तक जो पहले एन.एच. 82 था अब एन.एच. आई. हो गया है पूरा शहर वह बाई पास बन गया है मगर आज वहाँ पर मानव नहीं चल सकते हैं, गाड़ियाँ नहीं चल सकती हैं । उसको आप मरम्मत करावें और जगजीवन कॉलेज से अबगिला तक पी.सी. सी. और नाले का निर्माण करा दें नंद किशोर बाबू तो आपको वहाँ की जनता जो आप एस्केलेटर बोले हैं, उसके जगह पर हम कह देंगे कि नंद किशोर भाई यह बना दिए हैं मंत्री जी को बधाई दो । बजीरगंज बाजार जो प्रायः रास्ता वहाँ भी बाई पास एन.एच. 82 का एन.एच.आई. बना दिया गया है मगर बजीरगंज बाजार जो है पूनामा से बाजार जहाँ कि आप ही कहते हैं कि बाजार का वोटर भाजपा उस वोटर को कष्ट है वह दखिनगांव तक उस रोड का निर्माण करा दें और इस बरसात में आप उसको बनवा दें और अभी हमारे सदस्य बोल रहे थे कि घोषणा की गयी है कि मुख्यालय आने के लिए पाँच घंटा से छः घंटा में पटना मुख्यालय आया जा सकता है । हम तो मुख्यालय आते थे गया से पटना तीन घंटे में, पौने तीन घंटे में और आज हम गया से पटना आ रहे हैं नंद किशोर जी पाँच घंटा, साढ़े चार घंटा में, गया पटना रोड में आप जांय या न जांय आप अपने पदाधिकारी, अपने इंजीनियर को भेंजे और पूछें कि आज इस इलाके के लोग जो पटना आयेंगे उनकी क्या दशा है । उसमें आज के दिन गाड़ी नहीं चल सकती है । बैल गाड़ी से अगर पटना पांच घंटे या छः घंटे में आया जा सकता है तो हो सकता है कि हम गया से पटना पाँच से छः घंटा में पहुचेंगे । सभापति महोदय, समय का अभाव है । सभापति महोदय, औरंगाबाद जो आपका जिला है । औरंगाबाद क्षेत्र में आपका घर है, औरंगाबाद जिला के अंतर्गत कुटुम्बा प्रखंण्ड के एन.एच.आई. 139 अम्बा भाया जिवाबिगहा-भालूगंज, आर.ई.ओ. पथ देव, एन.एच.आई-2 तक का संडा भया कुटुम्बा माली पथ एवं अम्बा नवीनगर के तूरता नहर पथ को आर.सी.डी. पथ में डायभर्ट करने का प्रस्ताव विभाग के वार्षिक कार्य योजना में है परंतु अभी तक आर.सी.डी. में उस पथ को सम्मिलित नहीं किया गया है इसलिए सभापति महोदय, हम आग्रह करेंगे

कि औरंगाबाद की ये महत्वपूर्ण सड़क है, इसको देखें और नंद किशोर बाबू से व्यक्तिगत अनुरोध करेंगे कि आप गया- पटना जो बुद्धा सर्किट है।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): माननीय सदस्य अब समाप्त करें ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : हॉं, समाप्त कर रहे हैं । गया-पटना पथ और जगजीवन कॉलेज से जो अबगिला और बजीरगंज बाजार दोनों जगह पर निश्चित तौर पर मरम्मत करा दें और पी.सी.सी. रोड का निर्माण करायें । यह हमारा नंद किशोर बाबू से व्यक्तिगत आग्रह है ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): अब आप समाप्त करें । माननीय सदस्य श्री सुनील कुमार ।

श्री सुनील कुमार : माननीय सभापति महोदय, मैं आज समूचे विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में और पथ निर्माण विभाग पिछड़ा, अति पिछड़ा विभाग एवं खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा लाए गए मांग के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

क्रमशः

टर्न-17/12.07.2019/बिपिन

श्री सुनील कुमार : क्रमशः महोदय, पथ निर्माण विभाग पथों के मामले में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है । पथ निर्माण विभाग के कार्यों पर ही राज्य के विकास की गाड़ी दौड़ती है। लेकिन महोदय, जिस प्रकार से पथ निर्माण विभाग के द्वारा काम किया जा रहा है इससे प्रतीत होता है कि विभाग को सिर्फ और सिर्फ पटना की ही चिंता है, राज्य के बाकी इलाकों से बहुत मतलब नहीं है महोदय । महोदय, जिस तरह से पटना की सड़कें चकाचक बन रही है तल्ला-दोतल्ला पुल बन रहे हैं, ओवर ब्रीज बन रहे हैं लेकिन राज्य के बाकी इलाकों में अनदेखी की जा रही है । इससे प्रतीत होता है कि राज्य का जो यह विभाग है, गांव विरोधी है, गरीब विरोधी है ।

महोदय, माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग से आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्रीजी जब अपना जवाब दें तो निश्चित रूप से माननीय सदन को बतावें कि पथ निर्माण विभाग के इस बजट में इन्होंने किस जिला को कितना दिया है, माननीय मंत्रीजी से अपेक्षा करूंगा कि अपने जवाब में निश्चित रूप से सदन को बतावें ।

महोदय, दो साल पहले अक्सर हम लोग सुना करते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कितनी बार कहा है कि एन.एच. की मरम्मती का 900 करोड़ रूपया भारत सरकार पर बकाया है । अब उसकी चर्चा दो सालों से नहीं हो रही है । माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय, आप सदन को इस बात से

भी अवगत करावें कि यह 900 करोड़ रूपया जो भारत सरकार पर एन.एच. मरम्मती का जो बकाया था वह आपको मिला कि नहीं मिला । आप सदन को अवगत कराएंगे ।

माननीय मंत्री महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र और मेरे जिला सीतामढ़ी में मेहसॉल चौक से सीतामढ़ी, आजाद चौक की तरफ जाने वाली जो सड़क सुरसंड जाती है, पुपरी जाती है, नेपाल जाती है, एक आर.ओ.बी. है, पिछले पांच साल से उसका निर्माण कार्य चल रहा है महोदय । एक दिन बीच करके एक मिस्त्री और एक मजदूर काम करता है उसमें । एक दिन बंद रहता है और दूसरे दिन फिर एक मिस्त्री और एक लेबर काम करता है और अभी तक पांच साल में दो ठो पाया बनकर तैयार हुआ है । दो-तीन दिन पहले माननीय पथ निर्माण मंत्री महोदय ने सदन को अवगत कराया कि केंद्र सरकार से जो नीतिगत कुछ मतभेद था वह अब खतम हो गया है गतिरोध दूर हो गया है, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय, अब जो गतिरोध था खतम हो गया है तब पुल का जो बाकी भाग है यह कितना दिन में बनकर तैयार हो जाएगा, यह भी आप सदन को बताना चाहेंगे । माननीय मंत्री महोदय, एन.एच. -77 जो हाजीपुर से चलकर सोनबर्षा तक जाती है, बनकर तैयार हो गई है और सड़कें कुछ जगहों पर ग्रामीण इलाकों को छोड़कर अलग से चली गई । यानी एन.एच. 77 का जो पुराना भाग है ओल्ड एलायन्मेंट है, जो रून्नी सैदपुर के गाढ़ा से सुबई तक जाती है और भूतही से सोनवर्षा तक जाती है, गायत्री जी के क्षेत्र में भी है, सोनवर्षा तक जाती है उसकी हालत इतनी खराब है, सालो भर जल-जमाव रहता है । अभी तक बरसात का समय है, नाव चलाने की स्थिति होगी उसमें । सालों भर जल जमाव रहता है । भूतही का बता दीजिए न ! भूतही का बता दीजिए

(व्यवधान)

सालों भर जल-जमाव रहता है और सड़कों की हालत इतनी खराब है और उसमें दोनों तरफ से महोदय, सभापति महोदय, उसमें दोनों तरफ से लोग बसे हुए हैं, हजारों लोग बसे हुए हैं और लोगों की जिन्दगी नारकीय हो गई है । लोगों को बहुत बड़ी समस्या है । गायत्री जी, आप दिल पर हाथ रखकर कहिएगा । हम गए थे वहां रजवाड़ा से मुशहरनिया बरियाती में, तीन घंटा लगा सोनबर्षा से जाने में, रास्ता तो अच्छा है हमने देखा है लेकिन तीन घंटा लगा था हमको रात में जाने में सोनवर्षा से रजवाड़ा से मुशहरनिया ।

(व्यवधान)

महोदय, एन.एच.-104 जो मोतिहारी से चलकर शिवहर होते हुए सीतामढ़ी होते हुए सुरसंड भीठामोड़ होते हुए वहां तक, जयनगर तक जाती है, नरहिया तक जाती है । उसकी हालत इतनी खराब है, पांच-छः साल से सड़कें बन रही है और हमने तो

बहुत सारा उसका पार्ट नहीं देखा है लेकिन शिवहर से भीठामोड़ तक हमने खुद जाकर देखा है । आज आपको, हमको लगता है साइकिल से नहीं जा सकते हैं सीतामढ़ी से शिवहर और जाइएगा तो रास्ते में जरूर गिर जाइएगा, आपका हाथ-पैर टूट जाएगा । कोई लोग सही से नहीं जा सकते । उस रोड की इतनी हालत खराब है और आज उसकी इतनी दुर्दशा हो गई है उस रोड का कि उसमें कोई काम नहीं हो रहा है । एन.एच. 104 का काम पूरी तरह से ठप है और वह मोतिहारी से लेकर और जयनगर तक जो उसकी हालत है उसको देखने की जरूरत है और उसको जल्द-से-जल्द बनवाने की जरूरत है ।

महोदय, एन.एच. 104 का ही पार्ट से लेकर बरियारपुर तक इतना जल-जमाव है उसमें, आज भी दो-दो फीट पानी लगा हुआ है और पथ निर्माण विभाग के मंत्री तो बहुत ही संवेदनशील मंत्रीजी हैं, मैं फ्री में एक सलाह देना चाहूंगा मंत्री जी और उससे आपके विभाग को भी फायदा होगा । धान के रोपनी का समय हो गया है, बिचड़ा तैयार है । तीन-चार किलोमीटर जो सड़कें हैं उसमें अपने विभाग के अधिकारियों-पदाधिकारियों को भेज कर धान रोपवा दें तो विभाग को उससे अच्छी आमदनी होगी महोदय और दो-तीन महीना तक कोई काम भी नहीं होने वाला है । उस रोड में पूरा दो फीट पानी जमा है । इसलिए उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है महोदय।

(व्यवधान)

श्री नंद किशोर यादव, मंत्रीः सीतामढ़ी आज जा पा रहे हैं तो वह पुल मैंने बनाया है तो बोलेंगे किसको ?

श्री सुनील कुमार : महोदय, आप तो कहते हैं जिला मुख्यालय से पांच घंटा में पहुंचा देंगे पटना लेकिन गांव से न पहुँचाइए । जिला मुख्यालय से पहुंचा देने में, पटना की सड़कें चकचका देने से काम नहीं चलने वाला है, जब तक गांव की सड़कें नहीं चकचकाएंगी महोदय और हमारा जिला तो सीतामढ़ी के सभी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं सभापति महोदय और मैं कहना चाहता हूं, पिछले दो वर्ष पहले जो बाढ़ आया और उसमें जो सड़कें ध्वस्त हुई, आज तक उस सड़क को अगर बना दिया गया है उसमें एक टोकड़ी अगर मेटल और गिट्टी रखा गया हो तो जो कह दीजिए महोदय । कोई सड़कें नहीं बनी है और गांव के सभी सड़कों की हालत खराब है सीतामढ़ी जिला में। किसी भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है महोदय । महोदय, पी.डब्लू.डी. का ही सड़क है, आर.सी.डी. की सड़क है, अब सड़कों की बात छोड दीजिए, पुलों की बात छोड़ दीजिए । तीन पुल है जो रेलिंग विहीन है । बराबर दुर्घटनाएं होती है । एक आजमगढ़ के जमदीशपुर में, और दो मोहनपुर चौक पर, उसमें हम कितना बार वहां आर.सी.डी. के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से, जिला के समाहर्त्ता से दो साल से कह रहे हैं । रोज कहते हैं कि एक सप्ताह में हो

जाएगा ? तीनों पुल का आज तक रेलिंग नहीं लगा है । पथ बनाने की बात तो दूर है उसका रेलिंग नहीं बन पाया है महोदय ।

महोदय, मैं एक सुझाव आपको और देना चाहूंगा महोदय । पथ निर्माण मंत्री भी हैं, सभापति महोदय आपके माध्यम से जिस तरह से पहले सड़कों की रख- रखाव के लिए, देखभाल के लिए वर्क सरकार रहता था जो अपने साईकिल पर कुदाल लादकर और सड़कों पर जहां-जहां जल जमाव होते थे उनको बाहर निकालने का काम करता था। आज आपकी सड़कें बनी है और वह इसलिए टूट रही है जो वहां जल का जमाव हो जाता है और उसको निकालने वाला नहीं है, पानी को काट कर बहाने वाला नहीं है । आपकी सड़कें टूट जाती हैं । तो मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप वर्क सरकार के तौर पर ही सड़कों की दूरी बांट कर वैसे आदमी को रख लेते हैं जो आपके जल जमाव को भी निकालेगा और उसमें आपके सड़कों का जो अतिक्रमण कर लिया जाता है लोगों के द्वारा, उसकी भी देखभाव वो करेंगे ।

दूसरी एक बात और कहना चाहूंगा महोदय, सड़कें जब बन जाती हैं तो कुछ दिनों के बाद कहीं-कही छोटे-छोटे गढ़े हो जाते हैं और हमलोग उस गढ़ा को बड़ा होने का इंतजार करते रहते हैं कि कब यह गढ़ा बड़ा होगा तो इसको फिर भरेंगे तो उसको अगर तत्काल बना दिया जाए, तत्काल उसका पैचपॉट कर दिया जाए तो सड़कें जो ज्यादा टूटती हैं, नहीं टूटेंगी महोदय ।

महोदय, आज पिछड़ा एवं अति पिछड़ा विभाग पर भी, महोदय, सारण जिला के अन्तर्गत छपरा सत्तर घाट के नेथवलिया के समीप पथ एस.एच. में फ्लाई ओवर चौक का निर्माण कराया जाए । नेथवलिया चौक के समीप फ्लाई ओवर का निर्माण कराया जाए । प्रतिदिन वहां दुर्घटनाएं होती रहती है इसलिए वहां फ्लाई ओवर का निर्माण आवश्यक है महोदय ।

टर्न : 18/कृष्ण/12.07.2019

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : आप का समय समाप्त हो गया ।

श्री सुनील कुमार : समय है पार्टी का, उसी में से हम को समय दे दीजिये । महोदय, आज पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा कल्याण विभाग की भी मांग है, उसको गिलोटीन मे रखा गया है । आज एन0डी0 ए0 की सरकार में पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्गो के आरक्षण एवं हक अधिकार पर प्रहार किया जा रहा है । निर्धारण सदन का काम है लेकिन उसे लागू करनेवाले लोग उसको तोड़-मरोड़ कर उसकी व्याख्या कर पिछडों, अति पिछड़ों को आरक्षण से वंचित कर रहे हैं । महोदय, इस स्पष्ट उदाहरण यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन निकाला

गया, उसमें डी0एस0पी0 के 62 पद रिक्त थे लेकिन पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्गों के लिये उसमें एक पद भी आरक्षित नहीं था । तो इस तरह से एक साजिश के तहत पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को उच्च कुर्सी पर जाने से रोकने की साजिश चल रही है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है ।

महोदय, एम0बी0बी0एस0 के काउंसीलिंग में कौन-सा नियम बनाया गया कि बेतिया और पावापूरी मेडिकल कॉलेज में पिछड़ा, अतिपिछड़ा दलित छात्र ही नामांकन ले रहे हैं । इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है । महोदय, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिये योजनायें तो बहुत सारी बनती हैं लेकिन जमीन पर बहुम कम योजनायें उतरती है । पिछड़ा अति पिछड़ा अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चियों के लिये कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की क्या स्थिति है, यह कहने की जरूरत सनही ं है ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : आप का समय समाप्त हो गया ।

श्री सुनील कुमार : महोदय, एक मिनट दिया जाय ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : आप का समय समाप्त हो गया है । आप दूसरे माननीय सदस्य को दे दीजियेगा, वह बोल देंगे । आप बैठ जाईये । माननीय सदस्य श्री निरंजन कुमार मेहता ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : सभापति महोदय, लोकतंत्र के इस पवित्र सदन में वर्ष 2019-20 के सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की मांग संख्या 41, मांग संख्या 11 और मांग संख्या 18 पर बोलने के लिये समय दिया गया है, उसके लिये मैं सभापति महोदय, आपके प्रति आभार प्रगट करता हूं ।

सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से विकास पुरूष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं । मैं आप के माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय तथा माननीय मंत्री महोदय, पथ निर्माण विभाग, माननीय मंत्री महोदय, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा माननीय मंत्री महोदय, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग का भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूं ।

सभापति महोदय, आज जिनके सानिध्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में हमलोग काम कर रहे हैं । बिहार के सभी माननीय मंत्री महोदय काम कर रहे हैं जिन्होंने निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं हमारा बिहार राज्य हर दिशा में आगे बढ़ रहा है । हरेक विभाग में कार्य द्रुत गति से हो रहा है । महोदय, मेरे सर्वमान्य नेता जिन्होंने न्याय के साथ विकास का वादा दिया, जिन्होंने

2015 के चुनाव में आम जनता के साथ 218 चुनावी आमसभा में वादा किया आज हरेक काम धरातल पर दिखाई दे रहा है ।

सभापति महोदय, आज पथ निर्माण विभाग प्रगति के पथ पर चल रहा है । आज मैं विश्वास के सेतु पर चर्चा कर रहा हूं । पथ निर्माण विभाग आज पूरी तत्परता से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में काम कर रहा है । महोदय, मैं बताना चाहूंगा माननीय मंत्री श्री नन्दकिशोर बाबु की तत्परता मैंने विभाग में जो देखा, उसकी चर्चा मैं जितना भी करूं, वह बहुत कम होगा । इनकी जो कार्यशैली है, उसके संदर्भ में मैं अपने क्षेत्र का थोडा-सी परिभाषा देना चाहूंगा । सभापति महोदय, जो काम करे, उनकी चर्चा होना जरूरी है । उनकी चर्चा होनी भी चाहिए । काम जो करते हैं उनके बारे में, हमलोग भी अपने क्षेत्र में काम करते है । अगर कोई दो शब्द बोलता है तो अच्छा लगता है और काम करनेवालों की काम करने की गति बढ़ती है ।

महोदय, हम अपने क्षेत्र बिहारीगंज के बारे में बताना चाहेंगे, पिछले साल की बात है, एक बाईपास है एस0एच0-91, किसान को जमीन का सारा पैसा मुहैय्या करा दिया गया था, बाईपा का लाईन-अप भी हो गया था, लेकिन वह बाईपास साफ डेड हो गया था, वह मृत घोषित हो गया था । उसके संबंध में मैंने पिछले सत्र में चर्चा किया था, सदन में सवाल को उठाया, हम उसका निष्कर्ष बताना चाहते हैं, माननीय मंत्री द्वारा इतना देखा गया कि आज उस बाईपास का 90 परसेंट काम हो चुका है और हम समझते हैं कि एक माह के अंदर वह रनिंग अवस्था में आ जायेगा । यह माननीय मंत्री महोदय की सोच है। जब भी हमलोग इनसे मिलने जाते हैं तो हमा री बातों को अच्छी तरह से सुनते हैं । इसलिए जो काम करते हैं उसके बारे में बोलना चाहिए दो शब्द अच्छा और झूठी बात बोलने से कोई फायदा नहीं होता है । आज रोड की जो बात है, कौन रोड है, जो अच्छा नहीं बना है । अभी हमारे साथी मुजाहिद साबह बोल रहे थे, हम भी मधेपूरा से आते हैं, हमलोगों का एन0 एच0 वीरपुर-बीहपुर रोड जो पिछले साल से बंद हो गया था,आई0एफ0आई0सी0एल0 का ठीकेदार था, आज उस भी हम आगे बतायेंगे, उस की भी सुनवाई हुई है, उस पर भी माननीय मंत्री महोदय का सारा आदेश हो गया और फिर वही ठीकेदार काम भी शुरू कर दिया गया है । तो रोड कैसे नहीं बन रहा है । हरेक जगह रोड बन रहे हैं । साढ़े 5 घंटे में मधेपूरा से 352 किलोमीटर से आते हैं ।

महोदय, आज हम पथ निर्माण विभाग के कार्यों के संबंध में कुछ चर्चा करना चाहेंगे । वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2017-18 तक योजना उद्व्यय का लगभग

शत-प्रतिशत एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिसंबर माह तक योजना उद्व्यय का लगभग 60 प्रतिशत राशि व्यय कर दी गयी है ।

सभापति महोदय, पथ निर्माण विभाग महात्मा गांधाी सेतु के पुनर्गठन हेतु एक समर्पित प्रमंडल तथा महात्मा गांधी सेतु प्रमंडल का पुनर्गठन किया गया है जिससे गांधी सेतु का कार्य और गति से चले । उसके लिये व्यवस्था की गयी है । पथ निर्माण विभाग के अधीन महात्मा गांधी सेतु के प्रबंध हेतु विभागाधीन गंगा पुल परियोजना उपभाग को सेतु प्रबंधन उपभाग के रूप में पुनर्गठित कर इसका सुदृढ़ीकरण आधुनिकीकरण के साथ अतिरिक्त 10 विशेषज्ञ का भी पद सृजित किये गये हैं, जिससे उसका कार्य जल्द से जल्द हो सके ।

सभापति महोदय, पथ निर्माण विभाग भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजन एवं 6 लेन गंगा ब्रीज कच्ची दरगाह विद्दूपुर में भू-अर्जन की कार्रवाई में अपेक्षित प्रगति लाते हुये कार्य प्रारंभ किया गया है । महोदय, विश्व बैंक सम्पोषित योजना NHIIP के अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-1 104 शिवहर, सीतामढ़ी, जयनगर, नरहरिया एन0एच0 106, बीहपुर-वीरपुर रोड यही रोड मेरा है, जिसकी स्थिति इतनी खराब थी और मधेपुरा से हमलोग अपना घर उदाकिशनगंज जाते हैं, 35 किलोमीटर, इतना रोड खराब है, अभी फिर से काम शुरू किया गया है, माननीय मंत्री महोदय आदेश दे दिये हैं, इसके लिए मैं पुनः इनका हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं, सभापति महोदय, यह कार्य हो रहा है । एन0एच0 30 0 फतुहां ,बाढ, हरनौत एवं एन0एच0-98, अनिसाबाद औरंगाबाद, हरिहरगंज के कुल 509 किलोमीटर के अपग्रेडेशन कार्य के विरूद्ध 260 कि0मी0 शेष कार्य प्रगति पर है । कहते हैं कि काम ही नहीं हो रहा है ।

सभापति महोदय, महात्मा गांधी सेतु 5.575 कि0मी0 के पुनर्स्थापन लागत राशि 1382.4 करोड़ का कार्य प्रगति पर है और अब गांधी सेतु के कार्य को आगे बढ़ाने के लिये गांधी सेतु प्रमंडल का पुनर्गठन किया गया है । जैसाकि मैंने पहले भी कहा । बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-6 से 1018-19 अक्टूबर माह तक 9400.24 करोड़ की लागत पर 1846 अदद एवं पथ प्रमंडलों द्वारा वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक 353.44 करोड़ की लागत पर 91 अदद वृहद् लघु पुलों का भी निर्माण कार्य कराया जा रहा है ।

सभापति महोदय, मुख्यमंत्री सेतु योजना के अन्तर्गत 3352.06 करोड़ की लागत पर कुल 5,135 योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : महोदय, कुछ अपने क्षेत्र की बात कहकर समाप्त करता हूं । मुझे एक मिनट का समय दिया जाय । भागलपुर सुल्तानगंज में भी पुल का काम हो रहा है । आप के यहां औरंगाबाद में काम हो रहा है । पटना शहर का बेली रोड है, मीठापुर का ऊपरी पुल है । महोदय, मिनट कुछ अपनी बात कहना चाहता हूं ।

क्रमश :

टर्न-19/अंजनी/12.07.19

श्री नरेन्द्र कुमार मेहता : क्रमशः..... सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कुछ गुजारिश करना चाह रहा हूँ, काम मेरा हो रहा है, मुझे कोई शिकवा-शिकायत नहीं है, हम शिकायत करेंगे भी तो कैसे । हमलोगों को तो पक्ष में बोलना है । सरकार काम कर रही है, मेरा क्षेत्रीय बात है, ग्वालपाड़ा से लक्ष्मीपुर, एस0एच0-91 तक में काम चल रहा है । मुरलीगंज बाजार में जो सड़क खराब है, उसमें भी काम लगा हुआ है । वीरपुर-वीहपुर, एन0एच0-106 में काम लगा हुआ है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ कि कार्य में गति दिया जाय, यही मेरा अनुरोध है ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब आप समाप्त करें । माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार ।

श्री जिवेश कुमार : सभापति महोदय, सरकार द्वारा जो बजट लाया गया है उसके पक्ष में और कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । अब कटौती प्रस्ताव पेश करने वाले माननीय सदस्य श्री ललित यादव जी गायब हैं सदन से । उनको सुनना चाहिए कि क्यों कटौती प्रस्ताव का विरोध हो रहा है । जब इन लोगों को मौका मिला तो एक आदमी चारा खा गये, कोई अलकतरा पी गया और जो काम करने वाले लोग हैं, उनपर विरोध और क्रिया-प्रतिक्रिया पेश कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

बिहार सरकार अपने काम के प्रति चिंतित है और बहुत ही मनोभाव से बिहार के विकास में सतत् अनवरत काम कर रही है और यहां जितने भी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, माननीय ललित बाबू ने 20 मिनट में अपनी बात को सदन में रखा और सिर्फ एक ही विषय को रखने का काम किया । अगर आप माननीय सदस्य श्री ललित बाबू जी का 20 मिनट का भाषण सुनें तो राष्ट्रीय जनता दल के सभी सदस्यों का समय खाकर उन्होंने अपने एक रोड का मांग किया है, अब 20 मिनट में केवल एक रोड का उन्होंने मांग किया है और राष्ट्रीय जनता दल के सभी सदस्यों का समय खा गये और एक रोड सिर्फ मांगने का काम किया है । पता नहीं, काहे इनलोगों को गुस्सा

होता है, हम तो जरा छेड़ते हैं तो ये चिल्लाते हैं और वे कत्ल भी करते हैं तो ये मुस्कराते हैं । हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनकी मंशा क्या है ? इनके नेता कौन-कौन हैं । अब आप देखिए कि इनके नेता सदन से गायब हैं ।(व्यवधान) तारकिशोर जी बैठ जाइए । अब इनका नेता कौन है, ये पहले तय करें । मुझे आज बहुत भरोसा था कि नेता प्रतिपक्ष, जो पथ निर्माण मंत्री भी रहे हैं और संयोगवश उनको 18 महीने में दो बार बजट पेश करने का मौका मिला और माननीय ललित बाबू कह रहे थे हमारे काम करने वाले उर्जावान मंत्री महोदय से कि आप पार्टी विशेष का काम करते हैं तो अगर आसन का इजाजत हो तो बीस महीने में हमने कितना पत्र लिखा है उनको, मैं दिखाना चाहता हूँ और उसमें एक काम भी उस समय के नेता, अभी जो वर्त्तमान में प्रतिपक्ष के नेता हैं और उस समय के पथ निर्माण मंत्री ने इसलिए नहीं किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक था । सदन को आप भरमाने का काम मत कीजिए, सदन को विषमित करने का काम मत करिए, जो फैक्ट है, उसको रखने का काम करिए । आज पांच घंटा में अगर मधेपुरा से लोग पटना आ रहे हैं तो यह है पथ निर्माण विभाग की उपलब्धि और ओ0पी0आर0एम0सी0 में तो आपने कमाल का काम कर दिया हुजूर, अब तो सड़क में कोई गड्ढ़ा मिल ही नहीं रहा है । यह अलग बात है कि माननीय सदस्य मुन्ना बाबू मुजफ्फरपुर से चलते हैं तो पटना आने में रास्ते में एक दिन विश्राम कर लेते हैं तो इनको डेढ़ दिन लगता है आने में तो इसमें सरकार की क्या गलती है । सरकार तो पांच घंटे की व्यवस्था तय कर दिया है, अगर आप अपनी रफ्तार में चलेंगे तो बिहार के किसी कोने से पांच घंटे में आप पटना पहुंच जायेंगे । माननीय सदस्य को बड़ी चिन्ता है तो अपने समय में अपनी बात कहेंगे । चूंकि समयाभाव है । यातायात की सुगमता के लिए, अभी आते होंगे मुजफ्फरपुर की तरफ से चलकर आने वाले लोग अभी देख रहें होंगे कि कितना तेजी में गांधी सेतु का काम हो रहा है और पटना में फ्लाई ओवर का जाल बिछाकर सरकार ने कितनी सुगमता पैदा कर दी है और नेता, प्रतिपक्ष से आज उम्मीद था हूजूर कि सदन में रहते तो माननीय मंत्री जी को बेहतर सुझाव देते । पहले वे इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं, हमारी अपेक्षा थी कि आदरणीय सिद्दिकी साहेब से, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से कि आज उनको कम-से-कम सदन में रहकर अपना बहुमूल्य सुझाव बिहार के हित में देना चाहिए था और मेरा तो कहना है कि सभापति महोदय कि...

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब आप कनकलुड कीजिए ।

श्री जिवेश कुमार : दो मिनट हुजूर । मेरा तो कहना है कि अगर सदन के लिए उनके पास समय नहीं है तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए । जनता के टाईम को क्यों खराब कर

रहे हैं । अब मैं दो मिनट में अपने क्षेत्र की कुछ बात रखता हूँ । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां एक पर्यटक स्थल है अहिल्या स्थान, उस अहिल्या स्थान का सड़क तीन किलोमीटर है, मुख्य सड़क से जोड़ना है, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है और वहां नवम्बर में महोत्सव होने वाला है तो हम उम्मीद करते हैं कि विभाग के पास क्षमता है, अगर विभाग चाह ले तो तीन किलोमीटर सड़क को तीन महीने में जरूर बनाकर के उसको दुरूस्त कर सकती है और अहिल्या स्थान से गौतम कुंड होते हुए नवमछिदांत तक, यह 9 किलोमीटर सड़क टॉप प्रायोरिटी का सड़क है, हम उम्मीद करते हैं कि विभाग संज्ञान लेगा । भरवाड़ा से चामुण्डा स्थान तक

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री जिवेश कुमार : एक मिनट में समाप्त करता हूँ । हुजूर, जोगियारा मदौली सड़क की स्वीकृति हो गयी है और अभी मेरा कहना है कि जाले से लेकर सन्होली चॉक एस0एच0-50 तक जो पी0डब्लू0डी0 की सड़क है, वह सकरी सड़क है, बिहार सरकार अभी अपने 80 परसेंट रोड को सात मीटर चौड़ी सड़क में तब्दील कर चुका है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि जाले से लेकर जो जोगियारा तक की सड़क है, इसको सात मीटर चौड़ी सड़क बना दें और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पूरे बिहार का है, जिसको रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ । महोदय, नोर्थ-साउथ कोरीडोर के तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, नोर्थ-साउथ कॉरीडोर में तीसरे और अंतिम चरण के कार्य ताजपुर से भिठ्ठा मोड़ के लिए 117 किलोमीटर सड़क निर्माण को अविलम्ब प्रारंभ किया जाय ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : मताननीय सदस्य श्री सुधीर कुमार, आपका समय पांच मिनट ।

श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी : सभापति महोदय, आज पथ निर्माण विभाग के वाद-विवाद पर बोलने के लिए जो आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद । मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, राज्य सरकार का लक्ष्य है कि सड़क संरचनाओं का ऐसा सुगम जाल बिछाया जाय, राज्य के किसी भी क्षेत्र से पटना पांच घंटे में पहुंचे लेकिन शायद सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायकों के लिए ही संभव है । हमलोगों के लिए यह सुगम नहीं हो पाया है । आज भी जमुई से हमारे यहां आने में सरमेरा और हरनौत का रास्ता जो बन रहा है, बीच रास्ते में जो आधा काम कम्पलीट होकर खत्म हो चुका है, पर कुछ दूरी लगभग 500 मीटर छोड़ दिया है । क्या वजह है यह तो विभाग जानें या ठीकेदार जानें । महोदय, मैं अपने क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य हो रहे हैं बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड से, एस0एच0-82 में जो कौआकोल से जमुई होते हुए खैरा होकर सोन्हो तक जायेगा, यह रोड एस0एच0-82 में कार्य लगा

हुआ है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ पर जिस तरह से कार्य चालू है या जिस तरह से कंट्रेक्टर के द्वारा पेटी कंट्रेक्टर से काम किया जा रहा है, यह बहुत ही गंभीर मामला है ।

...क्रमशः...

टर्न-20/राजेश/12.7.19

श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी, क्रमशः क्योंकि जिसतरह से कंट्रैक्टर की सारी निविदाएँ पूरी करने से पहले जांचोपरान्त, उसके पेपर सारा कुछ उसके इक्यूपमेंट के आधार पर काम करने के लिए उसे दिया जाता है और वही कंट्रैक्टर अपने फायदे के लिए, अपनी सुविधा के लिए ऐसे अनुभवहीन पेटी कंट्रैक्टर को दे देते हैं और वह लीपापोती काम को करते हैं । इसलिए मेरा आग्रह है कि पेटी कंट्रैक्ट जहाँ भी हो रहा है, उसपर सरकार के द्वारा वहाँ पर जांच करवायी जाय और इसको देखा जाय । उसी सड़क एस0एच0-82 में खैरा बाजार आता है, जहाँ पर दो तरह का रोड आ रहा है, एक है अमीन से खैरा रोड और दूसरा कौआकोल से खैरा जमुई रोड यानि दोनों रोड के बीच में खैरा बाजार पड़ता है, जहाँ पर बाईपास का बहुत ही आवश्यकता है और कई वर्षों से बाईपास की मांग भी हो रही है लेकिन वहाँ पर बाईपास आज तक नहीं बनाया गया है, उसी रोड में जो देवघर जायेगा खैरा से दो पुल क्षतिग्रस्त है और वह लगभग तीन साल से पड़ा हुआ है, एक है नरैना पुल और एक है बागोबंदर पुल और जबकि सावन के समय में बोलबम के लिए लोग उसे बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं और वह रास्ता आज भी नहीं उपयोग हो पा रहा है क्योंकि यह दोनों पुल एक साथ क्षतिग्रस्त है और आपको जानकर आश्चर्य होगा महोदय और उस पुल को बनाने में करोड़ों रुपये की राशि की लागत से पुल जो बना था, वह मात्र चार से पाँच साल में वह पुल क्षतिग्रस्त हो गया, इसका क्या वजह था, यह जांच का विषय है और सबसे बड़ा वजह यह आता है कि नो इंट्री में पुल पर भारी वाहनों यानि ट्रक का ठहराव कराया जाता है जिसके कारण पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है, इसलिए मैं आपके माध्यम से विभाग को आग्रह करना चाहता हूँ कि वह जल्द से जल्द दोनों पुल को या तो जो क्षतिग्रस्त है उसकी मरमति करायी जाय या तो नई पुल के निर्माण का प्रस्ताव हो और उसे यथाशीघ्र कराया जाय और जो बाईपास की मांग है हुजूर, यह भी बहुत ही पुरानी मांग है और ग्रामीणों द्वारा कई बार इसके लिए रोड भी जाम किया गया है और यह मांग मैं सदन में रखता हूँ कि खैरा बाईपास रोड को जल्द से जल्द निर्माण किया जाय और इसमें महोदय, कई रोडों को आज ही मैंने देखा है जिसमें शेखपुरा-सिकंदरा रोड, जो

बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी है और जो भी रोड बनता है, उसपर जो पुलिया बनाया जाता है, उपर से पुलिया पर जो रोड होता है, उसमें इतना गड्डा होता है कि गाड़ी जब चलती है, तो वह उछल जाता है । इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ कि इसतरह से जितना भी पुलिया रोड पर पड़ता है, उसका समतलकरण होना चाहिए ताकि गाड़ी का आवागमन सुगम हो । इसी तरह से मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, जिसतरह से सत्तापक्ष के माननीय विधायकों ने कहा कि कई रोड बन गये हैं और हमें जाने के लिए सरमेरा और बिहटा पथ कई वर्षों से लंबित है, कार्य इसपर पहले बंद हुआ था, फिर चालू हुआ है लेकिन जो गति से चालू होना चाहिए, उस गति से चालू नहीं हुआ है, जिसके कारण आवागमन की बहुत ही बुरी स्थिति व्याप्त है । उसीतरह से महोदय, यहाँ पर आपका पटना में दीघा से सोनपुर पुल पर बनते हुई बाईपास एम्स के लिए जो ओभरब्रीज बना है, उसका भी चाल जो है वह बहुत ही धीमी गति से है और मैं बताना चाहता हूँ एम्स में लाने के लिए यह पुल प्रस्ताव में है और उसका कार्य काफी धीमी गति से हो रही है ।

इसके साथ ही सभापति महोदय, आज खद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग पर भी मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ और लगभग सभी राज्यों में जो डी0एस0ओ0 से डीलर के यहाँ गेहूँ और अन्य खाद्य पदार्थ उपलब्ध करायी जाती है, वह जो मात्रा होना चाहिए, उस मात्रा में कटौती होता है, कमी होता है और यह कहाँ पर होता है, यह भी जांच का विषय है, हुजूर इसकी भी जांच करायी जाय ताकि जो गरीब, मजलूम और मासूमों को गरीबों को जो खाद्यान मिलता है, वह उसको उचित मिल सके ।

सभापति महोदय, आज कल्याण विभाग पर भी बोलना चाहता हूँ, उसका भी आज है हुजूर कि उसमें सबसे अधिक सी0डी0पी0ओ0 का लूट-खसोट मचा हुआ है और हर सेंटर से दो हजार रुपया लिया जाता है और पर्यवेक्षिका जांच में जाती है, तो वह भी एक हजार लेती है, यह भी जांच का विषय है, इसकी जांच किया जाय और मैं इसका प्रमाण भी देने के लिए तैयार हूँ । जय हिन्द ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): माननीय सदस्य श्री शिवचन्द्र राम, 10 मिनट ।

श्री शिवचन्द्र राम: सभापति महोदय, आज पथ निर्माण विभाग पर जो कटौती प्रस्ताव में 10 रुपया घटाने के लिए माननीय ललित कुमार यादव जी ने जो लाए हैं, उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सभापति महोदय, पथ निर्माण विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और इस विभाग के अन्तर्गत जो आना-जाना और विकास की सारी चीजें इसी पर निर्भर करती है लेकिन पथ निर्माण विभाग के नंद किशोर बाबू हमारे वैशाली जिला के प्रभारी मंत्री जी भी है और हम देख रहे हैं कि जितने भी प्रतिवेदन छापे गये हैं, वह सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा प्रतिवेदन इनका है लेकिन बेस्ट और अच्छा

प्रतिवेदन इनका है उतना हमको सड़क का उतार-चढ़ाव और वह सड़क दिखाई नहीं दे रहा है । हो सकता है कि सत्तापक्ष के लोग चश्मा की बात कर रहे थे, हमलोग लग रहा है कि चश्मा आप भी पहनते हैं और हम भी पहनते हैं लेकिन देखने का तारीका अलग-अलग है । नंदकिशोर बाबू इस भाषण में कहते हैं कि चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतरकर देखो ना, ये कौन लोग दिल में उतरेगा, इसीलिए हमारे महात्मा गाँधी सेतू जिस रोड से लोग अभी कई साथी हमारे बोल रहे थे, यह गाँधी सेतू का हाल इतना बुरा है कि प्रत्येक दिन लगभग चार घंटा, पाँच घंटा और 12-12 घंटा तक रोड जाम रहता है, कोई व्यवस्था इनका नहीं है, कहाँ इनकी पुलिस गयी, कहाँ इनका व्यवस्था गया और यह सिर्फ भाषण में जो है, ये बता रहे हैं कि हमारा यह दो लेन का काम सभापति महोदय, 2019 तक, इनका पश्चिमी लेन है, इनका पूरा हो जायेगा और सच यह है कि कागज पर कुछ है और जमीन पर कुछ दिखाई देता है, इसको आज देखने की जरुरत है । हमारे कई साथी जो उत्तर बिहार से आते हैं, वे देख रहे हैं कि कितना अभी तक तैयार हुआ है, हम दावे के साथ कहते हैं सभापति महोदय, कि जो दावा इन्होंने भाषण के साथ इस किताब में देने का काम किया है कि दिसम्बर, 2019 तक पश्चिमी लेन का दो पार्ट कभी पूरा नहीं हो सकता है और इतना ही नहीं, इसके दूसरे लेन का दिसम्बर 2020 तक का ये बता रहे हैं कि हम इसको पूरा करने का काम करेंगे, तो इसतरह का जो भाषण है, जो इनका किताब में है, वह जमीन पर कहीं भी दिखाई नहीं देता है । सभापति महोदय, सड़क की जो स्थितियाँ हैं, उस सड़क की स्थिति बद से बदत्तर बनी हुई है, इनके जो टेंडर लेने वाले ठीकेदार हैं, जो इनके पदाधिकारी हैं, वह पदाधिकारी और ठीकेदारों का जो मिला-जुला, यह जो दोनों आदमी का मिलन है और ये दोनों ही मिलकर इस कार्यक्रम को करते हैं, जिससे कि एक तरफ से इनका पिचिंग होता है और दूसरी तरफ से इनका पिचिंग उखड़ रहा है, जब हमलोग इनके पदाधिकारी से मिलते हैं, तो वे कहते हैं कि बारिश आ गया है उससे पिच उखड़ रहा है, तो जब पिच इस तरीके से उखड़ जायेगा, तो इंजीनियर
क्यों ? इंजीनियर क्यों रहते हैं और इसको देखने वाले आज क्या कर रहे हैं जिसके कारण पिच उखड़ रहा है, तो जो तरीका यहाँ चली आ रही है, बिचौलियों के माध्यम से जो काम चलाये जा रहे हैं, इस काम के कारण ही आज बिहार की सड़कों की स्थिति बद से बदत्तर बनी हुई है । सभापति महोदय, आज हमारे कितने, हम समझते हैं कि महात्मा गाँधी सेतू की आज जो स्थिति बनी है, कोई ऐसा दिन नहीं है चूंकि बगल में हाजीपुर से हम आते हैं, हम लगातार हाजीपुर में रहते हैं और देखते हैं कि कोई ऐसा दिन नहीं है, जिस दिन दो से तीन मरीज जो उत्तर बिहार से आते हैं उनकी मौत नहीं होती हो, लगातार जाम लगा हुआ है, उसपर निश्चित रुप से हम माननीय

मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि कम से कम वहाँ पर आपने जो किरान की व्यवस्था तो कराया है लेकिन वह किरान कहाँ रहता है, क्या करता है कि जब बीच में गाड़ियाँ खराब होती हैं, तो लगभग चार घंटा से पाँच घंटा तक सभापति महोदय जाम रहता है तो वह किरान किस काम का है और इसके चलते हमारे कितने मरीज मर जाते हैं, क्या इसका मंत्री जी जवाब देंगे कि जो जाम में लोग मरे हैं, उनको हम पथ निर्माण विभाग से हम अलग से मुआवजा देने का काम करेंगे, इसका माननीय मंत्री जी घोषण आज करेंगे । यही नहीं सभापति महोदय, जो सड़कों की स्थिति हमारे यहाँ है ।

क्रमशः

टर्न-21/सत्येन्द्र/12-7-19

श्री शिवचन्द्र राम (क्रमशः): हमारे यहां जो अभी सड़क बन रहा है विदुपुर से लेकर राजापाकर होते हुए सराय । सराय में यह सड़क जो है मिलती है, उसको पिचिंग कर दिया गया है जगह-जगह पर पुल जो है, मैं वैशाली जिला के विदुपुर की बात कर रहा हूँ वहां जगह जगह पर जो है, जो पुलिया बनाया जा रहा है, वह पुलिया को वैसे हीं छोड़ दिया गया है जिससे वहां काफी घटनाएं हो रही है । उसको वहां जो डायभर्सन बनाया जाना था, अभी पानी आया है और इस पानी में पूरा डायभर्सन गिर गया है । हम उसके इंजीनियर को जब बोलते हैं तो वे कहते हैं कि ठीक हो जायेगा, आवागमन बाधित हो गया है, यही नहीं सभापति महोदय, जहां भी इनकी पुलिया बन रही है ,उस पुल में डायभर्सन मजबूत बनना चाहिए और डायभर्सन बजाप्ते जो उनका है रोकन के लिए, वह अलग से दिखाई पड़ना चाहिए, उसका लिखा हुआ रहता है, वह सब कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं घेर घार नहीं है, राम भरोसे छोड़कर के लोग काम को कर रहे हैं, यही नहीं जो जहां बन गया, उस रोड में जो फिलिंग करना था वह फिलिंग भी अभी तक नहीं हुआ है और उसके 75 प्रतिशत पैसे भी ठीकेदार द्वारा उठा लिये गये पदाधिकारी के मेल से, उसी प्रकार से हमारा देसरी प्रखंड के वैशाली जिला का, चन्द्रपुरा से देसरी होते हुए महुआ तक सड़क है, इसलिए सभापति महोदय, जो देसरी प्रखंड में जफराबाद, यहां पर जो है कि पुलिया बनाया जा रहा है ,पुलिया में वहां भी फ्लैंक की वही स्थिति है जहां पर कम से कम, तीन व्यक्ति को तो मैं जान रहा हूँ जिसके कहने का मतलब एक बार उसका डायभर्सन सही से नहीं बनने के कारण और दिखाई नहीं देने के कारण तीन दुर्घटना जो है हो गया है, उसमें हमारे घायल हुए हैं मोटरसाईकिल वाले जिसका मैं पी0एम0सी0एच0 में ईलाज करवाया हूँ यह स्थिति वहां बनी हुई है । दूसरा देसरी के नहर पर, देसरी बाजार के नहर पर जो पुलिया है उसकी

भी वही स्थिति है और महुआ में नहर पर पुलिया, इसमें निश्चित रूप से वहां पर एक हमारे अल्पसंख्यक समाज के आदमी उसका जो है नहीं रेखा रहने के कारण, उसका कोई पहचान या मानक नहीं रहने के कारण उसकी दर्दनाक मौत हुई, उस समय हम वहां पर थे, उसको अस्पताल ले जाया गया लेकिन अस्पताल में उसकी मौत हो गयी, ये हाल इनके पुलिया का है, पुल बनाने वाले ठीकेदार का है । इनके ठीकेदार कहते है कि पिया भईलई कोतबलवा, सीना तान चलबई न, यह हाल इनके सरकार में चल रहा है, उसका कहना कि हमको कौन क्या कर सकता है, पदाधिकारी हमको क्या कर सकता है, पदाधिकारी ऐसे स्टीमेट बनाते हैं, सभापति महोदय, हम देखें कि पुल बन रहा था, मैं जब वहां पर गया तो ढलाई हो रहा है पुल का, हम कहे कि भाई इसको कौन देख रहा है तो मुंशी ने कहा कि हम हैं तो हमने कहा कि इसके जो कनीय अभियंता होंगे ये तो होंगे यहां पर तो कहा कि नहीं आये हैं ऐसी ही पुल ढला रहा है जबकि नियम है सभापति महोदय कि जो भी पुलिया बनता हो, पुल बनता हो उसकी ढलाई तब होगी जब वहां पर कनीय अभियंता निश्चित रूप से रहेंगे, जो कार्यपालक अभियंता हैं वे वहां पर रहकर के ढलाई कराने का काम करेंगे । इनकी सरकार इनके देखरेख में कहीं ऐसा नहीं होता है और जैसे तैसे काम को चलाया जा रहा है । क्या हो सकता है आप बता सकते हैं भविष्य में इसका, यही नहीं सभापति महोदय, राजापाकर प्रखंड के चकसिकंदर से लेकर के कहिओ होते हुए महुआ सड़क के बारे में बताना चाहता हूँ, ये सड़क के बारे में कई बार हमने सवाल किया, सवाल में भी हमको उत्तर में मिला और ये ग्रामीण कार्य विभाग का सड़क था, दो वर्ष से ज्यादा हो गये और एन0ओ0सी0 ग्रामीण कार्य विभाग ने देने का काम किया लेकिन आज तक इस सड़क का निर्माण नहीं किया गया और महोदय, आज भी कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन वहां ऐक्सीडेंट नहीं होता हो और लोग जो है वहां ऐक्सीडेंट में बराबर घायल होते हैं, ये हाल बना हुआ है उस सड़क का, और हम जब मिलते हैं इनके पदाधिकारी से तो कहते हैं कि अब आपका सड़क नहीं बनेगा, अब इसको सिक्स लेन बनाने का काम हम कर रहे हैं । अरे सिक्स लेन कब बनाईयेगा, ये जबतक सिक्स लेन बनेगा तबतक कम से कम झामा, मेटल भी जहां तहां जो है टूटा हुआ है वैसे को कम से कम कामचलाऊ तो शुरू करवा दीजिये । महोदय, हमारे नन्दकिशोर बाबू हैं उनको पहले भी कह चुके हैं और वे हमारे यहां के प्रभारी मंत्री है और अच्छे भी हैं, हमारे बड़े भाई हैं लेकिन निश्चित रूप से हमें लग रहा है कि इनका काम करने का अपना अपना तजुर्बा है, काम करने का इनका अपना जोश और खरोश है लेकिन पदाधिकारी इनको जो है गलतफहमी में डाले हुए हैं । पदाधिकारी लोग इनको पता नहीं होने देते है जिसके कारण इस तरीका की स्थिति बन रही है। महोदय, यहां हमारे सरकार कई

साथी बोल रहे थे कि हम किशनगंज से 6 घंटा में आ जाते हैं, ये बात सही है हम इसको मानते हैं लेकिन निश्चित रूप से अपने अपने सीने पर हाथ रखकर माननीय सदस्य जाने कि इनके क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है, सरकार की बात है इसलिए सरकार की वकालत ये करना ठीक है लेकिन निश्चित रूप से उनको भी दर्द है और दर्द अगर नहीं होता सभापति महोदय तो निश्चित रूप से लोग भाषण में बड़ाई पहले कर देते हैं और बड़ाई करने के बाद अंत में अपना -अपना दिल का बात कहने लगते हैं कि हमारा ये सड़क खराब है, यहां का खराब है, वहां का सड़क खराब है तो ये तमाम यही नहीं दूसरा हमारा है...

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) अब आप समाप्त करिये।

श्री शिवचन्द्र रामः सभापति महोदय,दूसरा हमारा है कि अभियंताओं की बहाली, बहुत सारा पथ निर्माण में पद खाली है सहायक अभियंता का हम कहते है, इन्होंने प्रतिवेदन में दिया है कि हम उसको जो है कि संविदा पर बहाल करने का काम कर रहे हैं । हम कहते हैं कि अगर अभी खाली है तो जो हमारे इंजीनियर, कार्यपालक अभियंता हों या कनीय अभियंता हों, हम चाहते हैं जो कि कम से कम अगर आपको निविदा निकालने में जो है दिक्कत होती है, आप नहीं उसको कर सकते हैं तो कम से कम आप जो रिटायर किये हैं उससे काम तो कम से कम लीजिये जिससे आपका काम आगे बढ़ सके ।

सभापतिः माननीय सदस्य श्री ललन पासवान ।

श्री शिवचन्द्र रामः इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

श्री ललन पासवानः सभापति महोदय, सरकार के कटौती प्रस्ताव के खिलाफ जो लाये हैं विपक्ष के लोग और सरकार के पक्ष में, पथ निर्माण विभाग के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हूँ। पहले तो मैं आपका बधाई दूं सभापति महोदय कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और माननीय नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी और बड़े भाई और हमलोगों के नेता माननीय नन्द किशोर जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वर्ष 2005 से पहले मैं पुल निर्माण से ही शुरू करना चाहता हूँ कि 6 से 7 हजार, 600 से 700 करोड़ की घाटे में पुल निर्माण चलता था और पहले पथ निर्माण लूट विभाग था और लूट विभाग के कारण कितने इंजीनियर, कितने लोग, कितने मंत्री सी0बी0आई0 जांच, अलकतरा से लेकर क्या क्या हुआ, ये मुझे कितने लोग जेल गये जेल के अन्दर, जेल के भीतर और कुछ लोग जेल में भी और कुल इंजीनियर भी, कुछ आई0ए0एस0 अफसर भी उसमें कई लोग गये तो महोदय पुल निर्माण जहां से शुरू हुआ था कई कर्मचारी तो आत्म हत्या कर रहा था, पदाधिकारियों को कर्मचारियों को पुल निर्माण निगम में पैसा नहीं मिलता था, वेतन नहीं मिलता था । महोदय, पहली बार मैं 2005 में जीतकर आया था और उस समय हमारे यहां कई रोड का शिलान्यास हुआ था और

अभी चर्चा करें तो कोईलवर छोड़कर, राजेन्द्र पुल छोड़कर, बीच में पटना में गांधी सेतु छोड़कर कहीं पुल नहीं था और आज तो सोन नदी पर ही दर्जन के करीब चाहे वह नासरीगंज हो, चाहे कोईलवर के वगल में, चाहे दीघा हो, चाहे विदुपुर बन रहा हो, बिहार सरकार के कहीं तो कहीं भारत सरकार के सहयोग से, हमारे यहां भी एक पंडुका पुल का उसे भी प्रधानमंत्री योजना में शामिल किया गया था, इंटर स्टेट कनेक्टीभिटी के चलते वह भारत सरकार में प्रस्तावित है और याद नहीं हैं जब हमलोग पढ़ते थे, तब से बस से छतरपुर, पूर्णिया, कटिहार जाया करते थे सड़कों की हालत पर हम चर्चा करेंगे, ठीक बात है लोगों को अपनी अपनी बात रखनी चाहिए करना भी चाहिए।(क्रमशः)

टर्न-22/मधुप/12.07.2019

...क्रमशः...

श्री ललन पासवान : लेकिन बिहार की सड़कों का राष्ट्रीय राजमार्गों का हाल हमलोगों ने देखा है, अपनी नंगी आंखों से देखा है । वैसे भी मेरी आदत है झूठ बोलने की नहीं और सदन में मैं रहता हूँ तो असत्य बोलने की तो बात ही नहीं है, इधर रहूं या उधर रहूं उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है । (व्यवधान) वह तो पहले आप इधर भी थे, परेशान मत रहिये, पाईपलाईन में पहले इधर ही थे । इसलिये बीमार मत होइये, थोड़ा-सा इंतजार कीजिये ।

महोदय, नन्दकिशोर भाई, माननीय मंत्री को जितनी बधाई दी जाय वह कम है, हम कह सकते हैं कि नरेन्द्र मोदी जी को, इधर नीतीश कुमार जी को, सुशील मोदी जी को हम बधाई दें तो दिल्ली में नितीन गडकरी के काम करने का तरीका, बिहार में 31 राष्ट्रीय राजमार्ग दिया, उसके पहले भी माननीय नीतीश जी भूतल परिवहन मंत्री थे, तब पहली बार, रेल मंत्री से पहले, पहली बार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों का शुरूआत हुआ माननीय नीतीश कुमार की अगुवाई में । अब सड़कों की चर्चा करेंगे तो लम्बा लाईन लगेगी । उसके बाद 31 राष्ट्रीय राजमार्ग नितीन गडकरी ने दिया और ये जो चर्चा कर रहे हैं महात्मा जी, पहले के पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव जी जाकर पहली बार नितीन गडकरी से मिलकर चाहे वह विदुपुर वाली राष्ट्रीय राजमार्ग हो, कई राष्ट्रीय राजमार्गों को माँगने का काम किया । बिहार में अभी भी 31 के बाद और जोड़ियेगा, नहीं तो बिहार गुरबत का बिहार रहा है, बिहार इतनी परेशानियों का राज्य रहा है कि लोग बिहार में सड़कों की बात देखकर, गाँव के सड़कों की बात करें तो उसपर लम्बी बहस की बात है, समय मेरे पास नहीं है, महोदय ।

बिहार के पूर्णिया, कटिहार आज से नहीं, हमने कहा कि हम जब 1981-83 के बाद 1985, हमलोग 1983-85 सेशन में पढ़ने आये थे पटना, तब से पटना और संयुक्त झारखंड-बिहार था, हमलोग दलित छात्रों की छात्रवृत्ति और उसके आरक्षण पर लड़ा करते थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इसी सदन के बैक में दोनों गेट पर मैंने ताला भी मारा है, 23 दिसम्बर, 1987 को । महोदय, जब ये चर्चा कर रहे हैं तो इनकी चर्चा पर हम कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं बल्कि मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ ।

महोदय, माननीय नन्दकिशोर यादव जी को और नितीन गडकरी को सड़कों के सवाल पर जितनी बधाई दी जाय, शब्दों से नहीं, उनके विशेषणों से नहीं, हम जितनी भी कोटिशः बधाई दें, वह बहुत कम होगा शब्दों में । बिहार विकास के रास्ते पर है और पी0डब्लू0डी0 राष्ट्रीय राजमार्ग, मेरे यहाँ भी अगर चर्चा करें तो एन0एच0-2सी, 176 करोड़ रूपया हमको मिला, उसमें बैलगाड़ी भी नहीं चल सकता था, जैसा वह कहे कि रोपणी की स्थिति थी, एन0एच0-2सी डेहरी से यदुनाथपुर का अकबरपुर तक 40 कि0मी0, हालाँकि कम्पनी जो बना रही है, मैंने कई बार कहा है कि थोड़ा उसपर रख-रखाव की जरूरत है, थोड़ा और टाईट करने की जरूरत है । बाकी जो बचा हुआ शेष भाग है, पंडुका पुल है, हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से, प्रस्तावित है इंटर कनेक्टिविटी, स्टेट का रिपोर्ट गया है । मैं नितीन गडकरी जी से 23 दिसम्बर, 2015 को, जब से मैं एम0एल0ए0 बना, तीन बार नितीन गडकरी जी से मिला पंडुका पुल पर, एन0एच0-2सी और दो-तीन सड़कों पर, जो बिहार की महत्वपूर्ण सड़कें हैं । एन0एच0-2 मोहनियाँ से भभुआ होते हुये माँ मुंडेश्वरी से चढ़ती है अधवारा, अधवारा से जाकर राबर्ट्सगंज मिलती है, राबर्ट्सगंज से जायेगी, वहाँ से निकलकर मिर्जापुर 7 और 76 में मिलती है, यहाँ से सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि दोनों सड़कों को, बम्बई की दूरी 400-500 कि0मी0 की कम होगी, सीधे जैसे हम दिल्ली जाते हैं, वैसे हम बिहार से बम्बई जा सकते हैं, उन सड़कों को सरकार ने प्रस्तावित करके, कमीश्नर और माननीय मंत्री ने भेजा है इसलिये हम धन्यवाद देना चाहते हैं । पाईपलाईन में है, महोदय । एक सड़क और है.....

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब आप समाप्त करिये । आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री ललन पासवान : महोदय, 15 मिनट समय था, 5 मिनट में ही समाप्त हो गया !

महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, एन0एच0-2सी जो मैं डेहरी-यदुनाथपुर कह रहा हूँ, वह सड़क यदुनाथपुर से रेणुकोट 75 में चोपन होते हुये जाती है, एस0एच0-5 जो उत्तर प्रदेश के जंगल से जाती है । अगर वह जुड़ जायेगी तो इधर से हम यहाँ से अम्बिकापुर, नागपुर और बम्बई खेलगाँव जाते हैं ।

महोदय, तीसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, माननीय नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ गये थे, आजादी के 70 वर्षों में पहली बार आदिवासियों, वनवासियों को देखने के लिए रेहल में जहाँ डी0एफ0ओ0 रेन्जर की उग्रवादियों ने हत्या कर दी थी, अधवारा दो जिलों को जोड़ने वाली सड़क वन विभाग के कार्य योजना में हमको लगता है कि हमने आग्रह किया था माननीय मंत्री से, वह कार्य योजना में शामिल करने के लिए हम निवेदन कर रहे हैं कि जल्दी बन जाय । एन0एच0-2 मोहनियाँ से माँ मुंडेश्वरी भभुआ होते हुये पाँच धामों को जोड़ने वाली, माननीय मंत्री जी से पिछले बजट सेशन में आग्रह किये थे तो उन्होंने स्टेट हाईवे की घोषणा इन्होंने किया है, वह पाँच धामों को माँ मुंडेश्वरी से लेकर गुप्ताधाम, शेरगढ़ किला, गीताघाट आसन, ताराचंडी धाम, 5 धामों को जोड़ती है जंगल के किनारे, प्रशासन के लिए भी स्टेट हाईवे है, माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ....

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब समाप्त करें ।

श्री ललन पासवान : दो मिनट महोदय । इन सड़कों को स्टेट हाईवे आपने धोषणा किया था, इसको आप बनवा दीजिये । महोदय, वहाँ से निकलकर भगवानपुर से माँ मुंडेश्वरी से आकर भगवानपुर और अमाह होते हुये, पुल पार करते हुये चेनारी, मलिपुर दरियाव पथ होते हुये, कसेरूआ होते हुये, ताराचंडी धाम को आती है ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब समाप्त करिये ।

श्री ललन पासवान : एक मिनट महोदय । दूसरा, आग्रह हम करेंगे, दो-तीन सड़क मेरे इलाके का है जो पी0डब्लू0डी0 में शामिल हो जाता, मैंने आग्रह किया था, सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन रामपुर जोई एन0एच0-2 सासाराम से बगल में कुम्हऊ गाँव होते हुये रामपुर जोई जाती है 3 कि0मी0 की सड़क है, एक एस0एच0 शिवसागर दरियाव, शिवसागर और चेनारी पथ जो है, से 67, वहाँ से छोटका केनार होते हुये, भांटी होते हुये रायपुर चौर, बेदा दर्शनाडीह पथ में जाती है एक सड़क है, कुदरा चेनारी एस0एच0 67 है, माननीय नन्द किशोर यादव जी ने पहली बार हमारा बनाया था स्टेट हाईवे, वह सड़क जो है, मलहर से होकर नारायणपुर होते हुये, खैरा होते हुये आती है कुदरा...

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब आप समाप्त करिये ।

श्री ललन पासवान : बस एक मिनट में महोदय ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : माननीय सदस्य, महबूब आलम ।

श्री ललन पासवान : एक किशनगंज जिला के प्रखंड ठाकुरगंज से होकर....

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : श्री महबूब आलम जी, आपका समय दो मिनट ।

श्री महबूब आलम : महोदय, मैं पथ निर्माण विभाग के माँग के विरोध में और अपने कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहा हूँ ।

महोदय, माननीय मंत्री ने पिछली बार विधान सभा के पोर्टिको में मुझसे कहा था कि महबूब आलम जी, मैंने तो आपकी सड़क कर दी । वह सड़क मेरी नहीं है, महोदय । कटिहार एस0एच0 98 की सड़क जो 70 कि0मी0 लम्बी सड़क है, अभी भी वह मुश्किल से डेढ़ गज की सड़क नहीं है, अभी उसमें लिखा गया है कि पथ के स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है । महोदय, निर्मित पुलों का इन्होंने हिसाब दिया है, गांजन और बनवोई । महोदय, गांजन और बनवोई के किसानों से जमीन जबर्दस्ती छिन ली गई और आज तक उन किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है ।

महोदय, अभी तारकिशोर जी यहाँ मौजूद हैं, कटिहार डी0एस0 कॉलेज चौधरी मोहल्ला से मिर्चाइबाड़ी कोर्ट, जो पूरा कटिहार सड़क 5 लाख की सड़क, जिसकी आबादी दिन में 15 लाख हो जाती है, वह सड़क रेल से विभाजित है। आप चौधरी मोहल्ला से कटिहार मिर्चाइबाड़ी कोर्ट में माननीय तारकिशोर जी, 45 मिनट के अन्दर पहुँचा दीजिये, मैं चुनौती देता हूँ आपको । क्यों नहीं एलिवेटेड सड़क का माँग आपने की ? कटिहार में दो एलिवेटेड सड़क की माँग होनी चाहिये और महोदय, मैं चुनौती दे रहा हूँ माननीय पथ निर्माण विभाग के मंत्री को, आप बारसोई से गाड़ी पर चढ़कर बलरामपुर से शुरू कीजिये, कटिहार शहर तक आप 2.5 घंटे से पहले नहीं पहुंच सकेंगे, उसमें चार गुमटियां होती हैं, आप गलत-बयानी कर रहे हैं ।

महोदय, हमें पटना तक आने के लिये 8 घंटे का समय लगता है, यह मैं सच बयान दे रहा हूँ । महोदय, मैं कल गया गया था अपने साथी सुदामा प्रसाद जी को लेकर तो गया जाने में और आने में मुझे, चमकी बुखार से 8-10 बच्चों की मौत हो गई, 33 बच्चे अभी एडमिटेड हैं, एक जापानी इंसेफलाइटिस से मौत हो गई है, उसका जॉच-पड़ताल, निरीक्षण करने हमलोग गये थे । लेकिन इस सरकार को शर्म नहीं कि कितने बच्चों की मौत पर इनकी अंतरात्मा जागेगी, अपने मंत्री का इस्तीफा लेगी ।

...क्रमशः...

टर्न-23/आजाद/12.07.2019

..... क्रमशः .....

श्री महबूब आलम : आप जो है मंत्री जी का इस्तीफा लें, महोदय, मैं मांग करता हूं कि अगर वे इस्तीफा नहीं देते हैं तो आप उनको बर्खास्त करें । महोदय, मैं मांग करता हूँ कि कटिहार में दो एलिवेटेड रोड है और बारसोई, सुदानी, तेतर तक एक पी0डब्लू0डी0 की सड़क है और बारसोई, घुरहार, भेरीयार से एन0एच0-34 तक, दो बलरामपुर में पी0डब्लू0डी0 की सड़क है .....

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब आप कनक्लूड कीजिए ।

श्री महबूब आलम : महोदय और मैं जोरदार ढंग से बोल रहा हूँ कि कटिहार जिला बारसोई, बलरामपुर, कदवा चूँकि यह सींमाचल का इलाका माइनोरिटी कॉम्यूनिटी का इलाका है, इसलिए यह इलाका राजनीति की उपेक्षा का शिकार है, इसलिए इसका विकास महोदय होना चाहिए, नहीं तो जोरदार ढंग से इसलिए मैं इनके मांग का विरोध करता हूँ और कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहा हूँ कि 10 रू0 की कटौती की जाय और लूट-खसोट के लिए आपको पैसा नहीं दिया जाय ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : माननीय सदस्या श्रीमती बेबी कुमारी, आपका समय दो मिनट ।

श्रीमती बेबी कुमारी : सभापति महोदय, तीन मिनट सर । सभापति महोदय, सरकार द्वारा प्रस्तुत पथ निर्माण विभाग के अनुदान की मांग के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ । महोदय, इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक राजकीय पथ रहे हैं और उसी का फल रहा है कि 2005 में राजद की सरकार जाने के बाद विधि-व्यवस्था को ठीक करने के बाद पहला टारगेट गड्ढ़े में बदल गये पथों के निर्माण करने का रहा और सरकार उसमें सफल भी रही । सभापति महोदय, आज की तिथि में आप कहीं भी मुख्य सड़कों पर आपकी गाड़ी को ब्रेक शायद ही लगे । महोदय, कल मैं परिवहन विभाग पर विपक्ष के माननीय सदस्य का भाषण सुन रही थी, जिसमें वे सड़क दुर्घटनाओं के लिए अच्छी सड़कों को जिम्मेवार ठहरा रहे थे और यही हमारी सरकार की सफलता है । मैं विपक्षी दल के इस सोच पर तरस खाती हूँ कि इन्हें कहने के लिए कुछ नहीं मिला जो वे अच्छी सड़कों को दोषी ठहरा रहे थे । सभापति महोदय, मैं पथ निर्माण मंत्री जी का भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए राज्य के शहरों में नमामि गंगे परियोजना के तहत नाला एवं एस0टी0पी0 बनाया जा रहा है । साथ ही गैस की पाईप लाईन भी बिछायी जा रही है । महोदय, इन दोनों कामों में एजेंसियां लापरवाही बरतती है और एक-एक साल तक मुख्य सड़कों को खोदकर छोड़ देती है । इसके कारण दुर्घटनायें घटती है । मुख्य सड़कों पर काम किये जाने की सीमा अवधि निश्चित की जाय । सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र के बारे में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि मुजफ्फरपुर रामदयालु से हाजीपुर पथ में मधौल के पास काफी जाम लगता है । चूँकि मधौल में रामदयालु तक सड़क चौड़ीकरण नहीं हुआ है, इसे बनवाने की कृपा करेंगे और एक रोड है जो हमारे विधान सभा का है, जिसमें डी0पी0आर0 बनकर विभाग में जमा है । माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि यह रोड काजी इन्डा चौक से मनिका बॉध तक है और बगल के कुढ़नी विधान सभा का है, बलिया से कुढ़नी होते हुए केशोपुर और दूसरा रामचन्द्राचौक से बागी महुआ तक मुख्य पथ का डी0पी0आर0 बन गया है ....

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्रीमती बेबी कुमारी : माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि इसको जल्द से जल्द बनवाने का काम करेंगे । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ और सदन में माननीय मंत्री जी को बहुत, बहुत बधाई और आभार प्रकट करती हूँ ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार, 5 मिनट ।

श्री अरूण कुमार : सभापति महोदय, मैं बजट के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए उठा हूँ। मैं बहुत कम समय में माननीय मंत्री जी को बता देना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी जो बजट आपका 70,05,56,28,000/- रू0 का है । सभापति महोदय, वित्त मंत्री और पथ निर्माण मंत्री घुमा-फिराकर के पटना के ही दायरे में सब बजट को ले लिये हैं और इसको देख लिया जाय, लिस्ट उन्हीं के किताब में छपी हुई है । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, सदन को बताना चाहता हूँ कि राज्य के जो क्षेत्रफल हैं, 95 प्रतिशत ब्लॉकों में एक कि0मी0 भी रोड बनी हुई नहीं है पथ निर्माण विभाग का, मेरा चुनौती है, मंत्री जी इसकी जॉच करा लेंगे । दूसरी बात शहर के विकास से गांवों का विकास नहीं होता है । बिहार गांवों का देश है, गरीबों का देश है, झोपड़ी में रहने वाले, खेत-खलिहान में काम करने वाले लोगों का देश है । वहां एक कि0मी0 भी रोड नहीं है । मेरे विधान सभा में पथ निर्माण विभाग को चुनौती के साथ माननीय मंत्री जी को कहता हूँ कि आप जॉच करवा लीजिए, एक कि0मी0 भी रोड नहीं है । उस कोसी से तीन मंत्री आते हैं, बात हो रही है पटना आने में 6 घंटा का । सहरसा से मधेपुरा की दूरी मात्र 20 कि0मी0 है । दो घंटा में हमलोग सहरसा से मधेपुरा जाते हैं, एन0एच0-107 की हालत है, आप इसकी जॉच करवा लीजिए, मैं शोर्ट में ही कह देना चाहता हूँ । एक पथ जिसके लिए कई बार आर0डब्लू0डी0 से पथ निर्माण विभाग को लिखा गया । सहरसा एन0एच0 से सहरसा बस्ती होते हुए समदा रोहता खेम से बभतिया एस0एच0 जो पी0डब्लू0डी0 के मानक को पूरा करता है, वह रोड बनायी जाय, जिससे मधेपुरा-सहरसा और खगड़िया का डिसटेंस 50 कि0मी0 कम हो जायेगा। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गांव जितना मालामाल होगा, गांव का तरक्की होगा, गरीब-गुरबा जितना डेवलप करेगा, उसी मानक पर शहर भी डेवलप करेगा और शहर के डेवलप से बिहार की सुदूर इलाका डेवलप नहीं हो सकता है । सभापति महोदय, मुझे एक-दो योजना के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना है । पिपरा प्रखंड मुख्यालय से एन0एच0-57 को जोड़ने वाली सड़क को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण कराया जाय, एक सड़क है मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड एन0एच0-28 बुजुर्ग चौक से मोढ़वा फातेपुर जाने वाली सड़क को पी0डब्लू0डी0 में जोड़ा जाय, एक है समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड के पूसा प्रखंड को जोड़ने वाली

बाईपास सड़क को दुर्गास्थान होते हुए मगरदही तक जाने वाली सड़क को पी0डब्लू0डी0 में जोड़ा जाय और निर्मली से सिरहुचा जाने वाली सड़क को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण किया जाय । सभापति महोदय, मैं नन्दकिशोर बाबू से निवेदन करके कहना चाहता हूँ कि गांव घर को जरूर जोड़ा जाय पथ निर्माण विभाग से । अपनी बात समाप्त करने के पहले एक और बात सभापति महोदय कहूंगा पिछड़ा-अतिपिछड़ा का भी इस बजट में आया है । आप सभी बजट को देखेंगे, अतिपिछड़ा, पिछड़ा का जा बजट है, सरकार के बजट में सबसे कम उसी को रखा गया है । जिनकी आबादी इस राज्य में 90 फिसदी है, जिनको सदियों से बाप-दादा-पुरखों के दिन से जो सवर्ण जाति के लोग हैं, जो ऊँची जाति के लोग हैं, सामन्ती लोग हैं, कई अप्रभंश शब्द कहकर के रार, सोलकट, पचपनिया, शुद्र, क्षुद्र कहकर के अपमानित करते रहे हैं, आज उन्हीं का बच्चा ....

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : माननीय सदस्य समाप्त कीजिए । माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह ।

टर्न-24/शंभु/12.07.19

श्री अशोक कुमार सिंह : सभापति महोदय, जो विपक्ष के द्वारा कटौती प्रस्ताव लाया गया है उसके विरोध में और सरकार के द्वारा जो मांग रखा गया है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं कुछ बोलने से पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कुशल वित्तीय प्रबंधन के लिए, राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी को और दिन रात कड़ी मेहनत करके सड़क के मामले में बिहार का नाम जो रौशन हमारे माननीय मंत्री नन्दकिशोर जी ने किया उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ । सभापति महोदय, 2005 से लेकर अब तक जो हमारी राज्य सरकार ने बजट लाया है वह कुल बजट का 3.49 प्रतिशत पथ निर्माण विभाग पर सरकार का यह बजट है । हमारे राज्य का पथ निर्माण विभाग सड़कों का निर्माण करता है, सुगम और बढ़िया आवागमन का साधन बनाता है । उसके साथ ग्रामीण कार्य विभाग भी राज्य में सड़कों का निर्माण करता है । सभापति महोदय, अगर दोनों विभाग के बजट को जोड़ दिया जाय तो यह 8.94 प्रतिशत हो रहा है, मतलब कुल बजट का हमारी सरकार 9 वां हिस्सा बिहार में सड़कों पर खर्च कर रही है । एक तरह से कहा जाय तो सड़क की विशेषता के विषय में, सड़क की आवश्यकता के विषय में हमारे सभी माननीय सदस्य जानते हैं हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सड़क के मामले में पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग ने जो सफलता हासिल की है निश्चित रूप

से इससे बिहार का सम्मान बढ़ा है और बिहार में रोजगार का सृजन हुआ है, आवागमन आसान हुआ है ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब आप समाप्त करें ।

श्री अशोक कुमार सिंह : माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि राज्य के किसी कोने से राजधानी पटना आने के लिए 6 घंटा से अधिक समय नहीं लगना चाहिए । उसपर कड़ी मेहनत हुई, यह कोई मामूली बात नहीं है, राज्य के हर कोने से 6 घंटा में पटना आने का मतलब राज्य का कोई इलाका इससे वंचित नहीं रहेगा । राज्य के कोने-कोने पर सरकार की नजर थी । 6 घंटा के लक्ष्य को फिर हमारी सरकार ने कहा कि इसे हम 5 घंटा में पूरा करेंगे । यह प्रस्ताव विपक्ष के तरफ से नहीं आया, यह प्रस्ताव कहीं से नहीं आया । हमारी सरकार ने स्वयं निर्णय लिया कि हम 5 घंटा में पूरा करेंगे और सरकार हर क्षेत्र में तेजी से काम रही है । 2005 से लेकर 2014 तक जो हमें आर्थिक सहयोग केन्द्र से मिलना चाहिए था वह नहीं मिला । यहां तक कि जो एन0एच0 खराब थे, हमारी राज्य की सरकार ने लगभग 900 करोड़ रूपया उस एन0एच0 को ठीक करने में अपना पैसा लगाया और राज्य की सरकार मांगती रही आज तक पैसा नहीं मिला । आज वहीं दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री पी0एम0ओ0 पैकेज से लगभग 54 हजार करोड़ रूपया भारत सरकार ने बिहार सरकार को दिया है, डी0पीआर0 बन रहा है और काम होने जा रहा है । महोदय, इसी सदन में आज नहीं हैं नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने अपना भाषण दिया था और कहा था कि हमें जो केन्द्र से मदद 2015-16 में मिला था उससे दो गुणा मिला है हर क्षेत्र में तो आज केन्द्र की सरकार केन्द्र के माननीय मंत्री श्री नीतिन गडकरी जी बिहार के लिए खजाना खोले हुए हैं कि जितनी भी सड़क बनानी होगी, हम बनाने का काम करेंगे, एन0एच0 बनाने का काम करेंगे । मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मंत्री नन्दकिशोर यादव जी को कि जो भारत सरकार गोरखपुर लखनऊ दिल्ली हाइवे बना रही थी उसको इन्होंने खींचकर बिहार के बक्सर से जोड़ने का काम किया, निश्चित रूप से ये बधाई के पात्र हैं और अनेकों सारी एन0एच0 की योजनाएं- हमारे यहां सड़कों का जाल बिछा है बिहार में, पुल पुलियों का जो जाल बिछा है, बेहिचक हम कह सकते हैं । सभी हमारे माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं जितना काम 60 साल में नहीं हुआ, जितना पुल पुलिया 60 साल में नहीं बना, जितनी सड़कें 60 साल में नहीं बनी, एन0डी0ए0 की सरकार ने 13 साल में बनाने का काम किया है और आगे भी बनाने जा रही है । मैं आग्रह करूँगा जो सरकार की ओ0पी0आर0एम0सी0 नीति है । मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो यह नीति लायी है कि लगातार सात साल तक हम सड़कें बनायेंगे ही नहीं, सात साल तक हमारी सड़कें चकाचक रहेंगी, अगर उसमें कहीं दाग भी आयेगा तो उसे संवेदक को

बनाना पड़ेगा । उसको बनाने के लिए कहीं मंत्री, मुख्यमंत्री किसी के यहां आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है । उसपर हम लगभग 6 हजार करोड़ रूपया खर्च कर रहे हैं ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : आप कन्कलूड कीजिए ।

श्री अशोक कुमार सिंह : आज चौसा मोहनिया पी0एम0ओ0 के पैकेज में बनाने जा रहे हैं माननीय मंत्री जी, लेकिन मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ । आपने इसी सदन में बनारस का चर्चा किया था, पटना बनारस उसका भी आपने मार्ग रेखन किया है, लेकिन अभी बक्सर जिला के तमाम लोग एम्बुलेंस से रामगढ़ के रास्ते बनारस जाते हैं । हम आपसे आग्रह करेंगे कि रामगढ़ चौसा मोहनिया आप बना रहे हैं उसमें मात्र 50 कि0मी0 अगर टूलेन रामगढ़ से एन0एच0 जी0टी0 रोड पर बना दें तो पटना से बनारस की दूरी तय करने में हमें मात्र 4 घंटा का समय लगेगा ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब आप समाप्त करें । माननीय सदस्य श्री अत्री मुनी प्रारंभ करें ।

श्री अशोक कुमार सिंह : एक मिनट सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी आग्रह करूँगा कि ये सड़कें ग्रामीण सड़कें हैं एक सड़क आपकी है उसको बना दीजिए ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में अपना वक्तव्य देने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, समय कम है और समय का जो आपने निर्धारण किया है उसके हिसाब से जो मुख्य-मुख्य बिन्दु है उसपर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करूँगा । यूं तो इनके बजट में जो आकार है और डिफरेंट क्षेत्रों के लिए इन्होंने जो उपबंध किया है, सड़क के निर्माण में उस सन्दर्भ में कुछ बातें जो पिछले दो वित्तीय वर्ष से लगातार उन बातों पर जोड़ दिया जा रहा है । एक सबसे बड़ा सवाल जो नक्सल प्रभावित इलाका है, चाहे वह औरंगाबाद का सवाल हो, जमुई का सवाल हो, मुजफ्फरपुर का सवाल हो, बांका का सवाल हो इन सड़कों की स्वीकृति के संबंध में पिछले वित्तीय वर्ष में भी आया और इस वर्ष में स्वीकृति प्रदान करने की बात इन्होंने कही है, लेकिन उसपर अग्रेतर कार्रवाई अभी तक सुनिश्चित नहीं की गयी है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि पथ हम बनाते जरूर है, पथ पर पैसे भी खर्च करते हैं, डी0पी0आर0 बनाने में खर्च करते हैं, उसके निर्माण पर भी खर्च करते हैं, उसके अनुरक्षण पर भी खर्च करते हैं, लेकिन इनके क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते हैं । आपका ध्यान इनकी क्वालिटी पर आकर्षित करना चाहूंगा । पूरे राज्य में जो सड़कों का निर्माण हो रहा है उसमें चाहे एन0एच0 हो, चाहे एस0एच0 हो, चाहे

नाबार्ड योजना से बननेवाली सड़क हो, सब तरह की सड़कों में सबसे बड़ा भायलेशन जो हो रहा है वह है कि जितना कैक स्वाइल है, जितना आपका स्टोन जो कैक होनेवाला है उसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है । आप जानते हैं कि जो आपका रोड सेफ्टी है उसमें स्पष्ट तौर पर यह है । जिसका उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि आप जिस स्टोन का इस्तेमाल करते हैं उसपर जब व्हीकल चलता है तो चूर हो जाता है, वह पथ के लिए उचित नहीं है । आप धड़ल्ले से उस लाल स्टोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो डेड है । उसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है जिसके कारण एक तरफ सड़कें बन रही है और दूसरी तरफ सड़कें एक बरसात में उखड़ जाती है । आप कहते हैं कि उसके मेनटेनेन्स के लिए हमने पांच साल का उसमें शर्त्त रखा है जिसको कंट्रेक्टर कहीं न कहीं संरक्षित रखेगा, लेकिन जब हमारा बेसिक कमजोर हो जायेगा सड़कों का तो स्वाभाविक तौर पर हमारे लिये चिंता का विषय है । जैसे आप देखिये एन0एच0-30 जो नीतीश कुमार जी का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है, जब केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री बने थे उस समय उसको अधिगृहित किया था उन्होंने, उसको उन्होंने उस समय लिया था । उसमें जो काम करनेवाली एजेंसियां है पूरे तौर पर मैंने कई बार ध्यान आकृष्ट किया कि वे डेड स्टोन का इस्तेमाल कर रही है । आप जाकर उस रास्ते से गुजरे भी हैं । एक तरफ से सड़क बन रही है और दूसरी तरफ से उखड़ रही है । मेरा मानना है कि सड़क तो हम बना रहे हैं, पैसा भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम क्वालिटी पर कहीं न कहीं समझौता कर लेते हैं । यह हमारे लिये सबसे बड़ा दुखद स्थिति है । दूसरी बात आप अपने भाषण में चर्चा कीजिएगा भारत माला का और चीजों का लेकिन चर्चा तो लगातार कई भाषणों में आप कर रहे हैं पटना आरा से लेकर बक्सर का क्या हुआ ? अभी अभिशाप जो झेल रहा है एन0एच0 31 जो बख्तियारपुर से बिहार शरीफ होते हुए रजौली के रास्ते झारखण्ड को जोड़ती है । लगभग 13 वर्ष बीत गये उसके चौड़ीकरण के सवाल पर, अभी तक जितने उसमें भ्रष्टाचार हुए, जितने उसमें स्कैम हुए, कितने पैसे खर्च हुए, उस फाइल को छूने में बहुत लोग डर भी रहे हैं, बड़े पैमाने पर स्कैम है । इस बात को समझ लेनी चाहिए और वो चीज......

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें ।

श्री अत्री मुनी ऊर्फ शक्ति सिंह यादव : एक मिनट में अपनी बातों को हम रख देंगे और हम अपने विधान सभा के सन्दर्भ में आदरणीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि दो तीन सड़कें जो महत्वपूर्ण है एक खासकर हिलसा से जोगीपुर जाती है कोरामा के रास्ते उसका अधिग्रहण कर लीजिए दूसरा जो हिलसा लालसे बिगहा भदौल से होते हुए धूरगांव के रास्ते एन0एच0 110 को जोड़ने वाली सड़क है उसके अधिग्रहण के

सन्दर्भ में हमने आपसे आग्रह किया है और तीसरा जो चंडी से लेकर हथकट्टा मोड़ हिलसा को जोड़ती है । इन तीन सड़कों को आप सम्मिलित कर लें यह आग्रह है और क्वालिटी पर एक शब्द कहकर खतम करूँगा महोदय, चूंकि सबके लिए है । सबसे बड़ी बात है.....क्रमशः

टर्न-25/ज्योति/12-07-2019

क्रमशः

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : सबसे बड़ी बात है कि बिटूमिन का जो हम उपयोग करते है जो संवेदक विबूमिन का उपयोग करते हैं स्टोन के साथ, उसमें क्या दिक्कत है कि आपका प्लान्ट कहॉ है और कितने टेम्परेचर पर आप वहॉ उसको मंगवाते हैं और उसका कंडक्ट करवाते हैं तो अधिक तापमान पर करवाने पर वह जल जाता है इससे लगातार सड़क निर्माण के कार्य में क्षति पहुंचती रही है ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें । अमित जी, 5 मिनट में, 4.15 पर बिना कहे खत्म कर दीजियेगा उसके बाद सरकार का उत्तर होगा ।

श्री अमित कुमार : अध्यक्ष महोदय, आज मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका मिला है । मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ मंत्री जी का कि सीतामढ़ी जाने में हमलोगों को 12 घंटा लगता था, आज दो घंटा, तीन घंटा में पहुंचते हैं। मैं जो काम करेगा मैं उसकी बड़ाई करुंगा लेकिन शर्म की बात है कि पिछले पॉच साल से वहॉ पर आर.ओ.बी. का काम चल रहा है लेकिन कम्पलीट नहीं हुआ है इसको भी आपको देखना पड़ेगा । आप जो अच्छा कीजियेगा उसको मैं अच्छी तरह से बोलूंगा लेकिन जो खराब करेगा वहॉ भी बोलने की जरुरत है अच्छी तरीके से बोल रहा हूँ । आपको ध्यान देना पड़ेगा एन.एच. 104 जो चकिया से शुरु होता है और जयनगर तक जाता है लेकिन वहॉ भाई ने बताया कि साईकिल से भी लोग आज नहीं चल सकते हैं । बहुत दयनीय स्थिति है आपको उसपर ध्यान देना पड़ेगा और जल्द से जन्ल्द उसको टेम्पोरेरली कम से कम चलने की व्यवस्था वहॉ करायी जाय कि आदमी आ जा पाय क्योंकि वह सड़क कितने जिलों को जोड़ने का काम करती है । बहुत सी बातें हैं लेकिन समय कम है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । मेरे विधान सभा में कुछ ऐसे रोड जो कि बोर्डर रोड को जोड़ती हे जो कि आर.ई.ओ. के अंडर में है पहले मैं रिक्वेस्ट करुंगा कि उन सड़को को कम से कम पी.डब्लू.डी. में लिया जाय जैसे मंझौरा से हेलमपुर है जो मेजरगंज होते हुए नेपाल जाती है पटनहिया से रामपुर है जो एन.एच. स्टेट हाई वे टू स्टेट हाई वे जोड़ती है, वह भी बौर्डर पर जाती है और खैरवा से घोड़ा चौक है यह तीन रोड है

जो इम्पोर्टेंट है और हाट है जो बौर्डर सुरक्षा के लिए भी बहुत इम्पौर्टेंट सड़क है जिसको मैं चाहूंगा कि आर.ई.ओ. से आप पथ निर्माण में लेने का काम करें । बहुत सी ऐसी बातें हैं मैं उपभोक्ता विभाग के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि सिस्टम में क्या गड़बड़ी है, आपको ध्यान देना पड़ेगा मंत्री महोदय क्योंकि आप सबसे पहले हर गोडाउन में तौलने की व्यवस्था करायें । डोप डिलीवरी सिस्टम में हर डिलर को सुविधा रहनी चाहिए लेकिन क्या वह माल तौल कर डिलर के यहाँ जाता है ? उसका भोगना पड़ता है वहाँ के जो लोग उस डिलर से माल लेते हैं, सामान लेते हैं एक एक किलो डेढ़ डेढ़ किलो और महीना में नौ बारह के जगह आठ से नौ डिलर लोग बांटते हैं उसपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, कैसे उसको कंट्रोल किया जाय । सबसे पहले आप वहाँ पर कांटा लगवायें ताकि उचित तौल हो और उचित माल देने का काम करेगा । दूसरी बात है अभी जो डिलरों की बहाली हुई है पूरे बिहार में उसमें भी आपको गौर करना पड़ेगा जो विद्यार्थी 72 परसेंट हैं उसको 27 परसेंट कर दिया गया है । उसमें लाखों का गबन हुआ है । लाखों लाख रुपया लेकर बहाली करने का काम किया है सरकार ने । बड़े शर्म की बात है और जो लोग वहाँ अत्याचार कर रहे हैं उसपर भी आपको ध्यान देना होगा ।

अध्यक्ष : अब एक मिनट बचा है ।

श्री अमित कुमार : सर, मैं बोलूंगा । कुछ बातें ऐसी हैं जो कि इस बजट से बाहर बोलना चाहता हूँ लेकिन मैं शिक्षा के प्रति भी आपको बताना चाहता हूँ और उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा । आज जो गरीब गुरबा के बच्चे हैं जो बी.एड. नहीं करेंगे तो एग्जाम नहीं दे सकते इसलिए मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जिनके पास दो लाख रुपया नहीं है, प्राईवेट कॉलेज से बी.एड. नहीं कर सकते हैं, उनके बच्चे को शिक्षक के लिए टी.ई.टी. एग्जाम में बैठने के लिए आप क्या व्यवस्था करना चाहेंगे क्या आप पूरे जिला में पूरे बिहार में एक भी ऐसा जिला बताईये जहाँ सरकारी बी. एड. कॉलेज खुला हो और अच्छे रुप से चल रहा हो ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें अमित जी । ठीक है ।

श्री अमित कुमार : समय ज्यादा नहीं है लेकिन फिर से धन्यवाद करता हूँ ।

श्री महेश्वर प्रसाद यादव : अध्यक्ष मुझे एक मिनट दिया जाय ।

अध्यक्ष : क्या बोल रहे हैं ?

श्री महेश्वर प्रसाद यादव : बोलना यह है कि पी.डब्लू.डी. की सड़क मेरे विधान सभा क्षेत्र में सर्फुद्दीनपुर से बंदरा प्रखंड मुख्यालय को जोड़ती है । ठीकेदार एक साल से टेण्डर लिए हुए है ।

अध्यक्ष : वह लिखकर दे दीजियेगा मंत्री जी देख लेंगे ।

श्री महेश्वर प्रसाद यादव : दबंग ठीकेदार है । जो सड़क हाजीपुर से मजफ्फरपुर तक फोर लेन जाती है जो पूरे उत्तर बिहार को रास्ता देती है वो मुजफ्फरपुर बाई पास पॉच वर्षों से नहीं बन रही है । मैं चाहूंगा कि सरकार अपने वक्तव्य में इसका जिक्र करे ।

अध्यक्ष : श्री कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव। कोई एक खाली सड़क बोलिये कोई बाउन्ड्री मत मारियेगा नहीं तो समय खत्म हो जायेगा ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता और आसन के प्रति आभार प्रकट करते हैं ।

अध्यक्ष : इसी में समय चला गया ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : आज पथ निर्माण विभाग के अनुदान के पक्ष में कटौती प्रस्ताव के बारे में बोल रहे हैं । हम एक मिनट बोलेंगे, उससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। कटौती प्रस्ताव के पक्ष में हम बोलने के लिए खड़े हुए हैं महोदय ।

अध्यक्ष : आप खड़े हैं सब लोग देख रहे हैं ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, आज किताब देखे हैं कि 5 घंटे में बिहार राज्य के किसी भी कोने से राजधानी पहुंचने का सरकार ने संकल्प लिया है । चिराग तले अंधेरे वाली बात है हम जहानाबाद से महज 60. कि.मी. दूरी से आते हैं जहानाबाद से, एन.एच. 83 का जो हाल है । हमें जहानाबाद से आने में 3 से चार घंटे लगते हैं । उसी तरह का एन.एच.110...

अध्यक्ष : अब हो गया, सुदय जी , ठीक है, सुदय जी एन.एच. 83 का समझ गए ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद होते हुए जो अरवल रोड जाती है उसकी हालत एकदम खराब है । प्राय: एक्सीडेंट होते रहता है । उसके रख रखाव पर कोई ध्यान नहीं है । उसे ठीक कराया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है, अब वाद-विवाद समाप्त हुआ । माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । इसके पूर्व सिर्फ मैं आपको स्मारित करना चाहता हूँ कि आप सबको मालूम है कि कल दिनॉक 13 जुलाई, 2019 को सेंट्रल हॉल में राज्य में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जो आपदाजनक स्थिति है उसपर विमर्श के लिए महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है । आप सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि उक्त विमर्श में अवश्य भाग लें । इस विषय पर 10 बजे से पूरा दिन तक, जबतक आप अपनी राय देते रहेंगे, उस बैठक और विमर्श की कार्यवाही तबतक चलती रहेगी और इस बीच में नाश्ता,पानी, चाय, खाना सब रहेगा । इस विषय पर अपने सुझाव और अनुभव अवश्य साझा करें ताकि सरकार को भी उसके समाधान की पहल करने में सुविधा हो सके ।

अब पथ निर्माण विभाग की मांग पर सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, पथ निर्माण विभाग के वर्ष 2019-20 के अनुदान मांग के प्रस्ताव पर आज सदन में पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं । महोदय, मैं सब के विचार को बड़े गौर से सुन रहा था । नोट भी कर रहा था । महोदय, मुख्य रुप से मुझे दिखायी पड़ रहा है मुझे एक बात समझ में नहीं आयी कि कटौती प्रस्ताव सिद्दीकी जी क्यों ले आए, आप नहीं लाते तो मुझे कोई गुरेज नहीं था ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : हम इसलिए लाए कि जब आप इधर थे न, तो आप लाते थे तो उसी का अनुकरण किया ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, जब इन्होंने छेड़ ही दिया तो छोड़ कैसे दूँ इनको । महोदय, इसलिए लाता था कटौती प्रस्ताव । आप अपने विभाग का पैसा खर्च नहीं करते थे। महोदय, मेरे पास आंकड़े हैं ।

(व्यवधान)

मैं सही सही बोल रहा हूँ । महोदय, 2003-04 में पथ निर्माण विभाग का जो बजट था मैं उसकी संख्या नहीं बोलता हूँ । संख्या बोलने का कोई औचित्य नहीं है । खर्चे का परसेंटेज था 42.36 परसेंट, 2004-05 में खर्चे का परसेंटेज था 42.3 प्रतिशत, 2005-06 में खर्चे का परसेंटेज था 40.62 परसेंट और महोदय, जब सरकार एन.डी.ए. की बन गयी बिहार के अंदर तो 2006-07 में खर्चे का परसेंटेज था 92.86 परसेंट, 2007-08 में 96.24 परसेंट, 2008-09 में 99.5 परसेंट, 2009-10 में 99.98 परसेंट ।

क्रमशः

टर्न-26/12.07.2019/बिपिन

श्री नंद किशोर यादव, मंत्रीः क्रमशः 2010-11 में 98.61 परसेंट, महोदय, इस प्रकार से 1998-99 करते-करते 2018-19 में 97.30 परसेंट खर्च हुआ है महोदय । मैंने इसलिए कहा कि मैं सिद्दिकी साहब से उम्मीद नहीं करता था, ललित जी के दर्द को मैं समझता हूं महोदय । चूंकि इनको मंत्री बनने का अवसर नहीं मिल पाता है । बड़ी कोशिश के बाद भी जो इनके मन के अंदर प्रकट होता रहता है अपने भाषण के दौरान और इसीलिए आपने देखा होगा महोदय, केवल अपने विधान सभा के दो सड़क के लिए इन्होंने अपनी पार्टी के समाननीय सदस्यों का 22 मिनट ले लिया महोदय । आप खुद इस बात के गवाह रहे हैं ।

महोदय, मैं कह रहा था कि कटौती का प्रस्ताव तो सामान्यतः तब आता है जब लोग कहते हैं कि आप खर्च भी नहीं करते हैं तो पैसा लेकर क्या करिएगा ? लेकिन महोदय, आंकड़े गवाह हैं इस बात के कि पथ निर्माण विभाग बिहार का एक ऐसा विभाग है जिसने हमेशा जो धनराशि आपने दी है, वह हम लेकर नहीं आते हैं, सदन देता है हमें, जो राशि धनराशि सदन देता है हमें, उस राशि का अधिकांश पैसा सड़कों के निर्माण पर हम खर्च करते हैं । आंकड़े इस बात के गवाह हैं महोदय । महोदय, कई लोगों ने अपनी बात कही है अलग-अलग महोदय । एक तरफ कटौती का प्रस्ताव लाते हैं और दूसरी ओर ललित जी कह रहे हैं सड़क बना दीजिए । कई माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किए हैं महोदय, अधिकांश ...

(व्यवधान)

आपकी बात कहां कर रहे हैं, हम ललित जी की बात कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

सुन लो भइया, सुन लें आप । सुनिए सिद्दिकी साहब, आपको अपने सड़क के बारे में आग्रह करने की कोई जरूरत नहीं है, नंद किशोर बिना भेदभाव के सड़क बनाता है । किसी को पैरवी करने की जरूरत नहीं है ।

महोदय मैं कह रहा था कि जब कटौती लाए हैं तो कहते कि मेरा सड़क छोड़ दीजिए । फिर क्यों कहते हैं कि मेरा सड़क ले लीजिए । आप जितने माननीय सदस्यों के भाषण सुने होंगे, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, महोदय सब ने कहा कि पथ निर्माण विभाग में ले लीजिए । यह सड़क का अधिग्रहण कर लीजिए । अरूण जी भी कह रहे थे कि इस सड़क को ले लीजिए । अपने नहीं कह रहे थे, इनके कहने पर कह रहे थे । हम देख रहे थे यदुवंश बाबु का । उनके कहने पर कह रहे थे ।

तो महोदय, कह रहा था आपसे, माननीय सदस्य की बात मैंने सुनी है। आज आपको मौका नहीं मिला भाषण देने का, व्यक्तिगत मामला तो हम अलग से फरिया लेंगे, अभी तो बात सामान्य हो रही है । महोदय, मैं कह रहा था कि जो माननीय सदस्य हैं, सब सड़क ले लीजिए पथ निर्माण विभाग में । क्यों कह रहे हो भइया ? क्यों कहना चाहते हैं आप ? जब हम नकारा हैं, हम काम नहीं कर सकते, सड़क बनते उखड़ जाती है तो क्यों कहते हो कि पथ निर्माण विभाग में ले लीजिए । महोदय, पथ निर्माण विभाग में ले लीजिए, ये विरोधी पार्टी के माननीय सदस्यों के कहने का अर्थ ही साफ है कि इनको भरोसा है पथ निर्माण अगर बनाएगा तो अच्छी सड़क बनाएगा और पथ निर्माण इस काम को पूरा कर सकता है । महोदय, भरोसा लेकिन मजबूरी है.....

(व्यवधान)

बैठिए । अत्री मुनी जी बैठिए । महोदय, यह भरोसा है । आपकी जानकारी के लिए अब ग्रामीण कार्य विभाग ने भी अपने सड़कों के मानक को बदल लिया है और मेंटेनेंस पॉलिसी वहां लागू किया है । अब कोई विभाग की सड़कें खराब नहीं बनेगी, यह जानकारी आपको होना चाहिए ।

महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब ललित जी ने कहा कि तेजस्वी यादव जी ने टेंडर की फाइल अपने यहां लेने से मना कर दिया था । आप गलतफहमी के शिकार हैं ललित बाबू । यह काम विभाग में सबसे पहले किसी ने किया तो वहां बैठे आपकी पार्टी के सिद्दिकी साहब, इन्होंने इस काम को पहले लागू किया और मैं जब पथ निर्माण मंत्री बना, मैंने भी उस नियम को लागू किया । तेजस्वी जी ने केवल मेरे बनाए हुए नियम का पालन किया है । जानकारी आपको होना चाहिए, नहीं तो पूछ लीजिएगा उनसे, सिद्दिकी साहब से । जानकारी रखो भइया ।

(व्यवधान)

गुस्सा मेरे उपर क्यों फोड़ रहे हो ? में कहां कह रहा हूं । मैंने कहां कहा कि उल्लंघन हो रहा है । मैंने नहीं कहा लेकिन यह जो श्रेय लेना चाहते हैं उस व्यक्ति का श्रेय कमजोर करना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं । उस व्यक्ति ने प्रारंभ किया था यह । मैं सच्चाई से इंकार नहीं कर सकता ।

महोदय, यह जो भेदभाव का आरोप लग रहा है, बेबुनियाद है । अगर सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिलता विरोधी पार्टी के सभी सदस्यों को, तो स्वर बदल जाते महोदय । कहना पड़ता कि मेरे विभाग की सड़क बनी है । यह और बननी चाहिए। यह तो स्वाभाविक है । महोदय, विकास तो स्वत: प्रक्रिया है । कोई एक दिन में थोड़े ही यह होता है । और कितनी सड़कें हमने बनाई । अगर मैं सड़कों का आंकड़ा आपको दूं महोदय कि कितना विकास हुआ है बिहार के अंदर तो मुझे लगता है, ठीक ही कह रहे हैं, बहुत पहले नहीं शुरू करना चाहिए, लेकिन महोदय, बताना चाहता हूं आपको, जब हम सरकार में आए, इन्होंने क्या किया, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा लेकिन मैंने क्या किया, मैं इसकी चर्चा करना चाहता हूं महोदय । इसलिए हमको बोलने का अवसर मिला है । इनको जो अवसर मिला तो इन्होंने अपनी बात कही है । महोदय, जब हम सरकार में आए तो उस समय बिहार के अंदर जो कुल मिला कर पथ निर्माण विभाग की सड़क थी वह थी 14,693 कि0मी0 । अब महोदय आज की तिथि में 22.146 कि.मी. सड़क, महोदय, पथ निर्माण विभाग की है । यह कोई बहुत बहादुरी की बात नहीं है । मैंने सड़कों का अधिग्रहण आप सब के कहने पर किया । इसलिए बढ़ गई सड़कें, लेकिन महत्व की बात है महोदय । आप एन.एच. को छोड़ दीजिए । कई माननीय सदस्यों ने जो सड़कों के खराब होने की शिकायत किए हैं ..

(व्यवधान)

बोलने दीजिए महोदय । गलत बात है । यह तो बात ठीक नहीं है महोदय ।

अध्यक्ष : आप बोलते रहिए । आप बोलिए ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री: बैठिए । महोदय, एन.एच. की बात बहुत लोगों ने कही है । एन. एच. 83, एन.एच. 104, 106, 107, मैं उसकी चर्चा करूंगा महोदय, मगर एन.एच. को मैं माइनस कर देता हूं, चूंकि आप जानते हैं एन.एच. भारत सरकार बनाती है, वहां से पैसा आता है उसी से बनता है । मैं उसकी चर्चा बाद में करूंगा लेकिन जो स्टेट बनाता है चाहे वह स्टेट हाइवे हो, चाहे वह मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो, उसके आंकड़े बड़े मजेदार हैं महोदय । मैं आपको बताना चाहता हूं । महोदय, इंटरमीडिएट लेन बिहार में, सिंगल लेन की बात छोड़ दीजिए, सिंगल लेन तो बदलते रहते हैं। इंटरमीडिएट लेन बिहार में 2005 में 1705.45 कि.मी. था महोदय, आज के डेट में इंटरमीडिएट लेन बिहार के अंदर महोदय, 4705.42 कि.मी. है । उससे भी मजेदार महोदय, बिहार में जो डबल लेन की सड़कें हैं जो लोग कहते हैं कि हम सड़क नहीं बनाए हैं महोदय, उनके लिए आंकड़े बड़े मजेदार हैं, उनके ऑंख खोलने वाले हैं । जब हम सरकार में आए 2005 में, उस समय महोदय, बिहार में डबल लेन केवल 160.61 कि.मी. महोदय और महोदय, मुझे गर्व के साथ कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज बिहार में 4359.99 कि.मी. डबल लेन की सड़कें बना लेने का काम हमारी सरकार ने पूरा किया है । महोदय, इन आंकड़ों का जिक्र केवल आपक सामने इसलिए किया क्योंकि सच को कहने का साहस होना चाहिए । सच को कहो । कोई कमी है तो बताइए । सदन में चर्चा महोदय होती ही है इसीलिए कि अगर सरकार के द्वारा किए गए काम में कोई कमी है, हमारे सदस्य इंगित करें उसको और उसको इंगित करते हैं तो सरकार सुधारने का प्रयास करती है लेकिन क्या कहे जा रहे हैं हम ? कौन-कौन सी बात कह रहे हैं ? अवधेश बाबू को देखिए जरा । अवधेश बाबू पूरा पढ़ते नहीं हैं । आप तो पढ़े-लिखे आदमी हैं । आप तो विद्वान आदमी हैं ..

(व्यवधान)

सुनिए अवधेश बाबू, सुनिए । बात न सुनिए । आप जरा खोलकर पृष्ठ 46 पढ़िए । महोदय, गया जिले के अंदर 3 पैकेज है । पैकेज वन, पैकेज टू, तीन पैकेज है और एक शेरघाटी का तो अभी डाला ही नहीं है मैंने उसमें । तो महोदय, 46 नम्बर पेज पढ़िए और 1391 से 406 नंबर तक की सड़क देखिए । शहर की नहीं है, गया जिले की दूसरी सड़कें हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं और शेरघाटी का तो लिस्ट ही नहीं है उसमें । इसलिए आप चिंता मत करिए । आप गलतफहमी के शिकार मत रहिए अवधेश बाबू । यह एन.डी.ए. की सरकार है और जब एन.डी.ए. की सरकार...

(व्यवधान)

श्री अवधेश कुमार सिंह : पेज 44 पढ़ा है...

(व्यवधान)

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री: मैं कहां कहा ? मैं तो कहा 46 पढ़िये न !

(व्यवधान)

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री: अवधेश बाबू ...

अध्यक्ष : जब आपके जिले की चर्चा 46 पर है तो 44 क्यों पढ़ रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री: महोदय, 44 भी है, 45 भी है, 46 भी है .... क्रमशः ....

टर्न : 27/कृष्ण/12.07.2019

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्री (क्रमशः) : महोदय, सड़क के निर्माण के मामले में तो बिहार की वर्तमान एन0डी0ए0 सरकार ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है उसकी चर्चा केवल यही नहीं, सर्वत्र हो रही है । जब मैं आगे चर्चा करूंगा तो आपके ध्यान में बात आयेगी । महोदय, जो भेदभाव की जो बात कही गयी है, माननीय सदस्य ने यह ठीक है कि पॉलिटिकल बाध्यता के कारण आपने यह आरोप लगाया होगा । लेकिन जब आप स्वयं अपने दिल पर हाथ रखेंगे तो आप स्वयं समझेंगे कि आपने गलत आरोप लगाया है । मुझे इसका पूरा भरोसा है । महोदय, भेदभाव किस से करेंगे हम ? कौन हम से अलग है ? प्रदेश के अंदर 40 में से 39 सीटें जनता हमारे गठबंधन को देती है। किस से भेदभाव करेंगे हम ? कहां भेदभाव है ? लेकिन महोदय, जिनको भेदभाव करके सरकार चलाने की आदत रही है, उनको हर बात में भेदभाव दिखाई पड़ता है । मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं ।

महोदय, मेरे मित्र शिवचन्द्र राम जी भाषण दे रहे थे । महोदय, मैं आप को कुछ संकेत दे रहा हूं । वे यह नहीं कह रहे थे कि सड़क नहीं बन रही है। महोदय, वह कह रहे थे कि जो सड़क बन रही है, जो पुलिया है, उसका डायवर्सन ठीक नहीं है। महोदय, यह इस बात का संकेत है कि सड़कें बन रही है, काम हो रहा है । लेकिन इनको मेरे ऊपर इतना ज्यादा विश्वास है, हमारे विभाग पर है, हमारी सरकार पर है कि डायवर्सन की खराबी भी इनको कष्ट देता है, मैं उस कष्ट को दूर करूंगा, शिवचन्द्र बाबू, आप इसका भरोसा रखें । गुणवत्ता के बारे में बड़ी-बड़ी बात हो रही थी । लोग कह रहे हैं कि हम गुणवत्ता से समझौता कर रहे हैं ।

(व्यवधाान)

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अवधेश बाबू आजकल गर्म रहते हैं । लेकिन महोदय, आप ने जो सामने लिख दिया है- संबंधित जाति लोग कटु और लघु बातें कहते हों, उन की बातों पर ध्यान मत दें और अपने उत्तर से उनका हृदय वाणी और मन शांत करें । यह हम रोज पढ़ते रहते हैं ।

अध्यक्ष : कोशिश भी करते रहिये ।

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्री : जी, कोशिश भी करते रहिये । महोदय, मैंने सड़कों के निर्माण के संबंध में आप को बताया कि कितनी की है । सड़क बनाने का काम तो मैंने बहुत कर लिया । मैंने कहा कि यह लगातार चलनेवाली प्रक्रिया है । बिहार तो उससे बहुत आगे बढ़ गया । अब बिहार तो उससे बहुत दूर जाना चाहता है । हमारे मित्र जब अकेले में मिलते हैं तो कहते हैं कि कैसे कर लेते है । कैसे इतना सड़क बना लेते है आप ? मैं कहना चाहता हूं - जीतने का हुनर मैंने इस सूरज से सीखा है, जो चीरते हुये अंधेरे को जग को उजाले से भर देता है । यह तो हमारा संस्कार है । अभी तो भाई शुरू ही किये हैं ।

अध्यक्ष : अभी सब्र से रहिये ।

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : अभी से पांव के छाले मत देखो, अभी यारो सफर की इल्तजा है यानी शुरूआत है ।

महोदय, मैं कह रहा था कि निर्माण की प्रक्रिया से हम बहुत आगे बढ़ गये हैं । महोदय, हमलोगों ने जो सड़क मेन्टिनेंस की पॉलिसी लाया है 2013 में । महोदय, जेनरली होता था, माननीय सदस्य बोल रहे थे, इतनी कम जानकारी उनको है, मुझे आश्चर्य होता है । महोदय, पहले सड़कें बनती थी, गड्ढे बनते थे और सुन लीजिये माननीय सदस्य जो कह रहे थे, गड्ढे और बढ़े होने का इंतजार करते हैं । महोदय, वह जमान कब का बीत गया । अब जमाना दूसरा हो गया । अब तो ये नियम बन गये हैं कि जो सड़के बनेगी, रोड मेन्टिनेंस पौलिसी में रहेगी, जितनी दिन रहे । उसके बाद नया पॉलसी बन यगी OPRMC यह जो OPRMC यह तो अलग प्रकार की चीज हो गयी । अब तो सड़को को लगातार उसी प्रकार बनाते रहते हैं जैसे बनी थी। महोदय, 2013 से 2018 के बीच में बिहार के अंदर 2,579 करोड़ की लागत से 9,064 किलोमीटर सड़कों का सफलतापूर्वक संधारण करने का काम हम ने पूरा किया है । इसीलिये जो सड़के पांच साल बनी, जो सड़कें 6 साल बनी, आज वे सड़के उसी प्रकार मोटरेबुल है, उसी प्रकार चलने लायक है, चकाचक है, चिकनी है । महोदय, उसका बड़ा कारण यह मेन्टीनेंस पौलिसी है । इसलिए अब इसका इंतजार नहीं होता है कि गड्ढे और बड़े कब होंगे । रीवाईज्ड एस्टीमेट कैसे बनेगा ? अब यह

समस्या तो पथ निर्माण विभाग में खत्म हो गयी । अब तो सड़कें बनेगी और उसके मेन्टीनेंस का काम चलेगा और मैंने पांच साल इस काम को मैंने पूरा किया । इस OPRMC-1 के तहत पांस वर्षों तक सड़कों के मेन्टीनेंस का काम किया गया । परिणाम बड़े अच्छे आये । लेकिन कई प्रकार के अनुभव भी आये । कठिनाईयां भी आईं और 2018 में अधिकांश पैकेज की अवधि पूरे हो गये तो हमलोगों ने OPRMC-2 चालू किया और इस के तहत सात सालों तक सड़कों के मेन्टीनेंस करने का हमने निर्णय लिया है । महोदय, हमलोगों ने 13,064 किलोमीटर पथों को इस OPRMC-2 में शामिल किया है और हम ने निर्णय लिया है कि पथ निर्माण विभाग की जो भी सड़कें बनेगी, बनने के बाद वह OPRMC में शामिल होगी । तब सड़कों के खराब बनने का सवाल, सड़कों के परत उखड़ने का सवाल, सड़कों के मेन्टीनेंस नहीं होने सवाल, महोदय, यह विषय समाप्त होनेवाला है बिहार से । मैं एन0 एच0 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं स्टेट हाई-वे और मेजर डिस्ट्रीक्ट रोड की । तो आनेवाले दिनों में तो यह विषय ही नहीं रहनेवाला है । हां जो सड़कें मैंने अपग्रेड की है, उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा । तब शायद लोगों की समस्याओं का समाधान हो पायेगा । उनको संतुष्टि मिलेगी । महोदय, कितने प्रावधान इसमें हैं । आप जरा सोचिये तो । यह कितनी हिम्मत का काम है। कितनी पारदर्शिता है ? मैंने जिन-जिन सड़कों को OPRMC में शामिल किया है, महोदय, आप को इस सरकार की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, पारदर्शिता की दाद देनी पड़ेगी । मैंने सारी सड़कों की सूची मैंने सारे माननीय सदस्यों को बंटवा दिया है । आप देख लीजिये सूची । महोदय, यह साधारण बात नहीं हैं। शिकायत करने पर लोग सुधार करते थे । लेकिन हम एडवांस में सूची वितरित करने का काम कर रहे हैं । मैंने प्रावधान किया है, मैं यह भी बताना चाहता हूं, सात सालों के लिये नियम होगा और आनेवाले दिनों में जो भी सडकें बनेगी, वे इसमें शामिल हो जायेगी । मैंने इसमें तय किया है हर चार साल के बाद उसके सतह नवीकरण का भी काम होगा । केवल रीपेयर नहीं होगा । चार साल में उसकी सतह भी बनाया जायेगा । महोदय, अब तो हम उसके आगे बढ़कर उस की जो राईडिंग क्वालिटी है, उस को भी इन्टरनेशनल लेवल का बनाने का भी हमलोगों ने नये कॉट्रैक्ट का भी प्रावधान किया है । महोदय, प्रत्येक वर्ष 7 वर्षों के लिये यूनिक मेंटीनेंस प्लान बनाया है। इनिशियल जस्टीफिकेशन कब होगा, ऑर्डिनरी मेन्टीनेंस का काम कब होगा, प्रीयोडिक मेन्टीनेंस का काम कब होगा,माईनर इम्प्रूवमेंट का काम कब होगा, सबकी समय-सीमा तय किया गया है । उस समय सीमा में उस को काम करना पड़ेगा और अगर कोई काम नहीं करेगा, उसके लिये भी मैंने प्रावधान किया है । सेवा शर्त्त में त्रुटि होने पर दंडात्मक प्रावधान को अधिक कठोर बनाये हैं ।

महोदय, हमने इसकी भी व्यवस्था किया है । मान लीजिये कोई कौन्ट्रेक्टर गड़बड .करें, कहने के बाद भी काम नहीं करे तो हमने इसमें प्रावधान किया है हम दूसरे कौन्ट्रैक्टर से काम करा लेंगे और भुगतान में से उस का काट लेंगे । इसलिए किसी के भागने का भी सवाल पैदा होता है ।

महोदय, रोड मार्किंग हम ने प्रत्येक दो साल में कराने का निर्णय लिया है। झाड-्झंखर हटाना हमने प्रावधान इसमें किया है । आप जानते हैं कि रोड एम्बुलेंस हम ने OPRMC डाला था, अगर छोटे मोटे गड्ढे हो गये तो उस रोड एम्बुलेंस में सारी व्यवस्था हल्की-फुल्की थी, वही मिक्स करता था, वही डालता था, रोड रॉलर चला देता था, सब ठीक हो जाता था । इसमें भी हैं । कुल मिलाकर 72 पैकेज है । बिहार की सड़कों को हमने बांटा है । लेकिन उसमें मैं जरूर यह कहना चाहता हूं कि इसमें से 69 पैकेज का काम प्रारंभ हो गया है और दो पैकेज ऐसा है जो अभी न्यायालय के कारण काम शुरू नहीं हुआ है। 6 पैकेज ऐसा है जिसका अभी OPRMC की अवधि समाप्त नहीं हुई है वह भी मेन्टीनेंस में शामिल है । अवधि पूरे होने के बाद उसका फिर से टेंडर करेंगे ।

महोदय, हमने कहा कि हमने रोड एम्बुलेंस बनाया है । जब से सडकें चिकनी होती जा रही है आप जानते हैं एक्सीडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है । पहले गड्ढे थे तब एक्सीडेंट होते थे, अब सड़के अच्छी हैं इसएिल एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो हमने उसकी भी चिन्ता की है । इस OPRMC में हमने हर पैकेज में मेडिकल एम्बुलेंस का भी प्रावधान किया है । हर पैकेज में एक मेडिकल एम्बुलेंस होगा जो वह नजदीक के अस्पताल में रखा जायेगा, उसका नंबर, उसके ड्राईवर का नंबर, मेडिकल स्टाफ का नंबर, कार्यपालक अभियंता का नंबर, सब का नंबर अस्पताल के प्रशासक के पास भी रहेगा और अधिकारी को भी रहेगा और उस सड़क पर दोनों ओर साईन बोर्ड लगाकर ये सारे नंबर्स प्रकाशित किये जायेंगे ।

क्रमश :

टर्न-28/अंजनी/12.7.19

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : क्रमशः... भगवान न करे अगर किसी को दुर्घटना हो जाय तो अविलम्ब उसको मेडिकल एम्बुलेंस की सुविधा प्राप्त हो जाय निःशुल्क । शुल्क नहीं लगेगा, तो हम सड़कें भी बना रहे हैं, सड़कें मेन्टेन भी कर रहे हैं, चिकनी सड़कों के कारण एक्सीडेंट होता है, उसकी भी चिंता इस मेन्टेनेंस पॉलिसी में कर रहे हैं । महोदय, ये आप कह रहे हैं, कैसी-कैसी बात कर रहे हैं ?

महोदय, यह केवल हवा में नहीं है, मैंने टॉल फ्री नम्बर जारी किया है- 18003456233, कोई भी आदमी शिकायत कर सकता है । व्हाटस-ऐप नम्बर जारी किया है 9470001346 । महोदय, मैंने ई-मेल दिया है, complainroadmaintainance@gmail.com, मतलब सब प्रकार की व्यवस्था इसमें की गयी है । ऑनलाईन मोनेटरिंग सिस्टम का इसमें इन्तजाम किया है । इस ऑनलाईन मोनेटरिंग सिस्टम में निरीक्षण प्रतिवेदन अपलोड किये जाने की पूरी व्यवस्था है । ऐसा साफ्टवेयर बना रहे हैं कि सब प्रकार की बातें यहां हेडऑफिस में बैठकर लोग देख सकते हैं । महोदय, हमने इस बार ओ0पी0आर0एम0सी0-फेज-2 में जो हम रोड एम्बुलेंस रखते हैं, उसमें कैमरा भी लगा रहे हैं ताकि वहां जो बनाने जायेगा और रिपेयर करने जायेगा, उसका फोटो भी खिंचा जायेगा और रियल टाईम विडियो मुख्यालय में उपलब्ध रहेगा, जिसके कारण पथों के संधारण में सहुलियत होगी और वास्तविक स्थिति का अन्दाजा होगा । हम इतनी दूर तक जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि रोड उखड़ रहा है ! कैसे हो सकता है । मैं और उससे आगे जाना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी अलग प्रकार के स्वभाव के आदमी हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं कभी, एक काम करो, कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, अगर किसी एक काम में सफलता मिल गयी, और उसमें अच्छा कैसे किया जा सकता है, इसका विचार करते हैं महोदय। जब इन्होंने देखा कि बढ़िया रोड बना रहा है, मेन्टेनेंस पॉलिसी भी बढ़िया ले आया है तो तो इन्होंने रोड विभाग को बांधा है और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो सड़कें ओ0पी0आर0एम0सी0 में मेन्टेन की जा रही है, अब बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम,2015 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है । आपका सवाल केवल नहीं है, आम आदमी कोई अगर रोड में गढ़्ढे की शिकायत, इन सड़कों के बारे में जिसकी किताब मैंने आपको दी है, मैं इसको अखबार में प्रकाशित भी करनेवाला हूँ, सारे अफसरों को भेजने वाला हूँ, इन सड़कों के अन्दर कोई खराबी अगर दिखायी पड़ती है, आम आदमी भी इसकी शिकायत करके उन सड़कों को ठीक कराने का काम कर सकता है । महोदय, हम तो इतनी दूर तक गये हैं । महोदय, मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार पहला राज्य है, जिसने इस प्रकार की व्यवस्था सड़कों के मेन्टेनेंस के बारे में लागू किया है, देश के किसी राज्य ने इस प्रकार की व्यवस्था कहीं नहीं की है । मुझे यह भी प्रसन्नता है, कई राज्य कोशिश कर रहे हैं, कांटैक्ट भी कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि क्या चीज है यह । महोदय, इसलिये मैं जरूर आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, विरोध तो अपना होता ही रहेगा, जब दो दल की सरकार होती है, अलग-अलग पार्टियाँ हैं, अलग-अलग पार्टियाँ चुनाव में जाती हैं, एक-दूसरे का विरोध करती हैं, स्वाभाविक है

कि होगा लेकिन सच को छुपाकर विरोध करने की बात को जनता स्वीकार नहीं करती है । इसका जरूर ध्यान रखना चाहिये ।

महोदय, मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूँ, एक बड़ी उपलब्धि हमें मिली है, हममें से कई माननीय सदस्य जब प्रश्न करते हैं या फिर संकल्प देते हैं तो आप देखते हैं, आर0ओ0बी0 की चर्चा करते हैं कि हमारे यहाँ आर0ओ0बी0 नहीं बना । महोदय, आर0ओ0बी0 बनाने का पहले जो नियम था, आप जानते हैं, रेलवे रेलवे के पार्ट का काम करता था और पथ निर्माण विभाग उसका एप्रोच बनाने का काम करता था । कितनी विडम्बना थी अवधेश बाबू, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं पहली बार 2005 में पथ निर्माण विभाग का मंत्री बना तो सबसे पहले मुझे आरा के एक आर0ओ0बी0 का ध्यान आया । लोगों ने कहा, विधायक ने कोई क्वेश्चन किया, 1984 में उस आर0ओ0बी0 के रेलवे का पार्ट बनकर तैयार था लेकिन उस समय उसका एप्रोच बिहार की सरकार ने नहीं बनाया तो टँगा हुआ था, बाद में हमने बना दिया और उसका उद्घाटन कर दिया, वह अलग बात है । मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, महोदय, हो क्या रहा था ? रेलवे को अपने पार्ट का काम करना था, रोड को अपने पार्ट का काम करना था, कभी रेलवे सुस्त हो जाय, कभी रोड सुस्त हो जाय । महोदय, समय पर बनता नहीं था, तो बीच के कालखंड में एक व्यवस्था बनी, इरकॉन एक एजेन्सी से त्रिपक्षीय समझौता हुआ रेलवे के साथ, हमलोगों की सरकार में हुआ, महोदय । इरकॉन को रेलवे अपना पैसा देता था, हम भी अपना पैसा इरकॉन को दे देते थे ताकि मेरे एप्रोच का काम भी तुम ही कर दो । जब एक एजेन्सी होती थी तो काम थोड़ा बढ़ती थी लेकिन बीच के कालखंड में रेलवे ने इरकॉन को काम देना बंद कर दिया । फिर से वह पुरानी व्यवस्था लागू हो गई, रेलवे अपना काम करेगा, रोड अपना काम करेगा । महोदय, इसके लिए हमलोगों ने पहल किया, भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री से, मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस बार किसी आदमी ने डबल इंजन का नाम ही नहीं लिया, पता नहीं इनलोगों को स्वीकार हो गया कि डबल इंजन है, इसलिये अच्छा किया कि नहीं लिया । नहीं लिया तो अच्छा किया । महोदय, मैंने रेल मंत्री महोदय से इस संबंध में बातचीत किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात कराया और महोदय, इस बात पर सहमति बन गई, यह हमारी उपलब्धि है, यह बिहार की उपलब्धि है । बिहार के पथ निर्माण विभाग के काम करने के बेहतर तौर-तरीके का परिणाम है यह कि रेलवे विभाग ने कह दिया कि अब किसी और की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा काम हम बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग को देते हैं, हम अपना पैसा भी उसको देंगे और आप भी अपना पैसा दीजिये, नोडल एजेन्सी के रूप में पथ निर्माण विभाग काम करेगा । महोदय, यह उपलब्धि पूरे बिहार की है । मैं आपको

बताना चाहता हूँ, 53 आर0ओ0बी0 ऐसा है जो इस समझौते के तहत बनाया जाने वाला है । मैंने पुल निर्माण निगम और रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को इस बात का काम दिया है जो स्टेट हाईवे है, उस पर आर0ओ0बी0 बनाने का काम रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करेगा और जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है या दूसरी सड़कें हैं, उनपर आर0ओ0बी0 बनाने का काम पुल निर्माण निगम के द्वारा किया जायेगा । महोदय, मुझे आपको बताते हुये प्रसन्नता हो रही है, हमने तय किया है, समय-सीमा में चीजों को बॉधने का काम किया है, हमने कहा है कि हम दो साल में इस काम को पूरा करना चाहते हैं । छः महीने के अन्दर सर्वे और डी0पी0आर0 जमा हो जाना चाहिये और मुझे आपको बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि अभी तक 31 अदद रेलवे उपरी पुल का, आर0ओ0बी0 का ड्राफ्ट जी0ए0डी0 तैयार करके हमलोगों ने संबंधित रेलवे के मंडलीय कार्यालय को सहमति हेतु भेज दिया है ताकि उस काम को हम समय-सीमा में पूरा कर सकें । महोदय, यह बिहार की बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में जाना जायेगा ।

महोदय, अभी हमारे एक मित्र चर्चा कर रहे थे.... (व्यवधान) वह तो स्वाभाविक है, इस्टीमेट बनेगा, बन रहा है, इस्टीमेट अब बनेगा न, यह पुल निर्माण निगम और रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनायेगा । महोदय, मेरे मित्र एल0डब्लू0ई0 की चर्चा कर रहे थे, एल0डब्लू0ई0 की सड़कों में काम नहीं हुआ, किसने कह दिया आपको । शायद अत्री मुनी जी कह रहे थे, जानकारी आपको देना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि महोदय, अगर मेरा किताब, वार्षिक कार्य योजना ठीक से पढ़ लेते तो मुझे भाषण देने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन औपचारिकता का निर्वहन करना है, महोदय। (व्यवधान)

बैठिये न । (व्यवधान) ऐसा नहीं, भाई है । अरे भाई, उसको आना ही है, उधर ही है तो क्यों डॉटते हो ? कोई बात नहीं है ।

महोदय, मैं जरूर आपको बताना चाहता हूँ, नक्सल प्रभावित इलाकों में केवल बंदूक के जोर से नहीं, विकास..... (व्यवधान)

अध्यक्ष : आपकी उनसे पहले से बात हो रखी है क्या ? जब वे खड़े होते हैं, बिना आसन की इजाजत से आप उनसे मुखातिब भी हो जाते हैं, पूरी बात सुन भी लेते हैं और तब प्रेम से कहते हैं कि बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री नन्दकिशोर यादव, मंत्री : भोला जी, आपके लिए नहीं कहेंगे । महोदय, खून पानी से गाढ़ा होता है, इसका भी तो विचार किया करिये ।

महोदय, मैं कह रहा था कि जो एल0डब्लू0ई0 है, नक्सल प्रभावित इलाकों में केवल बंदूक की जोर पर हम शांति नहीं करना चाहते हैं, हम विकास की धारा बहाकर उनको मुख्यधारा में लाना चाहते हैं और इसीलिये भारत सरकार ने योजना बनाई, उस योजना के तहत जो बैच-1 था 2017-18 का, उसमें 864.92 कि0मी0 और एक पुल पैकेज की स्वीकृति प्रदान की गई जिसमें 1229 करोड़ रू0 की राशि खर्च होनी थी । इस बैच-1 के अधिकांश पैकेज का काम प्रारंभ कर दिया गया है और जो 2018-19 का बैच-1 है, उसमें कुल 13 पथ पैकेज का 184 कि0मी0 और 40 पुल पैकेज जिसकी अनुमानित लागत 410 करोड़ रू0 है, इसकी भी स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान कर दी गई है । इन सभी पैकेज की निविदा हो गई है । प्रक्रियाधीन है । 2018-19 में भी बैच-1 में चार अन्य जिले भी शामिल हो गये हैं...

...क्रमशः...

टर्न-29/राजेश/12.7.19

श्री नंदकिशोर यादव, मंत्री : क्रमशः .. जिसमें कैमूर, रोहतास, जमुई, नवादा, इन जिलों में कुल 75 सड़कें 851.95 किलोमीटर, 100 वृहद पुल, 206 पुल-पुलिया के निर्माण की भी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसके डी0पी0आर0 बनाने की कार्रवाई चल रही है । महोदय, मैं इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि विकास की जो रफ्तार है, वह इतनी तेज है महोदय, जो इसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि रफ्तार इतनी तेज है, महोदय । आर0ब्लॉक दीघा का काम प्रारंभ हो गया, कितने दिन से कोशिश कर रहे थे हम, कोई एक दो दिन से थोड़े न कोशिश कर रहे थे हम, जब से हम पथ निर्माण मंत्री हुए तब से कोशिश कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री पता नहीं कितने रेल मंत्री से बात किये होंगे, कई रेल मंत्री बदल गये, उस कालखंड 10 सालों में, कितने रेल मंत्रियों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात किया होगा, समाधान नहीं निकला, समाधान तब निकला जब डबल इंजन लग गया और आपने देखा की आर0ब्लॉक दीघा का रेल लाईन पथ निर्माण विभाग को मिल भी गया और उसपर सड़क निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है, जिसका भी एहसास आप सभी को है, प्रसन्नता भी आपको है, आप में से कई लोगों के घर उसी में हैं, सबका घर उसी रोड पर आने वाला है, आपको प्रसन्नता भी है, आप जो बार-बार कहते हैं कि पटना में काम हो रहा है, महोदय, आर0ब्लॉक दीघा का सड़क जो बन रहा है, कई माननीय सदस्यों ने कहा कि पटना में काम हो रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि यह पटना, पटना के लोगों का नहीं है, यह केवल पटनिया लोगों का पटना नहीं है, यह पटना, इस राज्य की राजधानी

है और यह पूरे बिहार के लोगों का हक है, लाखों लोग रोज पटना आते हैं, उनकी सुविधा का ध्यान रखना भी हमारा दायित्व है महोदय, तो इसलिए आज पटना का विकास हो रहा है, तो यह केवल पटना का स्थायी निवासी के लिए नहीं हो रहा है बल्कि जिस इलाके में यह रोड बनने वाला है, वहाँ अधिकांश बने हुए मकान दूसरे जिले से आये लोगों का बन रहा है महोदय । तो महोदय, मैं कहना चाहता हूँ और इससे आगे बढ़कर कहना चाहता हूँ कि रेलवे के साथ जो समझौता हुआ है महोदय, विकास के कई आयाम उसमें जुड़ने वाले है महोदय, पटना साहिब स्टेशन से पटना घाट रेलवे लाईन को रेलवे ने देने की सहमति दे दी है और महोदय पटना में जो यह गंगा पथ बनने वाला है महोदय, तो उसका पटना घाट से कनेक्शन सीधे पटना साहिब स्टेशन होते हुए पटना बख्तियारपुर फोर लेन से होने वाला है, महोदय उसके साथ-साथ आप जानते हैं एन0एच0-30 के निर्माण में हमें बिहटा से दानापुर तक एलिवेटेड रोड बनाना था महोदय, उस रोड को बनाने के लिए हमें रेलवे का क्वार्टर चाहिए था महोदय, तो रेलवे ने उस क्वार्टर को देने की भी सहमति दे दी है और बदले में हमलोगों ने हार्डिंग पार्क की जमीन रेलवे को दी है ताकि पटना जंक्शन का भी विकास हो सके और सड़कों के निर्माण का भी विकास हो सके । महोदय, मैं कह रहा था आपसे कि राजधानी के विकास के बारे में लोग परेशान होते हैं, मैंने कहा है कि राजधानी हमारा नहीं है महोदय, यह सबका है और इसका विकास हमारी प्राथमिकता में रहा है, मैं आपको जानकारी जरुर देना चाहता हूँ कि मैंने किताब में जो सब बातें लिखी हैं, मैं उसको दोहरा नहीं रहा हूँ महोदय लेकिन मैं केवल एक बात ध्यान में लाना चाहता हूँ आपलोगों को कि बिहार के अंदर पहली बार 8 लेन सड़क का निर्माण का कार्य हो रहा है और अवधेश बाबू पहला 6 लेन पुल तो आप ही के जिले में बनाने का काम किया था हमलोगों ने और अब पटना के अंदर सगुना मोड़ से ले करके दानापुर स्टेशन तक 8 लेन सड़क का निर्माण कार्य पथ निर्माण विभाग कर रहा है और महोदय बस स्टैंड शिफ्ट होने वाला है बैरिया में और जब वहाँ शिफ्ट होगा, वहाँ की सड़क अभी टू लेन है, तो यह जो पहाड़ी मोड़ है वहाँ से मसौढ़ी तक उस सड़क को भी फोर लेन करने के लिए हमलोगों ने टेंडर कर दिया, वर्क एवार्ड कर दिया, निकट भविष्य में उसमें काम भी होने वाला है महोदय ताकि जो हमारे उत्तर बिहार के हमारे भाई आयेंगे यहाँ, तो कठिनाई नहीं हो महोदय, मैंने इसके बारे में भी चिंता की है..............(व्यवधान)

महोदय, नवार्ड के माध्यम से महोदय, नवार्ड का काम करते हैं महोदय, नवार्ड से पैसा लेकर काम करते हैं महोदय और अब तक 13 वर्षों में नवार्ड के सहयोग से 12 हजार 92 करोड़ रुपये उनसे लिया, 393 पथ और पुल पुलिया का क्रियान्वयन किया गया

और महोदय, मुझे बताते हुए यह प्रसन्नता हो रही है कि हमारे काम की दक्षता को देखते हुए नवार्ड ने हमें प्रशंसा दिया है महोदय, नवार्ड ने हमें कहा है, पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार को, 2018-19 के दौरान आधारभूत संरचना निधि के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार हेतु यह प्रशस्ती पत्र प्रदान किया जाता है, बिहार राज्य के समावेशी विकास में, उनके उत्कृष्ठ कार्य एवं स्मरणीय योगदान के लिए राष्ट्रीय बैंक नवार्ड सराहनीय कार्य के लिए उनकी सराहना करता है, महोदय सब तरफ सराहना मिल रहा है सिर्फ आपको छोड़कर ....(व्यवधान)

अब तो आप जाइयेगा । महोदय, मेरे पास समय समाप्त हो रहा है..............(व्यवधान)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, मुझे खुशी होती कि जितनी राशि थी या राशि है आपको, उसमें जितना काम किया है, ठीक है और आगे काम बढ़ता, मगर आप अपने कामों का जिक्र करते और जहॉं कामों में संकट हो रहा है, उसका जिक्र करते लेकिन शुरुआत जो, असल में राजनीति प्राणी है, तो इनको राजनीति कीड़ा काटते रहता है बार-बार और बिना कुछ लिये पचता नहीं है, तो हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, आप पर दो लाईन का गाना याद आ गया कि:

''गोरे रंग पे न इतना गुमान न कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जायेगा ।''

अरे भाई आप गया के बारे में बोलते, फिर आपका जो रोड सब फॅसा हुआ है, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें अगर हमलोगों का सहयोग चाहते हैं, वे बताते .... (व्यवधान)

अध्यक्ष: सिद्दिकी साहब, आप जो दो पंक्तियॉं पढ़े हैं .... (व्यवधान)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, आपको जवाब नहीं देना है ।

अध्यक्ष: उसके अगले पंक्ति में 'समॉ और परवाने' की बात है, वह तो आपकी हालत नहीं न है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: माननीय अध्यक्ष जी, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, उसको थोड़ा तापकर रखिये । आप मंत्री जी यह बताइये कि विभाग में पी0सी0 बढ़ गया या खत्म हो गया, इसपर आप नहीं बोले, इसलिए हमलोग सदन से बहिर्गमन करते हैं ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बर्हिगमन किये)

श्री नंदकिशोर यादव, मंत्री: महोदय, इनके पास जवाब नहीं है और न ही सुनने के लिए समय है । महोदय, समय की सीमा है, इसलिए मैं अंत में जरुर कहना चाहता हूॅं कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में हमलोगों ने 1236 किलोमीटर पथों का उन्नयन, सतहीकरण करने का काम को पूर्ण किया है और वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2485 पथों का उन्नयन,

सतही नवीकरण का काम को पूर्ण करने का हमारा लक्ष्य है । महोदय, 2006 से अब तक अन्य विभागों से कुल 664 नये पथों का अधिग्रहण पथ निर्माण विभाग द्वारा किया

गया है, जिनकी कुल लंबाई 5931.817 किलोमीटर है और महोदय यह जो अधिग्रहित पथ है, इसको चरणबद्ध तरीके से निधि की उपलब्धता के आधार पर इसके निर्माण का कार्य किया जा रहा है । वर्तमान में पथ निर्माण विभाग द्वारा अन्य विभागों का कुल 182 नये पथों का अधिग्रहण किया गया, जिसमें जो सदस्य कह रहे थे, वह सड़कें भी शामिल हैं महोदय और इसकी कुल लंबाई महोदय 1754 किलोमीटर है, इसमें पहले से कोई भी मरम्मत का काम नहीं किया गया है, चूंकि यह अभी हाल में अधिग्रहण हुआ है । विभाग ने तय किया है कि उन सभी 182 पथों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के कार्य योजना में शामिल करके आवश्यकतानुसार नवीकरण, सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य कराया जायेगा । महोदय, विभाग ने तय किया है, जो बहुत बड़ी बात होने वाली है । महोदय, मैं जरुर आपसे कहना चाहता हूँ कि पथ निर्माण विभाग, महोदय पी0एम0 पैकेज की चर्चा इस बार किसी ने नहीं की, चूंकि सबको मालूम है कि काम हो रहा है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन इतना जरुर कहना चाहता हूँ कि 10 योजनाएँ पूरी हो गयी है महोदय पी0एम0 पैकेज की और साथ-साथ 36 योजनाएँ चल रही हैं महोदय और बाकी सभी योजनाएँ केवल चार योजनाओं का डी0पी0आर0 बनने की प्रक्रिया में है महोदय, बाकी सभी योजनाएँ समय पर पूरी हो जायेंगी और 2020 तक सभी योजनाएँ प्रारंभ हो जाय बची हुई, यह हमारी कोशिश है। महोदय, मैं अंत में जरुर उनसे कहना चाहता हूँ, हलाँकि वे चले गये लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि:

''हजार बार गिरे, लाख आँधिया उठे,
वे फूल खिलकर रहेंगे, जो खिलने वाले हैं,
उनके रोकने से रुकने वाला नहीं है ।''

महोदय, अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए जरुर आपसे आग्रह करुंगा कि जो हमारा लिखित भाषण है, उसको प्रोसिडिंग का पार्ट बनाने का निदेश दिया जाय और अंत में दो शब्द कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करुंगा कि:

''मुश्किलें जरुर हैं, मगर ठहरा नहीं हूँ मैं,
मंजिल से जरा कह दो, अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं ।''

क्रमशः

टर्न-30/सत्येन्द्र/12-7-19

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री:(क्रमशः): मैंने कहा कि विकास का काम कभी समाप्त नहीं होगा । महोदय, सिंगल लेन को दो लेन बनाते हैं तो लोग कहते हैं टू लेन नहीं बनाओ, फोर लेन बनाओ इसलिए महोदय, चले गये कटौती प्रस्ताव पेश करने वाले, मैं जरूर उनसे कहना चाहता हूँ, कटौती प्रस्ताव वापस ले लेते तो ज्यादा अच्छा होता लेकिन बिना

वापस लिये हुए चले गये इसलिए चले गये महोदय कि वे साहस नहीं कर पा रहे थे इस विकास के रथ को देखने का, उनमें विकास के रथ के चकाचौंध को बर्दास्त करने की क्षमता नहीं थी इसलिए मैं महोदय, आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान मांग संख्या-41 के अधीन पथ निर्माण विभाग का 70,05,56,28,000/-(सत्तर अरब पांच करोड़ छप्पन लाख अट्ठाइस हजार)रू0 का अनुदान मांग स्वीकृति हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ । मेरा आग्रह है कि इस अनुदान मांग को पारित करने की कृपा करें, इसकी स्वीकृति देने की कृपा करें ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी जो लिखित वक्तव्य सदन पटल पर रखेंगे, वह उनके भाषण का अंश बनेगा और सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनेगा ।

(माननीय मंत्री का वक्तव्य-परिशिष्ट द्रष्टव्य)

अध्यक्षः क्या माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते है ?

(अनुपस्थित)

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

'इस शीर्षक की मांग 10/- रू0 से घटायी जाय ।'

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

'पथ निर्माण विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 70,05,56,28,000/-(सत्तर अरब पांच करोड़ छप्पन लाख अट्ठाइस हजार) रू0 से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 12 जुलाई, 2019 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 46 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय । वैसे भी मैंने माननीय मंत्री के वक्तव्य शुरू होने से पहले भी आपको स्मारित किया था और फिर से मैं दोहराता हूँ कि आप सभी सूचित हैं कि कल दिनांक 13 जुलाई 2019 को विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हॉल में राज्य में उत्पन्न

जलवायु परिवर्त्तन के कारण जो आपदाजनक स्थिति है, इस पर विमर्श होगा जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं । आप अवश्य भाग लें और अपने अनुभव और सुझावों को वहां रखें जिससे कि समाधान की दिशा में सरकार को पहल करने में मदद मिल सके।

इसी अनुरोध के साथ अब सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 15 जुलाई, 2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट

श्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार सरकार

श्री सुशील कुमार मोदी
उप मुख्यमंत्री, बिहार सरकार

श्री नन्द किशोर यादव
मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

श्री नन्द किशोर यादव

मंत्री, पथ निर्माण विभाग

का

सदन में

बजट भाषण

2019 - 2020

पथ निर्माण विभाग के अनुदान माँग पर
श्री नन्द किशोर यादव
माननीय मंत्री
पथ निर्माण विभाग
का
बजट भाषण वर्ष 2019-20

माननीय अध्यक्ष महोदय,

पथ निर्माण विभाग के वर्ष 2019–20 के अनुदान मांग प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करते हुए मुझे हर्ष एवं गौरव की अनुभूति हो रही है। वर्तमान एवं बदलते बिहार के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक एवं शैक्षणिक विकास में पथ निर्माण विभाग की भूमिका अग्रणी रही है। विभाग के द्वारा विगत वर्षों में राज्य के पथों एवं पुल–पुलिया निर्माण के संदर्भ में काफी सराहनीय कार्य किये गये हैं। अथक प्रयास का यह नतीजा है कि आज राज्य के किसी भी हिस्से से पाँच घंटे में राज्य की राजधानी पटना पहुँचने के लक्ष्य के हम करीब है।

इस लक्ष्य को पूरा करने के क्रम में विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न श्रेणी के पथों यथा राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ, वृहद् जिला पथ एवं अन्य विभागों से अधिग्रहित किये गये पथों का उन्नयन, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य विभिन्न चरणों में प्रगतिशील है। सरकार द्वारा इन पथों के निर्माण के साथ–साथ इनके बेहतर रख–रखाव हेतु महत्त्वाकांक्षी अनुरक्षण नीति से पथों का संधारण किया जा रहा है।

OPRMC

महोदय, पथों के दीर्घकालीन रख–रखाव हेतु पथ निर्माण विभाग द्वारा बिहार पथ आस्तियाँ अनुरक्षण नीति, 2013 लागू करते हुए नई संविदा प्रणाली विकसित की गयी है। इस प्रणाली के तहत वर्ष 2013 से 2018 तक प्रथम चरण में 2579 करोड़ की लागत से 9064 कि०मी० पथों का सफलतापूर्वक संधारण किया गया है। प्रथम चरण के अनुभवों के आधार पर उक्त नीति के दूसरे चरण (वर्ष 2019–2026) में कई नये प्रावधानों को शामिल किया गया है।

OPRMC का द्वितीय चरण

OPRMC के द्वितीय चरण में कुल 6655 करोड़ रुपये की लागत से 13064 कि०मी० पथों के 7 वर्षों तक संधारण कार्य करने हेतु निविदोपरान्त ~~11873~~ 12373 कि०मी० पथ का संधारण कार्य प्रारंभ किया गया है एवं शेष ~~1191~~ 691 कि०मी० का संधारण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने की प्रक्रिया में है।

OPRMC के पहले चरण के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभव के आधार पर दूसरे चरण के बिडिंग डॉक्युमेंट के प्रावधानों को समुन्नत किया गया है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को शीघ्र नजदीकी अस्पताल पहुँचाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये विभाग ने रोड सेफ्टी एम्बुलेंस का भी प्रावधान इस चरण में किया है।

दूसरे चरण में पथों के रख–रखाव हेतु सेवा स्तर के मानक मापदंड को उत्क्रमित कर और अधिक प्रभावी किया गया है। पथों को पॉटलेस एवं पैच रहित रखने के अतिरिक्त पथों की

राइडिंग गुणवत्ता कायम रखने की जिम्मेवारी संवेदक को दी गई है। राइडिंग गुणवत्ता की माप IRI (International Roughness Index) के मानक के अनुरूप रखने की जिम्मेदारी भी संबंधित संवेदकों पर निर्धारित की गई है।

इस चरण में पथों के गुणवत्तापूर्वक रख–रखाव सहित रोड सेफ्टी पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रत्येक पथ पर रोड मार्किंग, पेंटिंग कार्य एवं सड़क के किनारे अवस्थित वृक्षों की रंगाई कार्य करने की जवाबदेही संबंधित संवेदकों को दी गई है। क्रियान्वयन के दौरान मानक मापदंड में पायी गई कमी की स्थिति में संबंधित संवेदकों के विपत्र से कटौती के प्रावधान को सख्त किया गया है। पथों के राइडिंग क्वालिटी को उत्कृष्ट बनाये रखने के लिए प्रत्येक पथ में चार वर्ष के अन्तराल पर सतह नवीकरण का प्रावधान इस चरण में किया गया है। भविष्य में जिन नयी सड़कों का निर्माण पथ निर्माण विभाग द्वारा कराया जायेगा, उसका अनुरक्षण OPRMC के अधीन ही किया जायेगा।

OPRMC के द्वितीय चरण में अनुश्रवण की व्यवस्था को और भी सशक्त करते हुये Real time Video Monitoring System लागू किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत सभी पथों का, मुख्यालय स्थित नियंत्रण कक्ष से सतत् अनुश्रवण संभव हो सकेगा। यह पथों के अनुश्रवण के लिये पूर्व से चालू व्यवस्था यथा OPRMC Monitoring System, Road Maintenance Public Grievance Redressal System तथा Vehicle Tracking System के अतिरिक्त होगी।

पी०एम० पैकेज

महोदय, विभाग द्वारा राज्य उच्च पथों एवं वृहद जिला पथों के अतिरिक्त राष्ट्रीय उच्च पथों का निर्माण एवं अनुरक्षण भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय उच्च पथ के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के लिए घोषित पैकेज अन्तर्गत कुल 54700 (चौवन हजार सात सौ) करोड़ की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके अन्तर्गत कुल 75 योजनाएँ चिन्हित् हैं जिसमें 10 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 41 योजनाओं की निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य आवंटित किया जा चुका है। 24 योजनाएं स्वीकृति, निविदा या DPR की प्रक्रिया में है। उक्त सभी योजनाएं विभाग अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग अथवा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2019–20 के अंत तक सभी योजनाओं का कार्य प्रारंभ करने का लक्ष्य है एवं इससे आगामी वर्षों में राज्य की परिवहन व्यवस्था में आमूल परिवर्तन देखने को मिलेगा।

पी०एम० पैकेज के अधीन जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्य विगत दिनों में पूर्ण कराया गया है, उसमें भागलपुर बाईपास एवं छपरा–रेवाघाट पथ महत्त्वपूर्ण है। जिन महत्त्वपूर्ण पथों/पुलों का कार्य प्रारंभ हो चुका है, उनमें पटना – बक्सर 4 लेन, बख्तियारपुर – मोकामा 4 लेन, बिहारशरीफ – बरबीघा – मोकामा 2 लेन सहित गंगा नदी पर औंटा – सिमरिया 6 लेन पुल एवं महात्मा गांधी सेतु का जीर्णोद्धार कार्य आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त सिमरिया–खगड़िया 4 लेन पथ, छपरा – सीवान – गोपालगंज 2 लेन पेव्ड शोल्डर, मुंगेरघाट सेतु का पहुंच पथ, डेहरी – अकबरपुर 2 लेन पथ, गया – दाउदनगर –

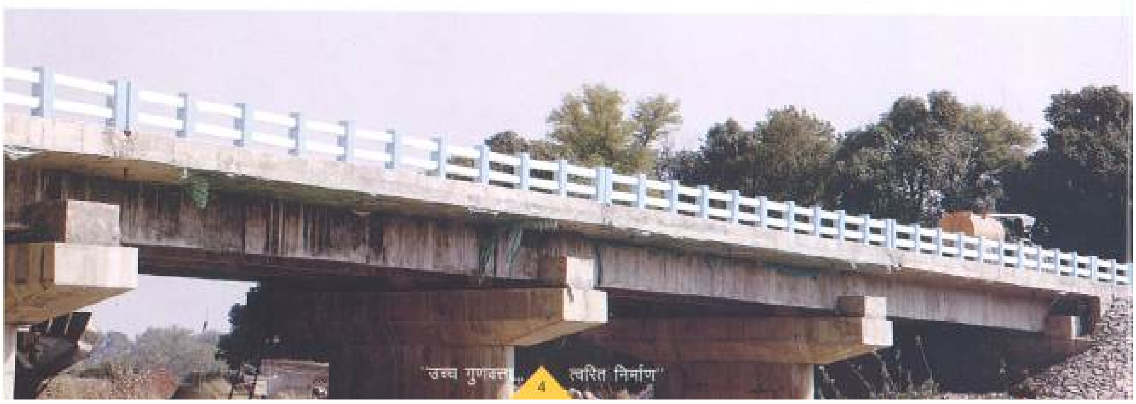

नासरीगंज – बिक्रमगंज 2 लेन पेभ्ड शोल्डर, सहरसा – पूर्णियां 2 लेन पेभ्ड शोल्डर एवं विश्व बैंक सहायता से निर्माणाधीन फतुहा – हरनौत – बाढ़ 2 लेन पथ का निर्माण कार्य शामिल है।

गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के समानान्तर नया 4 लेन सेतु का निर्माण, कोसी नदी पर फुलौत में 4 लेन पुल का निर्माण एवं मंझौली–चोरौत 2 लेन पेभ्ड शोल्डर पथ का निर्माण कार्य वर्ष 2019–20 में प्रारंभ करने का लक्ष्य है।

महोदय, भारत सरकार द्वारा राम जानकी मार्ग अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सीमा (मेहरौना) से सीवान होते हुये मशरख–सत्तरघाट–चकिया पथ का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है एवं भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार धार्मिक गलियारा अन्तर्गत उच्चैठ से महिषी पथ का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया गया है। इसके अन्तर्गत कोशी नदी पर भेजा – बकौर के बीच पुल निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की गई है।

इसके अतिरिक्त मुंगेर – मिर्जाचौकी पथ का 4 लेन निर्माण, विक्रमशीला सेतु के समानान्तर नये 4 लेन सेतु का निर्माण, बरबीघा–जमुई–बांका–पंजवारा 2 लेन पथ का निर्माण, भागलपुर– हंसडीहा 4 लेन पथ का निर्माण, बक्सर–चौसा–रामगढ़–मोहनियाँ 2 लेन पेभ्ड शोल्डर पथ, पटना रिंग रोड आदि कार्यों की स्वीकृति प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।

NH की अन्य परियोजनाएँ

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत माला योजना लागू की है। इसके अन्तर्गत औरंगाबाद से दरभंगा तक नये 4–लेन सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। औरंगाबाद से जहानाबाद होते हुए कच्ची दरगाह – बिदुपुर पुल पार करते हुए ताजपुर से दरभंगा तक इस पथ का निर्माण किया जायेगा। इस मार्गरेखन से दक्षिण एवं उत्तर बिहार के नये इलाकों में 4–लेन पथों का जाल बिछ सकेगा।

NHAI द्वारा रजौली – बख्तियारपुर पथ का रख–रखाव करते हुए इसका 4–लेन चौड़ीकरण किया जाना है। आरा–मोहनियाँ पथांश को NHAI द्वारा 4 लेन में विकसित करने हेतु डी०पी०आर० तैयार कराया जा रहा है।

पटना से वाराणसी के आवागमन को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा वाराणसी से बक्सर तक नया 4 लेन पथ निर्माण का मार्गरेखन तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया है।

महोदय, वैसे वाहन जिन्हें अपने गंतव्य तक जाने हेतु पटना आने की आवश्यकता नहीं है, को पटना के बाहर से ही थ्रू ट्रैफिक के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा पटना रिंग रोड के आरेखन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह रिंग रोड बिहटा में स्थापित हो रहे नये एयरपोर्ट के पास कन्हौली से प्रारंभ होकर डुमरी–लखना–बेलदारीचक–कच्ची दरगाह–चकसिकन्दर–एकारा–अस्तीपुर–दिघवारा–भोरपुर होते हुए पुनः कन्हौली में मिलेगी एवं इसी पथांश में दिघवारा–शेरपुर के बीच गंगा नदी पर पुल का निर्माण भी शामिल है।

महोदय, बिहटा में प्रस्तावित एयरपोर्ट को पटना से जोड़ने के लिए दानापुर – बिहटा पथ पर 4 लेन एलिवेटेड रोड के मार्गरेखन की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी जा चुकी है। रेलवे बोर्ड के द्वारा इस मार्गरेखन में आने वाले दानापुर स्टेशन के पास रेलवे भूमि के हस्तान्तरण पर सहमति प्रदान की गई है।

सड़क उपरि पुल (आर०ओ०बी०) का निर्माण कार्य

महोदय, राज्य सरकार द्वारा अभी तक राज्य सरकार, रेलवे तथा इरकॉन इन्टरनेशनल लि० के बीच वर्ष 2010 में त्रिपक्षीय समझौता के तहत कॉस्ट–शेयरिंग के आधार पर राज्य के अन्दर आर०ओ०बी० का निर्माण कराया जाता रहा है। पूर्व में चल रही इस व्यवस्था में प्रक्रियात्मक विलंब के निराकरण हेतु रेलवे के पदाधिकारियों के साथ विभिन्न बैठकों में इस आशय की सहमति बनी की राज्य सरकार के पथों पर आर०ओ०बी० के निर्माण के लिए राज्य सरकार तथा रेलवे के बीच MOU किया जाय। मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन के पश्चात् पथ निर्माण विभाग एवं रेलवे के बीच यह नया MOU सम्पन्न हुआ। इस MOU के हस्ताक्षर होने से राज्य सरकार (पथ निर्माण विभाग) Implementing Agency के रूप में कार्य करेगी तथा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड एवं बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से आर०ओ०बी० का निर्माण सम्पन्न करायेगी। उक्त MOU के अनुसार राज्य सरकार आर०ओ०बी० के पहुँच पथ के लिए भू–अर्जन की कार्रवाई करेगी एवं पहुँच

पथ सहित आर०ओ०बी० के निर्माण लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। पहुँच पथ सहित आर०ओ०बी० का पूर्ण निर्माण पथ निर्माण विभाग के निगमों (BRPNNL & BSRDCL) द्वारा कराया जाएगा। इस नीति के तहत कुल 53 लेवल क्रॉसिंग पर आर०ओ०बी० के निर्माण हेतु डी०पी०आर० गठन करने की कार्रवाई बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड एवं बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से की जा रही है।

वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क सम्पर्क योजना (RCPLWEA)

अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा RCPLWEA 2017-18 (Batch-I) के तहत् 52 पथ पैकेज (कुल लम्बाई–864.92 कि०मी०) एवं 1 पुल पैकेज (लम्बाई–148.8 मी०) की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति की राशि लगभग 1229 (बारह सौ उनतीस) करोड़ है। इस Batch-I के अधिकांश पैकेजों का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। RCPLWEA 2018-19 (Batch-I) में कुल 13 पथ पैकेज (कुल लम्बाई–184.928 कि०मी०) एवं 40 पुल पैकेज (लम्बाई–2727.31 मी०) की स्वीकृति (अनुमानित लागत 410 करोड़) भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। इन सभी पैकेजों की निविदा प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018–19 (Batch-II) में अन्य चार जिले यथा कैमूर, रोहतास, जमुई एवं नवादा में कुल 75 पथ (कुल लंबाई–851.95 कि०मी०), 10 वृहद पुल एवं 206 पुल/पुलियों की निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है एवं डी०पी०आर० प्रक्रियाधीन है।

सड़क सुरक्षा

महोदय, राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना के रोकथाम के लिए 2500 कि०मी० राज्य उच्च पथों का केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा सड़क सुरक्षा अंकेक्षण (ROAD SAFETY AUDIT) का कार्य किया जा रहा है, जिसमें अबतक 1100 कि०मी० का सड़क सुरक्षा अंकेक्षण का कार्य कर लिया गया है। सड़क सुरक्षा अंकेक्षण के सुझाव / मंतव्य का अनुपालन किया जा रहा है।

बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों / पुलों का तत्काल पुनर्स्थापन :-

अध्यक्ष महोदय, बाढ़ पूर्व तैयारियों हेतु विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैं एवं विभाग में बाढ़ प्रबंधन कोषांग 25 जून से 30 सितम्बर तक प्रतिदिन कार्यरत रहता है। OPRMC एवं CMBD के संविदा में बाढ़ के समय आपातकालीन कार्य हेतु प्रावधान है, जिसके तहत गत वर्षों में 7 दिनों के अन्दर क्षतिग्रस्त पथों में यातायात सुगम करा लिया गया है।

महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अत्यावश्यक / आकस्मिक कार्यों को विभागीय रूप से कराने हेतु निर्णय लिया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में अविलम्ब यातायात सुगम बनाया जा सके।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड

अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने पिछले 14 वर्षो (वर्ष 2005 से अब तक) में लगभग 15700 (पंद्रह हजार सात सौ) करोड़ की लागत से कुल 2170 परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया है तथा 232 योजनाओं का कार्य प्रगति में है।

राज्य में बाढ़ के कारण पथों के कटाव एवं पुलों के क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में आवागमन बाधित हो जाता है। ऐसे मामलों में कम से कम समय में आवागमन चालू करने के लिए बेली ब्रिज का प्रावधान रखा गया है। इसके अन्तर्गत कुल 8.00 करोड़ की लागत पर 1000 मी० लम्बाई का बेली ब्रिज क्रय कर सहरसा एवं कटिहार में रखा गया है। इसके तहत ही अररिया में NH-327E के कि०मी० 87 में 40 मी० लम्बा बेली ब्रिज का निर्माण किया गया है।

पिछले एक वर्ष में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा 3 मेगा पुल यथा सोन नदी पर दाउदनगर – नासरीगंज पुल, बरियारपुर आर०ओ०बी० तथा कमला नदी पर पुल सहित गंडौल–बिरौल पथ का निर्माण पूर्ण किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में गंडक नदी पर सत्तरघाट एवं बंगराघाट पर पुल कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है तथा 46.77 करोड़ की लागत से पुनपुन नदी पर पुनपुन में लक्ष्मण झूला के तर्ज पर केबल सस्पेंशन ब्रिज का शिलान्यास किया गया है। इसे अगले डेढ़ वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। छपरा में 411 (चार सौ ग्यारह) करोड़ की लागत से 3.5 कि०मी० लम्बे, भारत का सबसे लम्बा डबल डेकर फ्लाई ओभर का निर्माण प्रारंभ किया गया है।

राज्य की प्रमुख नदियों पर पुल निर्माण की महत्त्वाकांक्षी योजनाओं को मानक गुणवत्ता के साथ ससमय पूर्ण करने में इस निगम का योगदान उल्लेखनीय रहा है। राज्य सरकार बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की क्षमतावर्द्धन हेतु कृत संकल्पित है।

बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड

महोदय, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड द्वारा राज्य के राज्य उच्च पथ सहित राज्य सरकार की कई महत्त्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। निगम द्वारा अबतक लगभग 10 वर्षों की अवधि में लगभग 10,548 (दस हजार पाँच सौ अड़तालिस) करोड़ की लागत से अबतक लगभग 1387 कि०मी० पथों का निर्माण गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया है एवं 462 कि०मी० पथों सहित कई मेगा परियोजनाओं का निर्माण प्रगति पर है।

वर्ष 2019–20 में 5 महत्त्वपूर्ण राज्य उच्च पथों यथा SH-82 (कादिरगंज–सोन्हो), SH-84 (घोघा–पंजवारा), SH-102 (बिहियाँ–बिहटा), SH-58 (किशनगंज–विजयघाट) एवं SH-85 (अकबरनगर–अमरपुर) जिसकी कुल लम्बाई लगभग 232 कि०मी० है, में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है एवं इसे निर्धारित समय सीमा 27 महीने में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

इसके अतिरिक्त SH-80 (भभुआ–अधौरा), SH-105 (बेतिया–नरकटियागंज), SH-95 (मानसी – चौघड़ा) का मानसी–फानगो हाल्ट खंड, SH-98 (कटिहार–बलरामपुर) एवं SH-99 (वायसी–बहादुरगंज) पथ के स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। इसकी निविदा प्रक्रिया इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर कार्य प्रारंभ करने का लक्ष्य है।

पटना राजधानी क्षेत्र के आधारभूत ढ़ांचे का सुदृढ़ीकरण

पटना राजधानी क्षेत्र की वर्ष 2031 तक की यातायात की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधारभूत ढ़ाँचे का विकास किया जा रहा है। प्रमुख परियोजनाएँ जिस पर कार्य किया जा रहा है, वे निम्नवत् हैं–

1. **गंगा पथ :**

   दीघा से अशोक राजपथ के समानान्तर पटना शहर के विभिन्न स्थानों को सम्पर्कता प्रदान करते हुए दीदारगंज तक कुल 20.5 कि०मी० लम्बा 4 लेन गंगा पथ का निर्माण प्रगति पर है। यह दीघा में जे०पी० सेतु, एलिवेटेड कोरीडोर एवं आर० ब्लॉक – दीघा एवं दीदारगंज में एन०एच०–30 एवं कच्ची दरगाह – बिदुपुर पुल को सम्पर्कता प्रदान करेगा। दीघा से ए०एन० सिन्हा इन्स्टीच्यूट एवं पी०एम०सी०एच० तक जून 2020 तक सम्पर्कता प्रदान करने का लक्ष्य है।

2. **दीघा-एम्स एलिवेटेड रोड :**

   सरकार द्वारा जे०पी० सेतु के दक्षिणी भाग से 12.27 कि०मी० लंबाई का 4–लेन एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है। अगस्त, 2019 तक एलिवेटेड कोरीडोर के एक Carriageway एवं नवम्बर, 2019 तक दोनों कैरेज–वे पर वाहनों का आवागमन चालू करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त इस पथ के समानांतर पटना नहर के तटबंध पर अलग से 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा चुकी है जो दीघा को एम्स से सम्पर्कता प्रदान कर रही है। इससे महात्मा गांधी सेतु पर द हनों का दबाव कम हुआ है।

3. महात्मा गांधी सेतु का जीर्णोद्धार :

महात्मा गांधी सेतु के जीर्णोद्धार के लिए लगभग 1300 करोड़ रू० की योजना का कार्य तेजी से चल रहा है। दिसम्बर, 2019 तक पश्चिमी 2 लेन का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण हो जाएगा एवं दिसम्बर, 2020 तक पूर्वी 2 लेन का निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।

4. बिहटा में प्रस्तावित एयरपोर्ट को राजधानी से जोड़ने के लिए दानापुर–बिहटा पथ पर एलिवेटेड रोड बनाये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। सगुना मोड़ से दानापुर स्टेशन पथ का 8–लेन चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है।

5. एस०एच०-1 का 4-लेन चौड़ीकरण :

पहाड़ी जीरोमाईल से मसौढ़ी तक सादीकपुर–पभेढ़ा–मसौढ़ी पथ का 4–लेन चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

6. आर ब्लॉक-दीघा पथ :

पटना शहर के अन्तर्गत ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने में इस परियोजना की भूमिका भी अहम होगी। 380 (तीन सौ अस्सी) करोड़ रुपये की इस परियोजना का कार्य प्रगति पर है एवं इसे पूर्ण करने की अवधि 18 माह निर्धारित है। इसके निर्माण से बोरिंग रोड एवं जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर यातायात का दबाव कम होगा। साथ ही कृष्णापुरी, पुनाईचक, शिवपुरी, महेशनगर, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, राजीव नगर एवं दीघा

को सीधी सम्पर्कता प्राप्त हो जायेगी। इस परियोजना को Green Project के रूप में विकसित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत Green Corridor Development, Solar Street Lighting, Rain Water Harvesting आदि का कार्य समावेशित किया गया है।

आर ब्लॉक–दीघा पथ (फेज–2) के तहत इस पथ को गंगा पथ, J.P सेतु एवं AIIMS- Digha Elevated Corridor से जोड़े जाने की भी योजना है।

नदियों पर पुलों का जाल

महोदय, सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से राज्य की प्रमुख नदियों पर पुलों का जाल स्थापित किया गया है।

उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार को बेहतर सम्पर्कता प्रदान करने के लिए वर्ष 2005 से पहले गंगा नदी पर मात्र बक्सर, पटना, मोकामा एवं भागलपुर में कुल चार पुल थे, वहीं आज इनके अतिरिक्त आरा–छपरा सेतु, जे०पी०सेतु बनकर तैयार हो गये हैं। महात्मा गाँधी सेतु का जीर्णोद्वार, कच्ची दरगाह–बिदुपुर 6 लेन पुल, बख्तियारपुर–ताजपुर पुल, मुंगेर पुल, बक्सर पुल के समानान्तर सेतु, राजेन्द्र सेतु के समानान्तर सेतु एवं अगुवानीघाट पुल पर कार्य चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त जे०पी० सेतु के समानान्तर सेतु, महात्मा गाँधी सेतु के समानान्तर सेतु एवं विक्रमशीला सेतु के समानान्तर सेतु बनाने का निर्णय लिया गया है।

इसी प्रकार गंडक नदी पर अब धनहा–रतवल घाट एवं गोपालगंज–बेतिया पुल बनकर तैयार है तथा सत्तरघाट एवं बंगरा घाट का कार्य चल रहा है। कोशी नदी पर कोशी

महासेतु, बलुआहा घाट, विजय घाट बनकर तैयार है एवं डुमरी घाट पुल का जीर्णोद्वार कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त भेजा घाट एवं फुलौत घाट पर नये पुल बनाना प्रस्तावित है। सोन नदी पर अरवल–सहार पुल एवं दाउदनगर–नासरीगंज पुल चालू है। कोईलवर पुल के समानान्तर नये 6 लेन पुल का कार्य प्रगति में है। इसके अतिरिक्त पंडुका पुल का निर्माण कराने का प्रस्ताव है। बागमती नदी पर पिपराही, बैरगनियाँ, कटौंझा, डुब्बा घाट, माड़र घाट, फुलतौड़ा घाट एवं सोनमनखी घाट पुल चालू है। फल्गु नदी पर मानपुर 6 लेन पुल, कंडी (गया), वंशी बिगहा एवं हुलासगंज पुल बनकर तैयार है जबकि एन०एच०–82 पर घुघड़ीटाँड़ एवं श्रीपुर–केनी में पुल निर्माणाधीन है।

बिहार राज्य सड़क अनुसंधान संस्थान

महोदय, राज्य सरकार द्वारा सड़कों एवं पुलों के निर्माण में नवीनतम तकनीक एवं इससे संबंधित अनुसंधान हेतु बिहार राज्य सड़क अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में देश की अग्रणी संस्था केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान परिषद् को मेन्टर नियुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इस संस्थान के बन जाने से जहाँ विश्व स्तर पर हो रहे तकनीकी अनुसंधान से अभियंता, संवेदक अवगत होंगे वहीं दूसरी ओर इससे अभियंताओं को नये प्रयोग करने के अवसर मिलेंगे।

क्षमता विकास

महोदय, विभाग में अभियंताओं की रिक्तियों को भरने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियंताओं के नियुक्ति हेतु प्रारंभिक परीक्षा के उपरान्त मुख्य परीक्षा भी सम्पन्न करा ली गई है। नियुक्ति प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब को देखते हुए तत्काल विभाग द्वारा 200 सहायक अभियंताओं को संविदा पर नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त विभाग में 118 नियमित कनीय अभियंताओं की नियुक्ति की गई है।

पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत कुल 117 अभियंताओं का अतिरिक्त पद सृजित किया गया है।

विभिन्न परियोजनाओं को सुचारू रूप से संचालन एवं प्रबंधन हेतु विशेषज्ञ आधारित परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) के गठन का निर्णय लिया गया है एवं नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से अब मैं वित्तीय वर्ष–2019–20 के लिए अनुदान माँग संख्या–41 के अधीन पथ निर्माण विभाग का 70 अरब 05 करोड़ 56 लाख 28 हजार रूपये का अनुदान माँग स्वीकृति हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।